अप्रैल-मई, 2024

लोकतांत्रिक संस्थाओं से नाखुश हैं दुनिया के ज्यादातर मतदाता

40 रुपये

जन चुनौती

बेहतर कल के लिए...

लोकसभा चुनाव

दिलचस्प हुई जंग चौंका सकते हैं नतीजे

- **लोकतंत्र और राजशाही :** चुनावी राजनीति में अब भी कायम है राज परिवारों का जलवा
- **अर्थनीति :** दावे और हकीकत से मेल नहीं खाती अर्थव्यवस्था की तस्वीर

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

राजकमल प्रकाशन समूह

कोरोनाकाल का आख्यान पेश करती तीन किताबें

Contact Us

Head Office (Rajkamal Prakashan Pvt. Ltd, New Delhi)
Address: 1-B, Netaji Subhash Marg, Daryaganj, New Delhi - 110002 (India)
Phone: 011-23274463/23288769
Fax: 011-23278144
Email: info@rajkamalprakashan.com
Website: www.rajkamalprakashan.com

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

जन चुनौती

(हिंदी मासिक)

अप्रैल-मई, 2024
वर्ष-4, अंक-4-5

संपादक
राजकेश्वर सिंह

संपादकीय सलाहकार
नीलमणि लाल

कोलकाता ब्यूरो
विनय बिहारी सिंह

फोटोग्राफर
आर.बी. यादव

डिजाइन लेआउट
बीएल मौर्य

कवर पेज व इलस्ट्रेशन
राजीव तिवारी

महाप्रबंधक (आपरेशंस)
श्रीश सिनहा

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक राजकेश्वर सिंह द्वारा ग्रैंड प्रिंटिंग प्रेस, 337 विजईपुर, विशेष खंड, गोमतीनगर, लखनऊ से मुद्रित व 3/160 विराज खंड, गोमतीनगर, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित

RNI No. UPHIN/2021/79675

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

email : janchunautinews@gmail.com
टेलीफोन : 0522-3568329
मोबाइल : +91-9369918163

भीतर के पन्नों पर

कवर स्टोरी

उत्तर प्रदेश 15
बदली तस्वीर, ज्यादातर सीटों पर रोचक हुआ मुकाबला

बिहार 19
नीतीश को साथ लेकर भी घाटे में ही रह सकता है राजग

महाराष्ट्र 22
बदले समीकरण से दिग्गजों के सामने वजूद बचाने की चुनौती

पश्चिम बंगाल 25
तृणमूल व भाजपा में है कांटे की टक्कर वामदल व कांग्रेस हाशिए पर

राजस्थान 28
खोना तो भाजपा को ही है और पाना कांग्रेस को

पड़ोस 30
भारत के लिए मुश्किलें पैदा करने से पीछे नहीं हट रहा चीन

स्पोर्ट्स 42
राजनीति में भी कम जलवा नहीं रहा है खिलाड़ियों का

सिनेमा 51
चुनाव : रील लाइफ सितारों का रीयल इम्तिहान

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

संपादकीय

बहस के लिए मुद्दे और भी हैं

अगले पांच सालों के लिए देश के लगभग 140 करोड़ लोगों की तकदीर की नई इबारत लिखने की जमीन तैयार करने वाला लोकसभा चुनाव सामने है। इस चुनाव के दौरान ही आई एक रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि बीते अप्रैल में देश के 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के बीच बेरोजगारी दर बढ़कर 8.1 फीसद हो गई है और उसकी सबसे ज्यादा मार ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ी है। अप्रैल से पहले मार्च में वह बेरोजगारी दर 7.4 फीसद थी। सेंटर फॉर मानीटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे में यह भी दावा किया गया है कि बीते महीने ही 47 लाख लोगों का रोजगार छिन गया और उनमें भी लगभग 90 फीसद लोग गावों में रहने वाले हैं। जाहिर है कि बेरोजगारी की यह स्थिति तो देश के लिए अच्छी तस्वीर कतई नहीं पेश करती, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस पर या इस जैसे दूसरे मुद्दों पर कोई भी राजनीतिक दल बात तक नहीं कर रहा है। उसमें भी सत्तारूढ़ दल तो बिलकुल नहीं, जबकि होना तो यह चाहिए था कि वह अगले पांच साल के अपने कामकाज के रोडमैप के साथ ही अपने बीते दस साल का भी लेखा-जोखा जनता के सामने रखकर उसे बहस के केंद्र में लाता। वह अपनी इस ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़े हुए है। देश के युवाओं से जुड़े इस मुद्दे के साथ ही जनता से जुड़े दूसरे और जरूरी मसलों को भी इस चुनाव में बहस के एजेंडे में लाने का यह काम विपक्ष का भी है या फिर यह कहें कि इस मामले में उसकी भूमिका ज्यादा प्रभावी होनी चाहिए थी, लेकिन वह भी उसमें एक तरह से असफल है। हालांकि उसकी अलग-अलग कई वजहें हैं। अब तक लोकसभा के दो चरण का चुनाव निपट चुका है। याद करिए, पहले चरण के चुनाव के पूर्व सत्तारूढ़ भाजपा 'अबकी बार-चार सौ पार' का नारा देते हुए विकसित भारत की बात बड़ी प्रमुखता से उठा रही थी, लेकिन मुख्य विपक्षी कांग्रेस का घोषणा पत्र आने और पहले चरण के चुनाव के बाद से उसने बहस का सारा विमर्श ही बदल दिया। भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से ही नहीं जोड़ा, बल्कि उसने उसके बाद हिंदू-मुसलमान, घुसपैठियों, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों और पाकिस्तान तक को इस चुनाव में खुलकर मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। चुनाव और आगे बढ़ा तो उसने कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्ष की सरकार आने पर महिलाओं का मंगल सूत्र और लोगों की संपत्ति छिन जाने तक को बहस के केंद्र में ला दिया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि देश में जब एक से बढ़कर एक चुनौतीपूर्ण मुद्दे हैं, तब इस चुनाव में भाजपा इसे भी मुद्दा बनाएगी कि यदि विपक्षी दल सत्ता में आए तो उनकी सरकार लोगों की दो भैंसों में से एक भैंस तक ले लेगी। चुनावी बहस के मुद्दे यहीं नहीं रुके हैं, बल्कि चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, उसमें नये-नये शब्द और विशेषण जुड़ते जा रहे हैं, जिनका आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाने और बेहतरी से कोई संबंध नहीं है। मसलन- बात अब शहजादे और शहंशाह पर भी हो रही है। धर्म का भी सहारा लिया जा रहा है। चुनाव के दौरान सोशल मीडिया में ऐसी भी तस्वीरें दिखीं, जहां मतदान केंद्र के बाहर धर्म विशेष के महापुरुषों के पोस्टर भी लगे थे। कहना गलत नहीं होगा कि हमारा चुनाव आयोग जिस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात करता है, कई बार वह जमीन पर वैसा दिखता नहीं है। आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले अक्सर मीडिया में सुखियां बनते हैं और फिर बात आई-गई होकर रह जाती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती, जबकि हर पांच साल पर होने वाले चुनाव का यह ऐसा पर्व है, जिसमें जाति, धर्म, संप्रदाय से अलग उन सभी मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए जिससे देश के सभी नागरिकों को अपना बेहतर प्रतिनिधि चुनने के लिए निर्णय लेने में ज्यादा आसानी हो।

लोकसभा चुनाव के अभी कुछ चरण बाकी हैं, लेकिन उसमें भाग लेने वाले राजनीतिक दल, खासतौर से मौजूदा सत्तापक्ष जिस ढर्रे पर जाता दिख रहा है, उसके संकेत साफ हैं कि इस चुनाव में आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी और उसके विकास के लिए बुनियादी बदलाव लाने वाले एजेंडों पर बहस होने नहीं जा रही है। विपक्षी दल अलबत्ता, सत्तारुढ़ दल को कई बार जरूरी मसलों पर अपनी पिच पर लाने की कोशिश करते दिखते हैं, लेकिन ज्यादातर वे उसमें असफल ही रहते हैं। ऐसे में यह सवाल ज्यादा अहम हो जाता है कि क्या इस बार का भी आम चुनाव जनता के बुनियादी मुद्दों पर बहस के बगैर ही निपट जाएगा। क्या लोकसभा चुनाव के बचे बाकी चरण भी हिंदू-मुस्लिम, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों, पाकिस्तान, घुसपैठियों, भैंस, धर्म और जाति, अगड़ों और पिछड़ों की बहस तक सिमट जाएंगे और यदि ऐसा होता है तो उससे लोगों के बेहतर भविष्य की जमीन तैयार होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। देश, समाज और जनता के हित में यही है कि चुनाव के इस मौके पर बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार, किसानों की आमदनी बढ़ाने, दलितों-पिछड़ों को विकास की मुख्यधारा में लाने जैसे मसलों को चुनावी बहस के केंद्र में लाया जाए और जो राजनीतिक दल इससे कन्नी काट रहे हैं, मतदाता मतदान के पहले उन पर एक बार विचार जरूर करें।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

चुनावी राजनीति में अब भी कायम है राज परिवारों का जलवा

अरविंद कुमार सिंह, नई दिल्ली।

देश आज़ाद होने और लोकतंत्र स्थापित होने के साथ ही राजशाही तो चली गई, लेकिन चुनावी राजनीति में पुराने राजाओं, महाराजाओं, नवाबों और जागीरदारों के परिवारों का दबदबा शुरू से ही कायम रहा है। हालांकि आजादी के बाद से अब तक कई राजा-रानी कहानियों का हिस्सा बन चुके हैं। कई किले और महल खंडहर बन गए, लेकिन कई इलाकों में उनका आभामंडल अब भी कायम है। राजनीतिक शक्तियों के सहारे उनकी चमक-दमक और तेज हुई है, इसीलिए राजनीतिक दल राजाओं-महाराजाओं, नवाबों और जागीरदार परिवारों के सदस्यों को जीत की गारंटी मान कर पहले भी टिकट देते रहे हैं और अब भी दे रहे हैं। लोकसभा के 2024 के चुनाव और उसके साथ ही कुछ राज्यों के विधान सभा चुनावों में भी कई राज परिवार के सदस्य अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके पहले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी राजा-रानियों के परिवारों के सदस्यों के बीच खूब टिकट बंटे थे और राज परिवारों पर सबसे अधिक दांव भाजपा ने लगाया था।

लोकसभा चुनाव में राजाओं के गढ़ राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और पंजाब से लेकर त्रिपुरा तक कई पूर्व राजघरानों के उम्मीदवार मैदान में हैं। महलों से निकलकर राजाओं के परिजन वोटरों को रिझाने के लिए तमाम कलाबाजियां कर रहे हैं। पसीने बहा रहे हैं। कई निर्वाचन क्षेत्रों में तो ऐसा लगता है जैसे मतदाताओं की पीढ़ियां राजाओं-महाराजाओं को वोट देकर अभी भी थकी नहीं है। हालांकि कई राज परिवारों ने अपने इलाकों के बदले राजनीतिक समीकरणों को भांप कर राजनीति से दूरी भी बनायी है और खुद को महलों तक सीमित कर लिया है। उनमें से कुछ पांच सितारा होटल कारोबार या कुछ दूसरे कामों में लग गए हैं। उनके पास अभी भी बेशुमार संपत्तियां हैं, पर झगड़े और मुकदमों की विरासत भी है। उन संपत्तियों को सहेजने के लिए वे सांसद या विधायक न भी बनें तो भी सरकारी संरक्षण तलाश ही लेते हैं।

संसदीय इतिहास और राजे-महाराजे

भारत में 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी राज में पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत इंपीरियल विधान परिषद में गैर-सरकारी भागीदारी के तहत 1862 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, काशीराज देव नारायण सिंह और ग्वालियर के महाराजा सर दिनकर राव रघुनाथ को विधान परिषद में नियुक्त किया था। बाद में 1862 से 1892 के बीच 45 भारतीयों को परिषदों में मनोनीत किया गया, जिनमें अधिकतर राज परिवारों के लोग थे या फिर जमींदार। उसमें भी काशीराज, पटियाला महाराज, रामपुर के नवाब यूसुफ अली खान, विजयनगरम के महाराज, बर्दवान के राजा, जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय, बलरामपुर के राजा दिग्विजय सिंह, कपूरथला के प्रताप सिंह, महमूदाबाद के राजा सर मोहम्मद अली मोहम्मद खान और कुर्री सुदौली के राजा सर रामपाल सिंह को स्थान मिला था। उस परिषद में अधिक शक्तियां तो नहीं थीं, लेकिन वह बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल था। बाद में परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ी तो भी राजाओं का महत्व उसमें बना ही रहा। उसके बाद बनी विधान परिषदों में जब निर्वाचित सदस्यों का प्रवेश आरंभ हुआ तो कई राजा चुनाव लड़कर भी परिषद में पहुंचे। उत्तर प्रदेश में राजाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का सिलसिला 1930 के दशक में आरंभ हुआ।

संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर मैल्कम हैली ने कांग्रेस के खिलाफ राजाओं को आगे किया और नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा तथा नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध भी उनकी ही पहल पर बनी, ताकि कांग्रेस की बढ़त को रोका जा सके। 1937 में उसके बैनर तले राजघरानों ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस की लोकप्रियता के आगे वे ठहरे नहीं। फिर भी अंग्रेजों ने गोविंद बल्लभ पंत सरकार से पहले संयुक्त प्रांत का अंतरिम मुख्यमंत्री नवाब

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

छतारी को बना दिया। फिर कई राजा 1937 और 1946 के प्रांतीय चुनावों में भी जीते।

उत्तर प्रदेश में राजाओं ने 1952 के चुनावों के दौरान प्रजा पार्टी बनायी और उस समय की 430 में से 60 विधानसभा और 6 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन केवल जगमनपुर (जालौन) और पयागपुर (बहराइच) के राजा ही चुनाव जीते। लोकसभा में सभी छह प्रत्याशी हारे, जिनमें से चार की जमानतें जब्त हो गयीं। चुनाव में कांग्रेस, समाजवादी और जनसंघ जैसे दल ही मुख्यधारा के दल बने। राजाओं ने एक राजनीतिक संगठन उड़ीसा में गणतंत्र परिषद के नाम से भी बनाया जिसने कांग्रेस के साथ मिल कर साझा सरकार भी बनायी थी।

राज-महाराजाओं ने सी. राजगोपालाचारी के नेतृत्व में स्वतंत्र पार्टी को असल में सबसे अधिक सहारा दिया और जयपुर की राजमाता गायत्री देवी के प्रयासों से देश भर के काफी राज परिवार उससे जुड़े। स्वतंत्र पार्टी ने 1962 में 18 सीटें हासिल कीं और उसके बैनर तले राजस्थान के तीन राजा जीते। उसने 1967 में 34 लोकसभा सीटों पर देश में जीत हासिल की, जिनमें से से 10 राजा महाराजा थे। उसका 1971 आखिरी चुनाव था जिनमें उसने आठ सीटें जीती, जिनमें से छह राजा थे। राजाओं के दबाव में ही जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी का समझौता भी हुआ, पर उसमें कुछ विरोध की आवाजें भी उठीं और जयपुर के महराज कुमार जय सिंह ने जनसंघ को मुसलमानों का गला काटने वाली पार्टी कहने के साथ विवाद को तूल दिया था, हालांकि बाद में इसके साथ वे भी उससे जुड़ गए।

राजाओं की जहां तक बात है, आजादी के आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी रिसायतों में कांग्रेस संगठन बनने नहीं दिया। वहां अखिल भारतीय प्रजा परिषद इकाइयां काम कर रही थीं, जिनका जुड़ाव कांग्रेस से था। बाद में उस संगठन का कांग्रेस में विलय भी हुआ। सरदार पटेल, पंडित नेहरू और पट्टाभि सीतारमैया के अलावा शेख अब्दुल्ला उस संगठन के अध्यक्ष रहे। उस नाते कांग्रेस नेता राजाओं की हकीकत जानते थे। उधर जब-जब राजाओं को लगा कि उनकी अपनी सत्ता विदा हो रही है तो उसे बचाने के लिए कई राजाओं ने दूसरे प्रयोग भी किए। उन्होंने हिंदू सभा, क्षत्रिय महासभा, जाट सभा, सनातन धर्म सम्मेलन, अंजुमन मुसलमीन जैसी संस्थाओं के विकास में मदद की। कई राजाओं ने जनसंघ, रामराज्य परिषद तथा हिंदू महासभा को भी खासी मदद की। पहले आम चुनाव में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कई राजाओं की हकीकत को भांप कर दिसंबर 1951 में जबलपुर में एक बड़ी सभा में कहा था कि, मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि देसी रियासतों के कई पूर्व राजा अपनी पुरानी स्थिति प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान का विरोध कर रहे हैं। वे पुराने राजनीतिक अधिकार हासिल करना चाहते हैं। ऐसा करके वे आग से खेल रहे हैं। संविधान को दी गयी कोई चुनौती हमें मंजूर नहीं। संविधान को तोड़ने का जो प्रयास करेगा, उसका हम डट कर विरोध करेंगे। फिर भी नेहरू के तमाम ऐसे प्रयासों के बाद भी सामंती शक्तियां जीतीं और जीतती रहीं। पहले उनकी अपनी हैसियत अधिक थी, वह धीरे-धीरे घटने लगी तो उन्होंने सत्तारूढ़ दलों और मुख्यधारा के दलों के बीच अपनी पैठ बना ली। अब भी देश के तमाम हिस्सों में राजा, महाराजा के परिजन संसद पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति में परिवारवाद के सबसे बेहतरीन उदाहरण कुछ राज परिवार हैं, जिनमें सभी बालिग सदस्य कुछ न कुछ राजनीतिक ओहदा हासिल कर चुके हैं। 2024 में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां तमाम राजा परिवार नेपथ्य में हैं, वहीं कई जगह अभी भी वे अपना जलवा बिखेर रहे हैं।

नावें बदलता रहा सिंधिया घराना

2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक निगाह ग्वालियर के शाही परिवार के वारिस ज्योतिरादित्य सिंधिया पर टिकी है। पहली बार वे भाजपा के टिकट पर गुना संसदीय सीट से लड़ रहे हैं। इससे पहले वे चार बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने और केंद्र में मंत्री रहे। पिता माधव राव सिंधिया कांग्रेस में रहे, जबकि दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया जनसंघ और भाजपा की स्तंभ रहीं। 1949 में ग्वालियर समेत 15 रियासतें जब मध्य भारत का हिस्सा बनी थीं तो सरदार पटेल ने ग्वालियर महाराजा को मध्य प्रांत का राज प्रमुख भी बनाया था। 2001 में माधवराव सिंधिया के निधन के बाद गुना सीट पर हुए उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया भारी मतों से जीते और लगातार जीतते रहे, लेकिन उनका विजय रथ 2019 में भाजपा ने रोक दिया। उनके ही पुराने विश्वासपात्र केपी यादव ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का टिकट लिया और उनको 1.25 लाख मतों से हरा दिया। तीन पीढ़ियों से सिंधिया घराने की अपराजेय छवि भी उस हार से आहत हुई, लेकिन सिंधिया ने अपनी ताकत से केपी यादव का टिकट ही नहीं कटवाया बल्कि उनको होशंगाबाद और बैतूल का प्रभारी बना कर गुना के परिदृश्य से ही हटा दिया। भारत के राज परिवारों में सिंधिया घराना बहुत खास है क्योंकि उस परिवार ने 27 बार सांसद का चुनाव जीत कर रिकार्ड कायम किया है। सिंधिया परिवार के सदस्यों को केवल दो चुनावों में शिकस्त मिली। पहली बार 1984 में वसुंधरा राजे भिंड से कांग्रेस से हार गयी थीं और 2019 में ज्योतिरादित्य गुना से। यह परिवार लोकसभा की राह से ही संसद पहुंचता रहा है, लेकिन ज्योतिरादित्य राज्यसभा सदस्य बनकर भी संसद पहुंचे।

1952 में जब देश के हर कोने से कांग्रेस जीत रही थी तो गुना और ग्वालियर में हिंदू महासभा जीती और शक की सूई सिंधिया घराने पर पड़ी। 1957 में पंडित नेहरू ने ग्वालियर महाराज जीवाजीराव सिंधिया को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा तो विजयाराजे सिंधिया दिल्ली उनसे मिलने पहुंचीं। नेहरू जी ने उनके कांग्रेस विरोध का कारण पूछा तो राज परिवार ने सफाई दी। नेहरू जी ने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है तो आप कांग्रेस से चुनाव लड़िए और लाल बहादुर शास्त्री से मिल लीजिए। फिर 1957 में पहली बार गुना सीट से राजमाता

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

कांग्रेस के टिकट पर हिंदू महासभा के उम्मीदवार को हराकर संसद में पहुंचीं। दो बार वे कांग्रेस के टिकट पर जीतीं, एक बार जनसंघ, एक बार निर्दलीय और 4 बार भाजपा के टिकट पर सांसद रहीं। उनके पुत्र माधवराव सिंधिया 9 बार सांसद रहे। राजमाता ने 1967 में स्वतंत्र पार्टी और फिर जनसंघ का दामन थाम लिया। उनकी ताकत से 1971 में इंदिरा लहर में ग्वालियर चंबल संभाग की तीनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस हार गयी।

माधवराव सिंधिया की राजनीतिक पारी जनसंघ के टिकट पर गुना से आरंभ हुई, पर 1977 में आपातकाल के बाद वे कांग्रेस में चले गए। उनकी दोनों बहनों वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे को राजमाता ने भाजपा की राजनीति में जगह दिलायी। वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री तक बनीं और उनका बेटा दुष्यंत राजस्थान की झालावाड़ सीट से भाजपा सांसद और फिर चुनाव मैदान में है। यशोधरा राजे भी 1998 में भाजपा के टिकट पर मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचीं। पांच बार विधायक और मंत्री बनीं। ग्वालियर महल का दबदबा संसद और विधानसभा दोनों में रहा। मध्य प्रदेश में जब 1990 में भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा विधायकों को राजमाता का लिखा एक पत्र लिखा काफी चर्चित रहा। उसमें नसीहत के साथ लिखा था, अत्यंत सादगी पूर्ण और आडंबरहीन जीवन हमारे जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों की विशेषता होनी चाहिए, चंदे के धंधे को अब पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। शिलान्यास के पत्थरों पर नाम खुदवाने की लालसा के हम शिकार न बनें। धंधेबाज निजी सचिवों की खुशामदी और प्रलोभनी सलाह हमारे मन को डांवाडोल न करे। चाटुकारों और स्वयंभू शुभचिंतकों की उस जमात से भी कृपया आप लोग सतर्क रहें, जो सत्ता के गुड़ पर मक्खियों की तरह भिनभिनाती हैं।

महारानी पटियाला मैदान में

पटियाला के पूर्व शाही परिवार की बहू और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी श्रीमती प्रणीत कौर भाजपा टिकट पर पटियाला संसदीय सीट से इस बार मैदान में हैं। अमरिंदर सिंह की मां राजमाता मोहिंदर कौर और पिता भी संसद सदस्य रहे हैं। खुद अमरिंदर सिंह 1980 में पहली बार संसद में पहुंचे थे। 2009 से 2019 तक लगातार प्रणीत कौर कांग्रेस से सांसद रहीं। यूपीए सरकार में 2009 से 2014 के दौरान वे विदेश राज्य मंत्री रहीं। अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद भी वे हाल तक कांग्रेस में ही बनी रही थीं, क्योंकि पार्टी छोड़ती तो उनकी संसद सदस्यता छिन सकती थी, इसलिए उन्होंने 2024 में भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। अमरिंदर सिंह 1967 से राजनीति में सक्रिय हैं। पटियाला के मोती महल से अरसे तक कांग्रेस की सत्ता चलती थी। सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने वहीं से तय किया। पटियाला कांग्रेस का परंपरागत गढ़ रहा है। 1952 से 1977 तक यहां से कांग्रेस ही जीतती थी, पर 1977 में अकाली दल के गुरुचरण सिंह तोहड़ा ने उस गढ़ को तोड़ा था।

मैसूर महाराजा का परिवार भी अखाड़े में

दक्षिण भारत में कर्नाटक का मैसूर राजघराना देश के प्रमुख मालदार घरानों में रहा है। उस घराने के दायरे में सोने की खदानें तक रहीं। भाजपा ने उस घराने के उत्तराधिकारी यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार को मैसूर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहां भाजपा ने अपने दो बार के सांसद प्रताप सिम्हा का टिकट काट दिया है। उनके ही बनवाए पास पर पिछले साल लोकसभा में युवाओं ने सदन में कूद कर हंगामा किया था। मैसूर राजपरिवार के वारिस श्रीकांत दत्त वाडियार का दिसंबर 2013 में निधन हो गया था। उनकी कोई संतान नहीं थी, लिहाजा यदुवीर को गोद लिया गया। श्रीकांत दत्त वाडियार मैसूर से चार बार सांसद रहे और राजनीतिक जीवन का अधिकतर हिस्सा कांग्रेस में बीता था। कभी वे भी अपराजेय माने जाते थे। 1991 में वे भाजपा में चले गए, पर कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रप्रभा अर्स से पराजित हो गए। फिर 1996 और 1999 में जीते, लेकिन 2004 के चुनावों में तीसरे स्थान पर आने के बाद वे राजनीति से विमुख हो गए। वे सार्वजनिक तौर पर कहते थे कि भाजपा तो संघ वालों के लिए ही है और बाहरी आदमी की शायद ही उनसे निभ पाती है। खैर, उस सीट पर महाराजा की टक्कर कांग्रेस के एम. लक्ष्मणा वोक्कालिगा से है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वहीं की वरुणा विधानसभा सीट से विधायक हैं।

भाजपा का भरोसा टिहरी घराने पर

भाजपा ने उत्तराखंड के टिहरी राजघराने की माला राजलक्ष्मी शाह को फिर से टिकट देकर टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। राम लहर में 1991 में राज परिवार भाजपा से जुड़ा था। वह चंद अपवाद को छोड़ लगातार विजयी होता रहा। इसके पहले टिहरी राजघराने के सदस्य कांग्रेस के टिकट पर लड़ते थे। माला राजलक्ष्मी शाह 2012 में तत्कालीन सांसद विजय बहुगुणा की खाली की गयी सीट पर उपचुनाव में जीत कर संसद पहुंची थीं और तबसे लगातार जीत रही हैं। उनके ससुर महाराजा मानवेंद्र शाह आठ बार वहां से सांसद रहे। वे तीन बार कांग्रेस और पांच बार भाजपा के टिकट पर संसद पहुंचे। 1948 में टिहरी राज का भारत में विलय हुआ तो मानवेंद्र शाह ही महाराजा थे, लेकिन 2007 में उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में महाराजा के पुत्र मनुजेंद्र शाह कांग्रेस के विजय बहुगुणा के हाथों पराजित हुए। विजय बहुगुणा 2009 में भी कांग्रेस से जीते, लेकिन राज परिवार ने बाद में यह सीट उनसे छीन ली। टिहरी राजपरिवार को लोग बोलंदा बद्री यानी भगवान विष्णु का बोलता रूप मानने की परंपरा रही है। देश में जब कांग्रेस की लहर बह रही थी तो उस दौरान निर्दलीय टिहरी महारानी कमलेंदुमती शाह ने 1952 में संविधान सभा के सदस्य रहे दिग्गज कांग्रेसी नेता ठाकुर कृष्ण सिंह को हरा दिया था। उस चुनाव में महाराजा मानवेंद्र शाह का नामांकन पत्र रद्द हो गया था। बाद में महाराजा मानवेंद्र शाह 1957, 1962 और 1967 में लगातार तीन बार कांग्रेस के टिकट पर जीते। प्रिवीपर्स से नाराज होकर 1971 का चुनाव महाराजा निर्दलीय लड़े, पर कांग्रेस के स्वाधीनता सेनानी परिपूर्णानंद पैन्यूली के हाथों पराजित हो गए। तभी यह धारणा टूटी कि बोलंदा बद्रीनाथ कभी नहीं हारते। टिहरी राज परिवार का जमीनी असर 1952 में तब दिखा जब राजमाता वोट

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

मांगने निकलीं। किसी चुनाव में भाग लेने वाली वे पहली गढ़वाली महिला थीं। लोकसभा चुनाव जीतने के साथ उन्होंने तीनों विधान सभा सीटों सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों को जिताया। पहले चुनाव पर टिप्पणी करते हुए सुंदरलाल बहुगुणा ने लिखा था कि कांग्रेस चुनाव तो हार गयी पर कई बदलाव हुए हैं। तमाम क्षेत्रों में लोगों के दिमाग में पीढ़ियों से राजाओं के प्रति जो खौफ था, वह भाग रहा है।

मंडी में राजाओं की हैसियत

हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर भी राजाओं की हैसियत दिखती है। अब तक हुए 17 लोकसभा चुनावों में केवल छह बार वे लोग जीते, जिनका राज परिवार से कोई संबंध नहीं था। इस बार भाजपा ने वहां बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत को उम्मीदवार बनाया है। उनके मुकाबले हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वे छह बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं, जो 1971, 1980 और 2009 में मंडी से लोकसभा चुनाव जीते थे। विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह 2004, 2013 और 2021 के उप चुनावों में यहां से विजयी रही थीं। उसी सीट से भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री और पटियाला राज परिवार की राजकुमारी अमृत कौर, मंडी के राजा जोगिंद्र सेन, ललित सेन, कुल्लू राज परिवार के महेश्वर सिंह चुनाव जीते थे। यह बड़ी संसदीय सीट है और इस बार लोकसभा चुनाव के साथ वहां की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। देश की आजादी के बाद भी जिन राज्यों में राजाओं का दबदबा कायम है, उनमें हिमाचल भी है। वहां से कई राजा-रानी संसद पहुंचे। 1951-52 में हुए पहली लोकसभा के चुनाव में तो बिलासपुर सीट से कोट कहलूर के राजा आनंद चंद ऐसे एकमात्र निर्दलीय सांसद थे, जो निर्विरोध चुनकर संसद में पहुंचे थे। पहले चुनाव में देश से 37 निर्दलीय सांसद जीते थे, जिनमें कई राजा, महाराजा थे।

ओडिशा में राजाओं का जलवा कायम

ओडिशा भारत के उन राज्यों में है, जहां राजघरानों की राजनीति में खासी दिलचस्पी है। इन दिनों ओडिशा में लोकसभा के साथ विधान सभा के चुनाव भी चल रहे हैं और वहां एक दर्जन राज परिवारों के सदस्य किस्मत आजमा रहे हैं। शाही परिवार का अब भी ग्रामीण इलाकों में सम्मान कायम है। राजशाही का सबसे चर्चित चेहरा बोलंगीर सीट पर संगीता सिंह देव भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं, जो उसी सीट पर चार बार निर्वाचित हो चुकी हैं। संगीता सिंहदेव के पति केवी सिंह देव पटनागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा टिकट पर मैदान में हैं। संगीता खुद राजस्थान में मध्यम वर्गीय राजपूत परिवार में पैदा हुईं और दिल्ली में पली-बढ़ीं, लेकिन बाद में बोलंगीर के पूर्व महाराज राज सिंह देव के बेटे कनकवर्धन सिंह से विवाह के बाद राज परिवार का हिस्सा बनीं। उस परिवार की राजनीति में खासी दिलचस्पी रही है। 1998, 1999 और 2004 में वे जीतीं पर 2009 और 2014 में उनको राज परिवार के ही कलिकेश नारायण सिंह देव से पराजय का सामना करना पड़ा जो कि बीजद से उम्मीदवार थे। 2014 में तो वे तीसरे नंबर पर थीं जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर। 2019 में वे करीब 20 हजार मतों के अंतर से जीतीं। ओडिशा में कालाहांडी राज परिवार की ही मालविका केशरी देव कालाहांडी संसदीय सीट से मैदान में हैं। 2023 में वे अपने पति के साथ भाजपा में शामिल हुईं थीं क्योंकि उनका टिकट बीजद ने काट दिया था। उनके पति अरका केशरी देव पहले बीजू जनता दल से सांसद थे जो बिक्रम केशरी देव के बेटे हैं जो तीन बार इस सीट पर विजयी रहे थे।

सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) ने शाही परिवारों के सबसे अधिक आठ सदस्यों को मैदान में उतारा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीन और कांग्रेस ने एक सदस्य को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने ढेंकनाल के राज परिवार की सदस्य सुष्मिता सिंहदेव को ढेकनाल से मैदान में उतारा है। वहीं दिग्गज नेता रहे ए.एन. सिंहदेव की पोती 28 वर्षीय सुलक्षणा गीतांजलि देवी सनाखेमुंडी विधानसभा क्षेत्र से बीजद की उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा विधायक रमेश चंद्र जेना से है। उनका पूरा परिवार राजनीति में है। दादा एएन सिंहदेव 1967 से 1995 के बीच चार बार यहां से विधायक और 1989 में अस्का लोकसभा सीट से सांसद भी रहे। उनकी दादी और पिता किशोर चंद्र देव भी 1990 और 2004 के चुनावों में यहां से सांसद रहे, जबकि मां नंदिनी देवी 2014 में इस सीट पर विधायक बनी थीं। गीतांजलि खुद धाराकोटे पंचायत समिति की अध्यक्ष हैं। चिकिती विधान सभा सीट से भी बीजद ने शाही परिवार के चिन्मयानंद श्रीरूप देब को मैदान में उतारा है। उनकी मां शहरी विकास मंत्री उषा देवी हैं। उनके दादा सच्चिदानंद देव 1971 में इस सीट पर जीते थे जबकि मां उषा देवी 2000 से लगातार 5 बार जीतीं।

बोलांगीर सीट से बीजद से दो बार सांसद रहे कलिकेश नारायण सिंह देव अब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं रानी अरुंधति

राजबाड़ी की मदद से तृणमूल की घेराबंदी

इस बार के लोकसभा चुनाव में कई और सीटों पर निगाहें लगी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने कृष्णानगर लोकसभा सीट से राजबाड़ी की राजमाता अमृता रॉय को मैदान में उतारा है। वे तृणमूल कांग्रेस की चर्चित सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ मैदान में हैं, जो एक चर्चित चेहरा हैं और उनकी सदस्यता जाने को लेकर काफी हलचल भी रही है। 2019 में महुआ मोइत्रा ने भाजपा के कल्याण चौबे को 63218 वोटों के अंतर से मात दी थी। खबरों में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अमृता राय को फोन करके चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद राजमाता 20 मार्च को पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में भाजपा की विधिवत सदस्य बनीं। कृष्णानगर राजबाड़ी (राजमहल) नादिया जिले में है जो बेशक आकर्षण का एक केंद्र है। एक दौर में यही नादिया का शाही निवास होता था और सत्ता चलती थी, लेकिन अब दौर बीत चुका है और राजमाता का कितना असर होगा यह तो चुनावी नतीजा ही बताएगा, पर यह हकीकत भी अपनी जगह है कि वाम दलों ने पश्चिम बंगाल और केरल में राजशाही के असर को बहुत कुंद किया है। भूमि सुधारों ने राजाओं-जमींदारों की जड़ो में मट्ठा डालने का काम किया, ये सच अपनी जगह कायम है।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

देवी देवगढ़ विधानसभा सीट से बीजद उम्मीदवार हैं। देवगढ़ के पूर्व राजा और संबलपुर के भाजपा सांसद नितेश गंगा देव की वे पत्नी हैं। बीजद ने राजपरिवार के एक दूसरे सदस्य पुष्पेंद्र सिंह देव को धर्मगढ़ विधानसभा सीट से उतारा है। अंगुल विधानसभा क्षेत्र से संयुक्ता सिंह अपने पति मौजूदा विधायक रजनीकांत सिंह की जगह लड़ रही हैं। वे अंगुल शाही परिवार से संबंधित हैं। राज परिवार के अन्य सदस्यों प्रत्युषा राजेश्वरी और प्रताप देब को भी बीजद ने उम्मीदवार बनाया है।

अन्य सीटों के उम्मीदवार

राजशाही परिवारों की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ये चंद बानगियां हैं। राजस्थान में राजनीति में पूर्व राजपरिवारों का महत्व अब भी बरकरार है। कई राजपरिवार जो राजनीति में नहीं हैं, पर उनका भी सामाजिक रुतबा कायम है और वे चुनाव में एक कारक हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे और धौलपुर शाही खानदान के वारिस दुष्यन्त सिंह झालावाड़ सीट से चार बार भाजपा सांसद रह चुके हैं और फिर मैदान में हैं। वहीं मेवाड़ के राज परिवार की महिमा सिंह राजसमंद से जयपुर के राजपरिवार की दीया कुमारी (जो अब उप मुख्यमंत्री हैं) के स्थान पर मैदान में भाजपा के टिकट पर उतरी हैं। महिमा कुमारी मेवाड़ राजघराने के विश्वराज सिंह की पत्नी हैं। विश्वराज सिंह महाराणा प्रताप के वंशज हैं और 2023 में नाथद्वारा विधानसभा सीट से कांग्रेसी दिग्गज नेता सीपी जोशी को पराजित करके विधानसभा पहुंच चुके हैं। कई दूसरे राजा भी 2023 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान विधानसभा पहुंचे।

उत्तर प्रदेश में मनकापुर रियासत के कीर्तिवर्धन सिंह भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं। उनके पिता आनंद सिंह भी सांसद रहे। वह परिवार जिताऊ घोड़े पर दांव लगाने के लिए विख्यात है। वहीं कांग्रेस

कोल्हापुर राज परिवार के शाहू छत्रपति।

ने छत्तीसगढ़ की सारंगढ़ रियासत की डॉ. मेनका देवी को रायगढ़ सीट से उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने मध्य प्रदेश में शहडोल राजघराने की हिमाद्रि सिंह को फिर मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश में राघोगढ़ सीट पर राज परिवार के ही दिग्विजय सिंह पर सबकी निगाहें लगी हैं, जो दो बार लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

त्रिपुरा पूर्व सीट पर महारानी कृति सिंह देबबर्मा पर भाजपा ने दांव चला है जो त्रिपुरा राज परिवार की हैं, पर उनका विवाह छत्तीसगढ़ के कवर्धा परिवार में हुआ है। उनके पति योगेश्वर राज सिंह कांग्रेस नेता रहे। वे टिपरा मोथा पार्टी के नेता प्रद्योत देबबर्मा की बड़ी बहन हैं।

कोल्हापुर राज परिवार के सदस्य को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। 76 वर्षीय शाहू छत्रपति-2 के परदादा छत्रपति शाहू महाराज का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। राज परिवार का मुकाबला एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मौजूदा कोल्हापुर सांसद संजय मांडलिक से है। साहू छत्रपति ने अपने चुनाव अभियान की शुरूआत इन शब्दों के साथ की कि उनके परदादा एक प्रतिष्ठित समाज सुधारक और सर्व-समावेशी विकास के पक्षधर थे। उन्होंने कभी भी लोगों के ध्रुवीकरण को प्रोत्साहित नहीं किया। वे अन्याय से लड़ने और लोक कल्याणकारी अपने दादा की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वे भाजपा से कई मुद्दों पर असहमत हैं और कहते हैं कि आजादी के बाद छह दशकों से अधिक समय तक सभी क्षेत्रों में कांग्रेस के ऐतिहासिक योगदान को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता।

राजाओं-महाराजाओं और रिसायतों में सबसे बड़ी हैसियत हैदराबाद निजाम की रही। आजादी मिली तो हैदराबाद निजाम मीर उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते थे। पर निजाम के वंशजों ने चुनाव नहीं लड़ा, पर सातवें निज़ाम के पोते नवाब मीर नजफ़ अली खान नवंबर 2023 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। वे निज़ाम परिवार से राजनीति में आने वाले पहले व्यक्ति हैं।

आजादी के पहले देश में राज कर रही थीं 652 रियासतें

आजादी के पहले देश में 652 छोटी बड़ी रियासतें राज कर रही थीं। उसमें हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा, कश्मीर तथा ग्वालियर सबसे बड़ी थीं। उनको 21 तोपों की सलामी मिलती थी। भोपाल, इंदौर, कोल्हापुर, त्रावणकोर, उदयपुर,रीवा, कोचीन, पटियाला, जयपुर, जोधपुर, बूंदी, बीकानेर, भरतपुर को 19 से 17 तोपों की सलामी मिलती थी। 149 राजाओं के पास तोपें भी थीं। अपनी सेना और डाक तार विभाग भी था। उनकी अपनी तस्वीरों के साथ डाक टिकट छपते थे। आजादी के बाद भी पूर्व राजाओं को विशेषाधिकार हासिल थे। निजी थैलियों पर आयकर से छूट थी। उनको निशुल्क चिकित्सा, महलों में सशस्त्र संतरी, निवास और मोटरों तथा जहाजों पर निजी झंडा फहराने की आजादी थी, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1879 से भी छूट थी। वे बिना लाइसेंस के भी कुछ प्रकार के हथियारों को रख सकते थे। उन पर मुकदमा दायर करने के लिए सरकार से अनुमति जरूरी थी और उनको जंगली जानवरों के शिकार का अधिकार भी था। उनके महलों को पानी और बिजली मुफ्त थी। यही नहीं जोधपुर, जयपुर, कच्छ आदि के राजाओं के जन्मदिन पर सार्वजनिक छुट्टी होती थी, पर इन बातों को लेकर जनाक्रोश भी था, इसीलिए विशेषाधिकारों को लेकर 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दो बड़े फैसले लिए, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण और राजाओं के प्रिवीपर्स पर रोक। मोटी रकम उन राजाओं को प्रिवीपर्स देने में खर्च होती थी, जिनकी रियासतों का विलय आजाद भारत में हुआ था। इस पर भारी राजनीति हुई, पर आम जनता ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस को इस प्रभावशाली वर्ग से नाराजगी झेलनी पड़ी। वह नाराजगी अब भी कायम है। इनका जलवा भी कई इलाकों में कायम है, पर धीरे-धीरे उतर रहा है क्योंकि अधिकतर राजे -जवाड़े अब परदे के पीछे समझौता करके या फिर किसी और राह से संसद या विधान सभाओं में पहुंच रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बदलती बयार के बीच 18 लोकसभा क्षेत्रों में कितने राजा-महाराजा संसद में पहुंचते हैं।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

लोकतांत्रिक संस्थाओं से नाखुश हैं दुनिया के ज्यादातर मतदाता

इस साल दुनिया में 80 से अधिक देशों में चुनाव होगा, यानी 2024 में दुनिया की करीब आधी आबादी वोट के जरिए अपने नुमाइंदों को चुनेगी। भारत में तो लोकसभा चुनाव शुरू भी हो चुके हैं, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ समेत कई देशों की जनता इसी साल अपने लिए नई सरकार चुनने वाली है। वैसे तो ये चुनाव दुनिया के बड़े हिस्से में लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति पर एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि कई देशों में मतदाता लोकतंत्र नहीं, बल्कि चुनाव और संसद के बंधन से मुक्त एक 'मजबूत' नेता चाहते हैं और वह एक ऐसा नेता हो जो सिर्फ मजबूत निर्णय ही न ले, वरन जन-आकांक्षाओं को पूरा करे। नीलमणि लाल की रिपोर्ट

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रोरल असिस्टेंस (आईडीईए) ने एक सर्वेक्षण के बाद कहा है कि दुनिया के ज्यादातर मतदाता लोकतांत्रिक संस्थानों की मौजूदा स्थिति से नाखुश हैं। 19 देशों के मतदाताओं के बीच किए गए सर्वे के बाद आईडीईए की रिपोर्ट बताती है कि कई देशों में लोकतंत्र की हालत अच्छी नहीं है। उनमें से सिर्फ डेनमार्क एक ऐसा देश निकल कर आया जहां के मतदाता मानते हैं कि अदालतें हमेशा निष्पक्ष होती हैं, लेकिन 19 में से 18 देशों में आधे से अधिक लोग अदालतों की निष्पक्षता को संदिग्ध मानते हैं। हैरानी की बात है कि न्याय व्यवस्था में इराकियों का भरोसा अमेरिकियों के मुकाबले ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक 19 में से आठ देशों में अधिकतर मतदाताओं ने कहा कि वे एक ऐसा मजबूत नेता चाहते हैं जो चुनाव या संसद के बंधनों में न बंधा हो। एक 'मजबूत नेता' के सबसे ज्यादा समर्थक लोगों की राय भारत और तंजानिया से सामने आई है।

मतदाताओं की नजर में लोकतंत्र तो ठीक, एक मजबूत नेता का होना ज्यादा जरूरी

अमेरिका में इस बार डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के एक बार फिर आमने-सामने होने की संभावना है। दोनों के बीच 2020 में भी मुकाबला था और जो बाइडेन की जीत के बाद ट्रंप समर्थकों ने चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था। डोनाल्ड ट्रंप आज तक उस चुनाव में धांधली के दावे करते हैं। आईडीईए के सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 47 फीसद मतदाता मानते हैं कि देश की चुनाव प्रक्रिया विश्वसनीय है। इसी साल जून में यूरोपीय संघ के भी चुनाव होने हैं और इस बार अति दक्षिणपंथी पार्टियां बेहद मजबूत स्थिति में हैं। आईडीईए महासाचिव केविन कसासा-जमोरा के अनुसार, जनता में पैदा हुई भ्रम की स्थितियों पर ध्यान दिया जाना ज्यादा जरूरी है। उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए और चुनावों की विश्वसनीयता को संदेह के घेरे में लाने वाली फर्जी सूचनाओं के प्रसार की पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ा जाना चाहिए। आईडीईए का यह सर्वेक्षण जुलाई 2023 से जनवरी 2024 के बीच हुआ था। सर्वे में शामिल देशों में सबसे बड़े लोकतंत्रों में भारत और अमेरिका के अलावा ब्राजील, चिली, कोलंबिया, गांबिया, इराक, इटली, लेबनान, लिथुआनिया, पाकिस्तान, रोमानिया, सेनेगल, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया और तंजानिया शामिल हैं।

कामकाज से असंतुष्ट

द परसेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी नाम की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 17 देशों में आधे से कम लोग ही अपनी सरकारों से संतुष्ट हैं। सिर्फ चार देश ऐसे हैं जिनमें अधिकतर लोग महसूस करते हैं कि वे आर्थिक रूप से अपने माता-पिता से बेहतर स्थिति में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर देशों में अल्पसंख्यक लोगों में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर संदेह बहुसंख्यक समुदाय से ज्यादा है। रिपोर्ट कहती है कि ब्राजील, कोलंबिया, रोमानिया और सिएरा लियोन में गरीबों के बीच सरकार का समर्थन अन्य वर्गों की अपेक्षा ज्यादा है।

लोकतंत्र की अवधारणा

भले ही लोग असंतुष्ट हों, लेकिन प्रतिनिधि लोकतंत्र की अवधारणा दुनिया भर के नागरिकों के बीच लोकप्रिय बनी हुई है। 2023 में प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा 24 देशों में सर्वेक्षण किए गए थे। प्रत्येक में ठोस बहुमत प्रतिनिधि लोकतंत्र या एक लोकतांत्रिक प्रणाली की विश्वसनीयता देखी गयी जहां नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यह तय करते हैं कि क्या कानून बनेगा ? हालांकि, 2017 के बाद से कई देशों में सरकार के इस स्वरूप के प्रति उत्साह कम हुआ है, लेकिन फिर भी

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

लोग ऐसी ही व्यवस्था चाहते हैं। अध्ययन के निष्कर्षों के मुताबिक कुछ लोग कहते हैं कि यदि जनप्रतिनिधियों में महिलाएं, गरीब पृष्ठभूमि के लोग और युवा वयस्क अधिक हों तो उनके देश की नीतियों में सुधार होगा। अधिक महिलाओं का चुनाव करना विशेष रूप से महिलाओं के बीच लोकप्रिय है और अधिक युवा लोगों को वोट देना 40 वर्ष से कम आयु वालों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है।

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में चुनावों का आयोजन बहुत बड़ा कार्य है, जिसने पूरी दुनिया को अचंभित किया है। भारत के चुनावों पर अपने देश की राजनीतिक गतिविधियों में गाहे-बगाहे भले ही कुछ बातें उठती रही हों, लेकिन दुनिया की नजर में उस पर कभी भी सवाल नहीं उठे, न संदेह किया गया, जबकि अमेरिका से लेकर बांग्लादेश और रूस से लेकर ब्राज़ील तक के चुनावों पर अंगुलियां उठ चुकी हैं। अब भी चुनावी लोकतंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण भारत ही माना जाता है। भारत के चुनाव, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, विशाल, रंगीन और जटिल है। यहां इस साल 19 अप्रैल से शुरू होकर 4 जून को समाप्त होने वाले चुनावों में 96.8 करोड़ से अधिक मतदाता लोकसभा के लिए 543 प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान करेंगे। देश में मौजूदा समय में 2,600 से अधिक राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। 1951 में देश में पहला चुनाव होने के बाद से चुनावी प्रक्रिया लगातार विकसित हुई है। भारत के चुनाव आयोग ने, जो तब बमुश्किल एक साल पुराना था, 17.3 करोड़ मतदाताओं और 1,874 उम्मीदवारों के साथ यह ऐतिहासिक मतदान कराया। निरक्षरता और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी बाधाओं के बावजूद चुनाव आयोग ने सफलतापूर्वक वह कार्य किया जिसे लोगों ने लोकतंत्र में एक महान प्रयोग करार दिया। उस समय लिए गए कई निर्णय हमारी संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन गए हैं, चाहे वह चुनाव चिन्ह हों या अंगुली पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही। तब से, चुनाव बड़े और बेहतर हो गए हैं और उसमें निर्णायक युवा और महिला मतदाता हैं।

इस बार भारत के लोकसभा चुनाव में 21 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से युवा मतदाताओं की लोकसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका रहेगी। यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कुल लगभग 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चुनाव में पहली बार वोट देने वाले यानी 18-19 साल के मतदाताओं की संख्या 1.82 करोड़ है। इसके अलावा 20 से 29 साल के युवा वोटरों की संख्या 19.74 करोड़ है। ये युवा मतदाता किसी भी हार-जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सिर्फ युवा ही नहीं, बल्कि महिला वोटर्स भी निर्णायक बन रही हैं क्योंकि ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है कि महिलाएं अब पुरुषों की अपेक्षा मतदान में ज्यादा हिस्सा ले रही हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में कुल मतदाताओं में से आश्चर्यजनक रूप से 47.1 करोड़ महिलाएं हैं। आंकड़ों के अनुसार, लोकसभा सीटों के मामले में पांच सबसे बड़े राज्यों में से तीन- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में 18 और 19 साल के एक चौथाई या उससे कम युवा वोट देने के लिए पंजीकृत हैं, जबकि अन्य दो राज्यों- पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आधे से भी कम लोगों ने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। देश की सबसे युवा आबादी वाले राज्य बिहार में संभावित 54 लाख (17 प्रतिशत) में से केवल 9.3 लाख नामांकित हैं। दिल्ली में 7.2 लाख युवा आबादी में से केवल 1.5 लाख ने वोट देने के लिए अपना पंजीकरण कराया है, जो कि सिर्फ 21 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की कुल युवा आबादी (18 और 19 वर्ष) में से केवल 23 प्रतिशत ने नामांकन कराया है, जबकि महाराष्ट्र में मात्र 27 प्रतिशत ने पंजीकरण कराया है। पश्चिम बंगाल में केवल 48 प्रतिशत युवा आबादी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए नामांकन कराया है। भारत के सबसे नए राज्य तेलंगाना में 18 से 19 वर्ष के बीच के 8 लाख से अधिक लोग मतदाता सूची में हैं, जो लगभग दो-तिहाई या 66.7 प्रतिशत हैं। इस आयु वर्ग में राज्य की अनुमानित जनसंख्या 12 लाख बताई गई है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी क्रमश 62 और 60 प्रतिशत युवा पहली बार मतदाता बने हैं।

महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि जारी

पिछले कुछ वर्षों में पुरुष और महिला मतदाताओं के बीच का अंतर ऐतिहासिक रूप से काफी कम हुआ है। एसबीआई रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार 2009 के लोकसभा चुनाव में करीब 42 करोड़ मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया था, जिनमें 19 करोड़ महिला मतदाता थीं, जबकि 2014 में 55 करोड़ वोटर ने मतदान में हिस्सा लिया, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 26 करोड़ थी। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया जिनमें 30 करोड़ महिला मतदाता शामिल थीं।

रिपोर्ट में आगामी चुनावी वर्षों में पुरुष और महिला मतदाताओं के बीच अंतर को पाटने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 68 करोड़ मतदाताओं के मताधिकार का उपयोग करने का अनुमान लगाया गया है, जिनमें 33 करोड़ महिला मतदाताओं के शिरकत करने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक मोर्चों पर उनका उचित हिस्सा दिलाने के मामले में 2029 एक निर्णायक बिंदु होगा। इस तरह 2029 को महिलाओं के प्रतिनिधित्व के साथ सामंजस्यपूर्ण विकास का अग्रदूत साबित होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक मतदान की वर्तमान दर ऐसी ही रही तो 2029 में 73 करोड़ मतदाता मतदान में शिरकत कर सकते हैं, जिनमें, जिसमें से 37 करोड़ महिला मतदाता पंजीकृत 36 करोड़ पुरुष मतदाताओं से आगे निकल सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमान है कि 2047 (संभावित चुनाव वर्ष 2049) में पुरुषों और महिलाओं के लगभग समान अनुपात के साथ लगभग 115 करोड़ पंजीकृत मतदाता होंगे और तब महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़कर 55 प्रतिशत तक और पुरुषों की हिस्सेदारी कम हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2047 में, मतदान 80 प्रतिशत तक हो सकता है। यानी लगभग 92 करोड़ लोग वोट डालेंगे। मतदान में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी अधिक होगी, जिसमें 50.6 करोड़ महिलाएं और 41.4 करोड़ पुरुष मतदाता होंगे, जो भारत में चुनावी भागीदारी के विवर्तनिक बदलाव को दर्शाता है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनावों में भारत में सबसे अधिक महिलाओं (32.2 फीसदी) को मैदान में उतारा था। उसके बाद भारत राष्ट्रीय कांग्रेस (31.6 फीसदी) रही है।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

कवर स्टोरी

लोकसभा चुनाव

दिलचस्प हुई जंग चौंका सकते हैं नतीजे

अंजलि मिश्रा, नई दिल्ली।

लोकसभा चुनाव-2024 अपने तीसरे चरण की दहलीज पर आते-आते बेहद दिलचस्प ही नहीं, बल्कि एक नए सियासी मोड़ की ओर बढ़ चुका है। वैसे तो बीते मार्च के मध्य में चुनाव की घोषणा से पहले ही सत्ताधारी भाजपा से लेकर तमाम चुनावी सर्वेक्षण एजेंसियों, टीवी चैनलों और मीडिया संस्थानों ने अपने-अपने प्लेटफॉर्म पर इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकतरफा जीत के पुर्वानुमानों की झड़ी लगाने के साथ ही कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन का मर्शिया पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन पहले चरण के चुनाव और कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र आते ही बहस का सारा विमर्श ही बदल आ गया है। आम जनता से जुड़े चुनाव के जरूरी मुद्दे फिर किनारे हो गए हैं। सत्तारूढ़ भाजपा ने तो कांग्रेस और उसके 'इंडिया' गठबंधन की सरकार बनने पर लोगों की भैंस, महिलाओं का मंगलसूत्र और आम लोगों की संपत्तियों के छिन जाने का डर दिखाना शुरू कर दिया है। उसने इसके साथ ही इस चुनाव में खुलकर हिंदू-मुसलमान, घुसपैठियों, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों और पाकिस्तान तक को खुलकर मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। बावजूद इसके विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा को विपक्ष की राजनीतिक पिच पर आने को मजबूर कर दिया है। लिहाजा चुनाव अब एकतरफा नहीं रह गया है। बदली चुनावी राजनीतिक परिस्थितियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भाजपा कांग्रेस और उसके चुनावी घोषणा पत्र पर उस हद तक हमलावर हो गई है कि कांग्रेस को उन बातों की भी सफाई देनी पड़ रही है, जो उसके घोषणा पत्र में नहीं है।

केंद्र की सत्ता में भारी बहुमत के साथ दस साल रहने के बाद भाजपा और राजग रोजगार के नए अवसर, बेरोजगारी से निजात, बेहतर आर्थिक स्थिति और आम लोगों की बेहतरी के लिए किए गए कामों के साथ ही भविष्य के अपने रोडमैप को लोगों के बीच ज्यादा प्रमुखता से रख सकती थी, लेकिन उसने अपने सबसे अमोघ अस्त्र धार्मिक ध्रुवीकरण की धार फिर से तेज कर दी है। लिहाजा किसान-जवान, महंगाई-बेकारी, उद्योग-रोजगार, महिला सुरक्षा-मजबूत भारत के मुद्दे भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान से बाहर हो गए हैं, जबकि मुसलमान, मुस्लिम लीग, मंगलसूत्र, पाकिस्तान से लेकर भैंस चुनावी मुद्दा बन रहे हैं। यह स्थिति लोकसभा चुनाव के पहले दो चरणों के मतदान के बाद आई है, वर्ना उसके पहले भाजपा और उसके प्रचार

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

की तेज आंधी 'अबकी बार 400 पार' और विकसित भारत के दावे के इर्द-गिर्द चल रही थी, लेकिन अब वे बातें नहीं हो रही हैं और सारा फोकस धार्मिक विभाजन के जरिए सत्ता की राह आसान बनाने के पुराने आजमाए दांव पर आ गया है।

चुनाव से पहले जिस विपक्ष को मरा हुआ कहा जा रहा था, उसे अब देशद्रोही, अर्बन नक्सल से लेकर संपत्ति छीनने वाला बताकर अपने पक्ष में वोट हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा की एक तिहाई से अधिक सीटों पर वोटिंग के बाद बदले इस सुर का संदेश साफ है कि 'चार सौ पार' का नारा जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रहा है। शायद यही वजह है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का घोषणा पत्र -2024 इस बार के आम चुनाव के विमर्श की धुरी बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र में मंगल सूत्र से लेकर भैंस तक छीन लेने के ऐसे-ऐसे दावे कर रहे हैं, जिनका आसानी से लोगों के गले उतरना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में साफ शब्दों में इस तरह की बातें नहीं की हैं। प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल जब चुनाव में अपना एजेंडा भूल केवल विपक्ष के घोषणा पत्र पर ही अपने चुनाव अभियान का संचालन कर रहे हों तो यह समझना कठिन नहीं कि चुनाव एकतरफा होने का दावा जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता।

लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के अगले ही दिन से पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा के तमाम शीर्ष नेताओं ने अपनी रणनीति बदली है तो उसे अनायास नहीं कहा जा सकता। संकेत तो इस तरफ ही इशारा करते हैं कि जमीनी स्तर पर विपक्ष के जुझारूपन ने कुछ तो काम किया है और उसका असर दो चरणों के मतदान के वोट प्रतिशत में आयी गिरावट से दिखता है।

राजनीतिक विशलेषकों का भी मानना है कि मतदान प्रतिशत में गिरावट का यह ट्रेंड इसका संकेत है कि चुनाव में किसी तरह की कोई लहर नहीं है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भाजपा बालाकोट के एयरस्ट्राइक से देश में सरकार के प्रति बने उत्साह का काफी असर था, जिसका भाजपा को चुनाव में भरपूर फायदा भी मिला, जबकि उससे पहले 2014 में केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे थे और मोदी व भाजपा उससे निजात के मामले में जनता को समझाने में कामयाब रहने के साथ चुनाव जीत लिया था, लेकिन इस बार स्थितियां अलग हैं और मौजूदा सरकार को अपने दस साल के काम और जिन मुद्दों पर सरकार असफल रही है-उसका भी जवाब देना है। इसके साथ ही राज्यों में उभर रही चुनावी तस्वीरों पर गौर किया जाए तो हिंदू बनाम मुस्लिम का विमर्श बहुत कारगर होने की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि ये फार्मूले पूर्व में कई बार आजमाए जा चुके हैं और उनसे अधिकतम फायदे का निचोड़ भी आ चुका है। ऐसे में इस बार इसकी धार पहले से कुंद भी हो सकती है। हालांकि यह फॉर्मूला अब भी किसी हद तक ही सही, असरदार तो है ही।

इस बार के चुनाव में महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को विपक्ष के मैदान में कम से कम खड़ा रहने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब तक दो चरण की वोटिंग के बाद जमीनी रिपोर्टों से लेकर कई दूसरी एजेंसियों के आकलन से यह संकेत मिल रहे हैं कि अखाड़े में मुक़ाबला तगड़ा है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विपक्ष लड़ाई में ही नहीं है। दक्षिण भारत के पांच राज्यों के वोटिंग पैटर्न और आकलन के आधार पर माना जा रहा है कि तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन के सहयोगी पिछली बार की तरह लगभग शत प्रतिशत सीटें हासिल करने की स्थिति में हैं। पिछले चुनाव में तमिलनाडु-पुडुचेरी की 40 में से 39 और केरल की 20 में से 19 सीटें कांग्रेस व उसके सहयोगियों को मिली थीं। इन दोनों राज्यों में भाजपा के लिए इस बार भी गुंजाइश नहीं दिख रही है। दक्षिण में कर्नाटक भाजपा का मजबूत गढ़ है और 2019 में सूबे की 28 में से 25 सीटें जीत पार्टी ने यह साबित भी किया था। मांडया की एक सीट पर भाजपा के समर्थन से निर्दलीय की जीत हुई थी। मगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की जोड़ी ने राज्य की सत्ता में आने के बाद सियासी हालात अब काफी बदल दिए हैं। आपसी अंतर्विरोधों से जूझ रही भाजपा को इस चुनाव में तगड़ी चुनौती मिली है। तमाम विश्लेषण इशारा कर रहे कि पिछली बार केवल एक सीट जीतने वाली कांग्रेस लोकसभा में कम से कम आधी-आधी की लड़ाई पर खड़ी है। इसका मतलब है कि कर्नाटक में भाजपा को पिछली बार की तुलना में दर्जन भर सीटों का नुकसान हो सकता है। तेलंगाना की 17 में से पिछली बार चार लोकसभा सीटें भाजपा तो तीन कांग्रेस के खाते में गई थीं। अभी चार महीने पहले सूबे की सत्ता में आयी कांग्रेस मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की लोकप्रियता और पार्टी के चुनावी वादों के दम पर इस बार छलांग मारने की प्रबल दावेदार है। तेलंगाना की लड़ाई में भारत राष्ट्र समिति अब तीसरे नंबर पर पहुंच गई है और कांग्रेस-भाजपा आमने सामने हैं। वहां का आंकलन है कि चाहे भाजपा की सीटें तेलंगाना में कम न हों मगर,

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

कांग्रेस अपनी तीन की पिछली संख्या में कम से कम आठ और अधिकतम दस सीटें बढ़ाने की स्थिति में है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में कांग्रेस-इंडिया गठबंधन के लिए कोई गुंजाइश नहीं दिखती और तेलगूदेशम के साथ गठबंधन के कारण भाजपा को एक-दो सीटें वहां मिलने की उम्मीद है। इन अनुमानों की रोशनी में देखें तो दक्षिण में भाजपा की पिछली बार की 29 सीटों की संख्या में लगभग 10 की कमी रह सकती हैं।

महाराष्ट्र में लोकसभा 2024 का चुनाव निसंदेह सबसे जटिल और दिलचस्प चुनाव बन गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़-फोड़ कर छिन्न-भिन्न करने के बाद भी भाजपा को महाराष्ट्र में तगड़ी चुनौती मिल रही है। उद्धव के खिलाफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शरद पवार के विरोध में उनके सगे भतीजे अजीत पवार को खड़ा करने के बाद भी इंडिया गठबंधन के साझीदार कांग्रेस-शिवसेना यूबीटी-एनसीपी पवार के महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार चुनाव को बराबर की टक्कर वाला बना चुके हैं। कुछ राजनीतिक सर्वेक्षणों से लेकर विशेषज्ञ अनुमानों में तो महाविकास अघाड़ी को भाजपा-एनडीए गठबंधन की तुलना में अधिक सीटें मिलने की बात तक कही जा रही है। पिछली बार महाराष्ट्र की 48 में से 42 सीटें भाजपा-एनडीए ने जीत ली थी और तब उद्धव उसके साथ थे। जैसा अनुमान लगाया जा रहा, परिणाम कुछ वैसा ही रहा तो महाराष्ट्र में भाजपा-एनडीए की पिछली बार की तुलना में सूबे से सीटों की संख्या डेढ़ दर्जन तक कम हो सकती है। वहां भाजपा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब देश के सबसे वयोवृद्ध वरिष्ठ नेता शरद पवार पर पीएम मोदी उनकी शारीरिक स्थिति का मजाक उड़ाते हुए उन्हें भटकती आत्मा बताने वाला तल्ख बयान देते हैं।

उधर, गुजरात में भी भाजपा को राजपूत समाज के बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। वहां भी चुनाव से पहले भाजपा ने अर्जुन मोडवाडिया समेत कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं को तोड़ विपक्ष की चुनावी मुहिम को डिरेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में नाराजगी और असंतोष के बावजूद भाजपा के प्रति मोह के पुराने पैटर्न को देखते हुए कोई चमत्कार ही गुजरात में विपक्ष की खाली झोली में कुछ भर सकता है यानी सूबे की 26 सीटों को लेकर भाजपा आश्वस्त रह सकती है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में पिछली बार 28 सीटें भाजपा ने जीती थी और वहां भी कांग्रेस दो-चार सीटों से ज्यादा उसका नुकसान करने की स्थिति में नहीं है। छत्तीसगढ़ की 11 में से नौ सीटें भाजपा के खाते में रही थी और अब तक के संकेतों से साफ है कि कांग्रेस इस बार भी अधिकतम तीन-चार सीटों के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाएगी। असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों की 25 सीटों के आंकड़े में भी बहुत फर्क आने के आसार नहीं है। पिछले दो आम चुनाव में राजस्थान में भाजपा ने सभी 25 लोकसभा सीटें जीती हैं, मगर 2024 में तस्वीर अलग होने के पुख्ता संकेत हैं जहां दो चरणों में सभी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। माना जा रहा है कि भाजपा को राजस्थान में आठ से दस सीटों का नुकसान हो सकता है तो सूबे में कांग्रेस के खाते में कमोबेश इतनी सीटें जुड़ने की संभावनाएं हैं।

पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद दिलचस्प और आक्रामक तेवर के दौर में है। राज्य की 42 सीटों में पिछली बार 22 सीटें जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस भाजपा के 18 सीटों की जीत के आंकड़े को नीचे लाने के लिए जोर लगा रही है। ममता बनर्जी के लक्ष्य और पहले दो चरण के बाद के जमीनी सर्वेक्षणों के आकलनों का संकेत तो यही है कि बंगाल में दीदी भाजपा के आंकड़े को शायद बढ़ने नहीं देंगी। इसमें दो-चार कमी करने में कामयाब हो जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी बंगाल के अपने दो सीटों की संख्या से आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। पड़ोसी राज्य ओडिशा में चुनाव के ऐन पहले तक नवीन पटनायक की बीजू जनता दल के साथ गठबंधन की पूरी कोशिश करती रही भाजपा पिछली बार जीती गई आठ लोकसभा सीटों की संख्या पर कायम रह जाए तो यह उसकी उपलब्धि रहेगी। कांग्रेस एक सीट के पिछले आंकड़े को सुधार ओडिशा में दो-तीन सीटें हासिल करने के अनुमान लगा रही है। झारखंड की बात की जाए तो राज्य की 14 सीटों में से भाजपा-एनडीए ने 11 सीटें पिछले चुनाव में हासिल की थी, मगर वर्तमान चुनावी आकलनों में एनडीए और इंडिया के बीच टक्कर बराबर की है। हेमंत सोरेन की ईडी के जरिए गिरफ्तारी के बाद भाजपा को सूबे की सियासत में उथल-पुथल की उम्मीद थी। मगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस-जेएमएम के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और हेमंत की पत्नी कल्पना

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

सोरेन ने जिस तरह ईडी-सीबीआई-इनकम टैक्स ब्रांड की राजनीति को चुनौती दी है, उससे साफ है कि विपक्ष खेमे की सीटें झारखंड में इस बार बढ़ेंगी और उसका नुकसान भाजपा को होगा।

महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के अलावा इस चुनाव में बिहार को विपक्ष के लिए तीसरा प्रमुख स्विंग स्टेट माना जा रहा है। 2019 में राज्य की 40 में से 39 सीटें भाजपा-एनडीए की झोली में गई थीं, मगर इस बार स्थिति काफी भिन्न हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू तब भाजपा के लिए सियासी साथी थे, मगर इस चुनाव में नीतीश के शासन के प्रति नाराजगी का भाव साफ दिख रहा है। उनकी पलटीमार अवसरवादिता की राजनीति के चलते उनकी छवि काफी धूमिल हुई है। भाजपा की चुनौती यह है कि सूबे के स्तर पर उसके नेतृत्व का कोई एक सर्वमान्य चेहरा नहीं। पहले दो चरण के वोटिंग के आकलनों और चुनावी अखाड़े में सबसे प्रभावी जातीय समीकरणों के दांव में विपक्षी खेमे ने भाजपा-जदयू की घेरेबंदी करते हुए मजबूत चुनौती पेश कर दी है। सीट दर सीट प्रत्याशियों की टक्कर और पहले दो चरण के विश्लेषणों का संकेत है कि भाजपा-एनडीए की सीटें बिहार में कम से कम 15 तक कम हो सकती हैं। इसमें भाजपा का कुछ कम और जदयू का नुकसान ज्यादा होना तय माना जा रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि जहां जदयू का वोट बैंक आसानी से भाजपा को ट्रांसफर हो रहा है, वहीं भाजपा समर्थक सवर्ण वोटर गैर सवर्ण उम्मीदवारों से दूरी बनाता दिख रहा है।

देश की राजनीति की निर्णायक दशा-दिशा की सबसे बड़ी धुरी उत्तर प्रदेश है, जहां पिछली बार सहयोगियों समेत 64 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार चुनाव से पहले 75 पार के नारे लगा रही थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग डेढ़ दर्जन सीटों पर पहले दो चरण के वोटिंग पैटर्न और अनुमानों को लेकर भाजपा की चुनावी चिंताएं बढ़ गई हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन ने विपक्षी वोटों में बिखराव की गुंजाइश लगभग बंद कर दी है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी मैदान में मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश जरूर कर रही है मगर जहां मुस्लिम मतदाताओं में भाजपा को चुनौती देने वाले कांग्रेस-सपा गठबंधन को लेकर कोई दुविधा नहीं, वहीं दलित समुदाय का एक बड़ा वर्ग भी एससी-एसटी आरक्षण खत्म होने के खतरों के दावे-प्रतिदावे को लेकर सशंकित है। उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर सबके उम्मीदवार सामने हैं और जिस तरह की लड़ाई तथा चुनावी विमर्श जमीन पर है उसमें भाजपा के खेमे में बेचैनी है। पार्टी के अंदरूनी गलियारों में चल रही चर्चाओं का सार यह है कि पिछली बार की तुलना में इस बार सीटें घटेंगी। चुनावी विश्लेषकों के एक समूह का अंदरूनी आकलन है कि भाजपा सूबे में 50-55 सीटों के आंकड़े पर रह सकती है तो दूसरे समूह ने 55-60 सीटों का अनुमान लगाया है। इस आधार पर देखा जाए तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें बढ़ने की गुंजाइश नहीं, बल्कि कुछ कम जरूर हो सकती हैं। इसका मतलब यह भी है कि बिहार, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में जहां भाजपा की सीटें कम होने की गुंजाइश दिख रही है, उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश या कहीं अन्य से होती नहीं दिख रही है।

भाजपा ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें पिछली बार जीत ली थीं। मगर इस बार कांग्रेस की स्थिति वहां बेहतर बताई जा रही है, जिसे थामने के लिए भाजपा ने मनोहरलाल खट्टर को ठीक चुनाव से पहले हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। खटटर को लोकसभा चुनाव में भी उतारा गया है मगर जमीनी रिपोर्ट्स और जनमानस के रूझानों के आधार पर माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में पांच सीटें जीत सकती है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के चलते मुकाबला आमने-सामने का है। चुनाव की घोषणा के बाद ईडी द्वारा कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग नाखुश है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर देख रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी के पस्त होने की भाजपा जो उम्मीद कर रही थी वह हुआ नहीं बल्कि इसके उलट सहानुभूति का एक

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

भाव जरूर पैदा हो गया है। इसकी वजह से सभी सातों सीटों पर मुकाबला कांटे का है और भाजपा के लिए राजधानी दिल्ली में इस बार विपक्ष का संपूर्ण सफाया करने की गुंजाइश नहीं दिख रही।

जम्मू-कश्मीर की छह सीटों में से घाटी की दो सीटों पर तो भाजपा ने उम्मीदवार ही नहीं उतारे हैं। उत्तराखंड की पांच सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। कहा जा रहा कि इनमें से दो सीटों पर कांग्रेस उलटफेर करने में कामयाब हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। पिछली बार पांचों सीटें भाजपा के खाते में आयी थीं। पहाड़ के दूसरे राज्य हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के छह विधायकों को अपनी तरफ करके भाजपा ने झटका दिया, मगर कांग्रेस ने अब अपना घर संभाल लिया है। इसका संकेत इसी से मिलता है कि दिवंगत दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह जो हिमाचल सरकार में मंत्री हैं, वेकांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर मंडी लोकसभा सीट पर पार्टी के उम्मीदवार बन गए हैं। मंडी में भाजपा की ओर से मैदान में उतरीं बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री कंगना रणौत की चुनावी पारी की शुरुआत करने की जद्दोजहद में हैं। शिमला सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। पिछली बार भाजपा ने हिमाचल की चारों सीटें जीती थीं।

पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। कांग्रेस के पुराने नेताओं को अपना चेहरा बनाकर इस बार अकेले मैदान में उतरी भाजपा राज्य में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी प्रणीत कौर की पटियाला सीट के अलावा कहीं दावेदारी में नहीं है। एनडीए से अलग हो चुके अकाली दल बादल की राजनीतिक साख काफी कमजोर हो चुकी है। ऐसे में वहां मुख्य मुकाबला सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है जिसमें अनुमान लगाया जा रहा कि पार्टी अपने पिछले चुनाव के प्रदर्शन से एक-दो सीटें आगे-पीछे रह सकती है। 2019 के चुनाव में पंजाब से कांग्रेस को नौ सीटें मिली थीं।

इस बार के लोकसभा चुनाव में राज्यों से उभर रही इन तस्वीरों से साफ है कि भाजपा का 'चार सौ पार' नारा छूना तो दूर, बल्कि पिछली बार की उसकी 303 सीटों में से फिलहाल 50-60 सीटें कम भी हो सकती हैं। चूंकि अधिकतर राज्यों में भाजपा अपने राजनीतिक चरम को छू चुकी है। ऐसे में कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल जैसे राज्य में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए उसके पास कहीं गुंजाइश नहीं है। चुनाव का एक पहलू यह भी है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल जैसे कुछ राज्यों में अपनी सीटों में सम्मानजक इजाफे की स्थिति में दिख रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, बिहार में लालू-तेजस्वी का राजद, झारखंड में हेमंत सोरेन का झामुमो, बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में स्टालिन की द्रमुक और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे तथा शरद पवार की पार्टी समेत इंडिया गठबंधन की पार्टियां या तो अपनी सीटें बढ़ा रहीं या पिछले आंकड़े को बरकरार रखने की स्थिति में हैं। शायद यही वजह है कि भाजपा का चुनाव अभियान कांग्रेस के घोषणा पत्र के सहारे भैंस, महिलाओं के मंगल सूत्र, हिंदू-मुसलमान, घुसपैठियों, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों और पाकिस्तान पर केंद्रित हो गया है और कांग्रेस को उसकी सफाई देनी पड़ रही है कि उसने अपने घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात काही ही नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह कहीं नहीं है कि अमीरों से संपत्ति लेकर घुसपैठियों-मुसलमानों को बांट दी जाएगी, लेकिन यह बात भी कही जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पीएम मोदी के इन आरोपों को बेबुनियाद, आधारहीन और झूठा बताते हुए उन्हें दो पत्र लिख उसे साबित करने की चुनौती दे रहे हैं। दिलचस्प यह है कि जिस कांग्रेस को चुनाव अभियान शुरू होने के समय मार्च के प्रारंभ में मोदी खत्म बताकर उसके लिए 40 सीटों के आंकड़े को छूने को भी दुरूह बता रहे थे, अब रोजाना उस पर ही सबसे ज्यादा

हमलावर हैं। कांग्रेस पर प्रहार के पीएम के इस विमर्श से भी साफ है कि चुनावी हवा का रूख बदल रहा है, भाजपा की चुनौतियां बढ़ रही हैं- उसका नतीजा क्या निकलेगा, वह तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

बदली तस्वीर, ज्यादातर सीटों पर रोचक हुआ मुकाबला

कुमार तथागत, लखनऊ।

दो महीने पहले तक नीरस और काफी कुछ एकपक्षीय सा दिखने वाला उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल बदल चुका है। शुरुआती झटकों, साथियों के अलग होने और प्रत्याशियों के चयन की मारामारी से उबरते हुए विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन अब काफी हद तक पटरी पर आ गया है। पहले और दूसरे चरण के मतदान के साथ ही आमने-सामने की लड़ाई का माहौल बनने के बाद अब उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से आधे से ज्यादा पर 'इंडिया' गठबंधन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती पेश करने की स्थिति में आ गया है। चुनाव के हर चरण के साथ-साथ भाजपा जैसे-जैसे और ज्यादा आक्रामक रुख अपना रही है, वैसे-वैसे विपक्षी गठबंधन भी अपनी लड़ाई की धार को और मजबूत करता जा रहा है। उसी रणनीति के तहत आने वाले दिनों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता साझा चुनावी सभाएं करने की भी तैयारी में हैं।

उत्तर प्रदेश में अब तक जिन चरणों का चुनाव निपटा है उनमें पश्चिम, ब्रज क्षेत्र और रुहेलखंड की सीटें रही हैं, जहां पूर्व के चुनावों में भाजपा ने बढ़िया प्रदर्शन किया था। हालांकि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों ने भाजपा के गढ़ माने जाने वाले कई क्षेत्रों में कड़ी चुनौती पेश की तो प्रत्याशियों के चयन, पुराने सांसदों को दोबारा टिकट देने, अलग-अलग जातीय समूहों की नाराजगी ने भी पश्चिम में कई सीटों पर भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी की।

राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ भाजपा का बगलगीर बन जाने का भी अपेक्षित फायदा भाजपा को मिलता नहीं दिखा तो पश्चिम की कई सीटों पर राजपूतों की नाराजगी एक बड़ा मुद्दा बनी। उस नाराजगी का बहुत ज्यादा नहीं, तब भी असर पड़ना लाजिमी है और उसमें नुकसान भाजपा का ही होगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए आसान सा दिख रहा चुनाव, अगर चुनौती भरा हो चला है तो उसके पीछे कई कारण काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ प्रमुख

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

कारणों की पड़ताल की जाए तो काफी कुछ तस्वीर साफ हो सकती है। भाजपा द्वारा अधिकतर सीटों पर पुराने सांसदों को फिर से टिकट देने को लेकर कई सीटों पर खुद उसके कार्यकर्ताओं और बड़े पैमाने पर जनता की नाराजगी देखने को मिल रही है। लगातार दो चुनाव से सांसद रहे प्रत्याशियों को लेकर जनता में नाराजगी दिखी तो कुछ जगहों पर पुराने सांसदों का टिकट कटने को लेकर रोष भी नजर आया है। रालोद का साथ जरूर भाजपा को मिला, पर पश्चिम की कई सीटों पर दोनों के दिल नहीं मिले। वहीं संगठन के तौर पर कमजोर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जमीनी स्तर पर बेहतर तालमेल दिखा है।

फतेहपुर सीकरी में भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर जो पिछला चुनाव 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, उन्हें और भाजपा के शीर्ष नेताओं को कुछ जगह जनसभाओं में जनता से माफी मांग आगे से क्षेत्र में अधिक समय देने का वादा करना पड़ा। उसी सीट पर भाजपा के स्थानीय विधायक बाबूलाल चौधरी के बेटे बागी होकर चुनाव लड़ गए जिसने कोढ़ में खाज का काम किया है। इंडिया गठबंधन के इस सीट से प्रत्याशी कांग्रेस के रामनाथ फौजी हैं जो कारगिल युद्ध लड़ चुके हैं और घर परिवार छोड़ मंदिर में रहते हैं। उनके पक्ष में जनता की खासी सहानुभूति देखने को मिली, जिसने वहां मुकाबले को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। भाजपा के पुराने सांसदों से नाराजगी का आलम यह रहा कि अलीगढ़ में उसके प्रत्याशी सतीश गौतम को पूरे चुनाव भर जगह-जगह जनता का विरोध झेलना पड़ा। वहीं, गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह का टिकट काटने के चलते नाराजगी इतनी रही कि भाजपा के नए प्रत्याशी के साथ मारपीट की नौबत आ गयी। मारपीट की नौबत मुजफ्फरनगर में भी आयी जहां केंद्रीय राज्य मंत्री व भाजपा के कद्दावर जाट नेता संजीव बालियान मैदान में थे। राजपूतों में अपने समुदायों के लोगों को टिकट न देने को लेकर उपजी नाराजगी के चलते पश्चिम के कई इलाकों में उनकी पंचायतें हुईं, जहां भाजपा को हराने की कसमें खायी गयीं। मथुरा में हेमा मालिनी को लेकर भाजपा के समर्थकों व कार्यकर्ताओं में उदासीनता इस कदर रही कि मतदान का प्रतिशत खासा घट गया।

महिला पहलवानों के साथ ज्यादती के मामले में जाटों की नाराजगी को देखते हुए भाजपा ने आखिरी दौर में जाकर कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट पर फैसला लेते हुए उनके बेटे को प्रत्याशी बनाया तो रायबरेली में उसे कांग्रेस की रणनीति ने छका दिया और वहां राहुल गांधी के मुकाबले उसका हाई प्रोफाइल प्रत्याशी उतारने का मंसूबा धरा रह गया। विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप पूरे चुनाव भर चस्पा करती रही भाजपा ने देवरिया, कैसरगंज, प्रयागराज, बहराइच सहित कई जगहों पर नेता पुत्रों को टिकट दिया, जिसके चलते उसे आलोचना का शिकार होना पड़ा। हालांकि प्रत्याशियों को लेकर इंडिया गठबंधन में भी बहुत अनुकूल हालात नहीं रहे। अमरोहा में वर्तमान सांसद दानिश अली से अल्पसंख्यक मतदाता नाराज रहे तो मुरादाबाद में मौजूदा सांसद का टिकट काट नए प्रत्याशी को लाने को लेकर रोष नजर आया। रामपुर में कद्दावर सपा नेता आजम खान की पसंद का प्रत्याशी न होने के चलते उनकी नाराजगी की खबर चर्चा में रही। हालांकि इस सबके बाद भी इंडिया गठबंधन ने असंतोष को थाम अपने मतदाताओं को साधने का हुनर दिखाया।

भाजपा की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती गैर यादव पिछड़ी जातियों को एकजुट करना रही है। विपक्षी इंडिया गठबंधन इस बार इसे लेकर ज्यादा सतर्क रहा है। वैसे समाजवादी पार्टी ने इसकी शुरुआत तो 2022 के विधानसभा चुनावों में ही कर दी थी, पर इस बार के लोकसभा चुनाव में यह चरम पर नजर आयी है। आमतौर पर यादवों की पार्टी कही जाने वाली सपा ने महज पांच टिकट अपनी जाति में दिए हैं जो सभी अखिलेश यादव परिवार के ही सदस्य हैं। कन्नौज से खुद अखिलेश यादव, मैनपुरी से उनकी पत्नी डिंपल यादव, चचेरे भाइयों में आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव को टिकट दिया गया है। वहीं पिछड़ों में दूसरी सबसे अधिक आबादी वाली कुर्मी बिरादरी को इंडिया गठबंधन ने 11 टिकट दिए हैं। शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, निषाद जैसी जातियों को भरपूर टिकट देकर सपा ने भाजपा के गैर यादव पिछड़ी जातियों के समीकरण को कई जगहों पर खराब किया है। इसके अलावा प्रतिनिधित्व के सवाल को लेकर और आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़ी जातियों के कुछ हिस्सों में पहले से भाजपा को लेकर कुछ विरोध को भी भुनाने की पूरी कोशिश इंडिया गठबंधन की ओर से की जा रही है।

राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भाजपा को उम्मीद थी कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा सिर चढ़कर बोलेगा और ध्रुवीकरण के हालात बनेंगे जो उसे मिशन 80 की तरफ ले जाने में मददगार साबित होगा। जनवरी में जिस तरह से राम मंदिर को लेकर लोगों में उत्साह दिखा था, उसने इस धारणा को पुख्ता भी किया था। हालांकि महज दो महीनों में ही यह मुद्दा जनता के बीच अपनी चमक खो बैठा है। प्रदेश में हुई कई रैलियों व देश भर की जनसभाओं में योगी-मोदी जमकर मुसलमान, राष्ट्रद्रोह, पाकिस्तान और पिछड़ों का आरक्षण छीनने की साजिश जैसे आरोप लगा हैं, पर उसका खास

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

असर जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। वाट्सअप के जरिए भाजपा का आईटी सेल हर रोज अल्पसंख्यकों का डर बैठाने की कवायद में जुटा है, जो अब तक तो बेअसर ही दिख रहा है। ध्रुवीकरण न होने का एक बड़ा कारण इंडिया गठबंधन की ओर से अल्पसंख्यकों को बहुत कम महज चार सीटों पर प्रत्याशी बनाना, सपा-कांग्रेस के घोषणापत्र और भाषणों में मुसलमान शब्द से परहेज करना, चुनाव प्रचार में मुसलमानों को आगे न करना और महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, संविधान जैसे कई मुद्दों पर ही चुनाव प्रचार को केंद्रित करना रहा है।

हालांकि किसी विपक्षी पार्टी ने इस मुद्दे को न तो जोर-शोर से उठाया और न ही उसको लेकर कोई जन-जागरण अभियान ही चलाया, फिर भी संविधान में बदलाव की संभावना और दलितों व अति पिछड़ों में इसे लेकर नाराजगी देश के कई अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के लिए गले की हड्डी बन गयी है। संविधान बदल सकता है, इसे हवा देने का काम भाजपा के 'अबकी बार 400 पार' के नारे और कुछ दोयम दर्जे के नेताओं के भाषणों व बयानों ने भी किया। अब जमीन पर उसका असर देखने के बाद सपा और कांग्रेस ने उसे जोर-शोर से उठाना शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में कई सामाजिक संगठनों, बौद्धिक समूहों और जन-अधिकारों के लिए आंदोलन करने वालों ने उसे लेकर जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे डा. लक्ष्मण यादव की पहल पर मध्य व पूर्वी उत्तर प्रदेश में संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत हो गयी है। इस मुद्दे के उठने के नुकसान को भांपने के बाद प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने 400 पार का नारा देना बंद किया है और बाबा साहब के संविधान को अक्षुण्ण रखने की बात कहनी शुरू की है। दूसरी ओर संविधान के मसले पर दलितों की प्रतिक्रिया देखते हुए इंडिया गठबंधन के हर शीर्ष नेता ने इसे जोर-शोर से उठाना शुरू कर दिया है।

चुनावी कौशल में महारत हासिल कर चुकी भाजपा ने इन सब कारणों और इसके चलते मिलने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बीते एक सप्ताह से ठाकुरों के विरोध को थामने और उन्हें मनाने की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। उसी के तहत अमित शाह ने बेंगलुरु में राजपूत बिरादरी के असरदार नेता राजा भैया से मुलाकात की। राजा भैया अपने प्रभाव वाली सीट कौशांबी पर भाजपा प्रत्याशी से नाराज थे और खुद के गृह जनपद प्रतापगढ़ में भी एनडीए के लिए प्रचार नहीं कर रहे थे। शाह से मुलाकात के बाद उनके तेवर नरम पड़ गए हैं और अब उन्होंने एनडीए के लिए वोट मांगने का ऐलान कर दिया है। इसी तरह विधान परिषद के चुनाव में आजमगढ़ में भाजपा की किरकिरी कराने वाले पूर्व मंत्री यशवंत सिंह को फिर से पार्टी में वापस ले लिया गया है। यशवंत सिंह को भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ अपने बेटे को चुनाव लड़ाने व जिताने की वजह से छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया था। पूर्वांचल के प्रभावी ठाकुर नेता व पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह बीते काफी समय से भाजपा में आने व अमित शाह से मिलने का असफल प्रयास कर रहे थे। बदली परिस्थितियों में आनन-फानन में राजकिशोर सिंह को दिल्ली बुला अमित शाह से उनकी मुलाकात करवाई गयी और पार्टी में शामिल कर लिया गया है। एक ताजा घटनाक्रम में जौनपुर में बसपा प्रत्याशी श्रीकला सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और उनकी जगह पार्टी ने पुराने सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया है। श्रीकला पूर्व सांसद व सजायाफ्ता धनंजय सिंह की पत्नी

हैं। माना जा रहा है उनके चुनाव मैदान में रहने से ठाकुर मतदाताओं का अधिसंख्य हिस्सा उनके पाले में रहता और भाजपा के जौनपुर प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के लिए मुश्किल होती। बसपा के कोऑर्डिनेटर घनश्याम खरवार का कहना है कि धनंजय सिंह ने खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया।

उत्तर प्रदेश के इस सियासी रण में बसपा और उसकी सुप्रीमो मायावती की बड़ी भूमिका है। लगातार छीजते जनाधार के चलते बसपा शायद ही गिनती की सीटों पर मुख्य मुकाबले में है, पर उसके प्रत्याशियों के चलते किसको नुकसान हो रहा, यह देखना अहम होगा। चुनाव की शुरुआत के साथ जिस तरह से मायावती ने अपने प्रत्याशी घोषित किए, उससे साफ था कि वह इंडिया गठबंधन को कम और भाजपा को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थीं। मायावती के उत्तराधिकारी व भतीजे आकाश आनंद अपनी चुनावी रैलियों में भाजपा के खिलाफ जहर उगल रहे थे। हालांकि इस मोर्चे पर भाजपा ने काम करना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों से मायावती ने अपने प्रत्याशी बदलने शुरु कर दिए हैं और यह बदलाव भाजपा के लिए मुफीद और सपा-कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। इतना ही नहीं आकाश आनंद की रैलियों की तादाद घट गयी है और वे एकाएक चुनावी परिदृश्य से गायब हो चले हैं। इतना तय है कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने बसपा का अपने पक्ष में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।

अब देखना यह है कि अपने खिलाफ जा रहे इतने कारणों और मुद्दों व उनके लिए शुरू किए गए डैमेज कंट्रोल के बाद भाजपा उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हासिल कर पाती है। इतना तो साफ है कि दो साल पहले यूपी के लिए दिए गए मिशन 80 के नारे को भाजपा ने भुला दिया है और अब सारी कवायद 2014 नहीं, तो 2019 की सफलता दोहराने पर आकर टिकी है। दूसरी ओर अब तक के चरणों में हुए मतदान के रुझान से उत्साहित इंडिया गठबंधन की पूरी कवायद भाजपा को अधिक से अधिक सीटों पर घेरने की है। चंद दिनों पहले तक आसान सा दिखने वाला यूपी का चुनावी गणित अब इस कदर उलझ गया है कि दर्जन भर सीटों को छोड़ दें तो करीब-करीब पूरे प्रदेश में ज्यादातर सीटों पर जबरदस्त लड़ाई के हालात हैं और 80 लोकसभा सीटों में से कम से कम आधे पर तो स्थिति इस पार या उस पार वाली हो चुकी है।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

पावर सेंटर

उत्तर प्रदेश

यूपी के बाद दिल्ली पर नजर

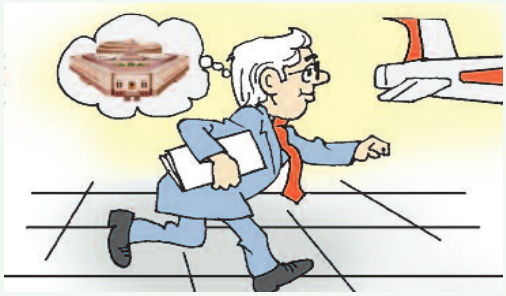

देशभर में कैडर के हिसाब से नौकरशाहों की सबसे ज्यादा तादाद उत्तर प्रदेश में है। लिहाजा हर बैच में यहां ज्यादा अफसर मिलते हैं और उसी हिसाब से रिटायर भी होते हैं। लगभग हर साल रिटायर होने वाले ज़्यादातर अफसरों में पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग की लालसा रहती है। उनमें भी सरकार के मुखिया के नजदीक रहने वाले मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव जैसे पदों पर कार्यरत अफसर रिटायर होने से पहले ही पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग का कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। उस लिहाज से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग और रियल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण (रेरा) के चेयरमैन के पद पर बड़े अफसरों की निगाह ज्यादा रहती है। हालांकि पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग वाले कुछ पद और भी हैं, लेकिन रिटायर होने वाले सभी अफसर उस पर पोस्टिंग पा ही जाएं, यह आसान नहीं। इस बीच, यूपी कैडर के अफसरों की आंखों में भारत सरकार के अधीन दिल्ली में पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग वाले पदों को लेकर एक नई चमक दिखी है। हुआ यह कि उत्तर प्रदेश के तीन मुख्यमंत्रियों मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के करीब रहकर काम करने वाले चर्चित अफसर नवनीत सहगल लगभग दो महीने पहले भारत सरकार के अधीन प्रसार भारती के चेयरमैन बन गये। उसके बाद से ही बड़े पदों पर बैठे जुगाड़ू अफसरों ने भारत सरकार के अधीन पोस्ट रिटायरमेंट नौकरशाहों से भरे जाने वाले दूसरे पदों पर पोस्टिंग के लिए अभी से हाथ-पैर चलना शुरू कर दिया है। सूबे के कई प्रमुख अधिकारी इस साल रिटायर हो रहे हैं। वैसे लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव होने हैं। चुनाव परिणाम आने के कुछ दिनों बाद 30 जून को सूबे की सबसे बड़ी प्रशासनिक कुर्सी पर कार्यरत दुर्गाशंकर मिश्र का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पूर्व में मुख्य सचिव के पद की दावेदार मानीं जा रहीं राधा एस चौहान भी 30 जून को रिटायर हो जाएंगी। सूबे में राजभवन से लेकर महत्वपूर्ण पदों पर रहे महेश कुमार गुप्ता भी इसी माह रिटायर हो रहे हैं। राजस्व परिषद के चेयरमैन रजनीश दुबे इसी अगस्त में रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद दिसंबर में 1989 बैच के मनोज सिंह और लीना नंदन भी रिटायर हो रही हैं। सत्ता के गलियारों में यह चर्चा ज़ोर पकड़ रही है कि इनमें से कई अफसरों ने अभी से अगली पोस्टिंग के लिए गोटी फिट करनी शुरू कर दी है। कुछ ने तो अपना बायोडाटा भी उपयुक्त स्थान पर पहुंचा दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि आगामी जुलाई में इस कवायद का रिजल्ट भी सबके सामने आ जाएगा, जब प्रदेश से रिटायरमेंट के बाद दो साहब दिल्ली में नया दायित्व पा जाएंगे। उधर, नया मुख्य सचिव बनने के लिए 1988, 1989 और 1990 बैच के कुछ अधिकारी अभी से मुख्यमंत्री के पास हाजिरी लगाने लगे हैं। उनमें तो कुछ ऐसे भी हैं जो बिना मांगे ही लोकसभा चुनाव में विपक्ष को कैसे पटखनी दी जाए- इसके सुझाव सीएम के नजदीकी सहयोगियों को दे रहे हैं।

अब हो रहा अफसोस

कई बार बिना सोचे-समझे जल्दबाजी में लिए गए फैसले पर जीवन भर अफ़सोस होता है। उत्तर प्रदेश में एक सीनियर पुलिस अफसर इन दिनों इस पीड़ा को झेल रहे हैं। साहब वैसे तो बेहद ही सुलझे हुए अधिकारी हैं। अपने बेहतर काम की बदौलत उन्हें कई सरकारों से पुरस्कार मिला। वे पुलिस विभाग की जिस भी विंग में तैनात रहे, वहां नियम-कायदे के तहत ही सिपाही से लेकर अफसरों तक ने कार्य किया। जिलों में तैनाती के दौरान उन्होंने अपराधियों का एनकाउंटर करने के बजाए, उसके नेटवर्क को ध्वस्त कर अमन चैन कायम किया। यही नहीं, कानून-व्यवस्था और विजिलेंस जैसी जगहों पर तैनात रहते हुए उन्होंने जो कार्य किया, उसे सूबे के मुख्यमंत्री ने भी सराहा। एक बार तो उन्हें सूबे के डीजीपी की कुर्सी का दावेदार भी माना गया। इसी बीच प्रदेश के पुलिस महकमे की उठापटक को देखते हुए उन साहब ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का फैसला कर किया और उन्हें केंद्र सरकार के एक अहम महकमे में तैनाती भी मिल गई । वहां उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसी बीच केंद्र सरकार ने उनके महकमे में के मुखिया के पद पर उनके ही बैच के एक जूनियर अधिकारी को तैनात कर दिया। वह तैनाती साहब को खल गई। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि उन्हें किसी अन्य विभाग में तैनात कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें अपने से जूनियर के साथ काम करना ठीक नहीं लग रहा है। पता चला कि केंद्र सरकार ने उनके आग्रह को मान लिया और उन्हें पहले की बनिस्बत एक कम महत्वपूर्ण जगह पर डीजी तैनात किए जाने का आदेश जारी कर दिया। साहब को अब वह तैनाती भी रास नहीं आई और उन्होंने वहां ज्वाइन नहीं किया। केंद्र सरकार ने उनके इस निर्णय को अनुशासनहीनता माना और उन्हें अचानक उनके मूल कैडर उत्तर प्रदेश वापस भेज दिया। लखनऊ आकर उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग तो दे दी है, पर अभी तक उन्हें पोस्टिंग नहीं मिली है। अब कहा जा रहा है कि यहां भी साहब के साथ वही समस्या सामने उठ खड़ी हुई है जो केंद्र में उनकी तैनाती के समय हुई थी। यानी सूबे में भी पुलिस महकमे के मुखिया की कुर्सी पर उनसे जूनियर अधिकारी तैनात हैं। ऐसे में उन्हें किस पद पर तैनात किया जाएगा? इसे लेकर उलझन है। कहा जा रहा है कि साहब को अगले साल रिटायर होना है। अब उनके पास अपने से जूनियर अधिकारी के अधीन ही कार्य करने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। ऐसे में साहब का अपने फैसले पर अफसोस करना लाजिमी है।

नए जोश का युद्ध

भगवान बुद्ध ने जिस धरती पर कई वर्ष गुजारे, वहां अखिल भारतीय सेवा के दो युवा अफसरों में युद्ध चल रहा है। उन अफसरों में एक डीएम (जिलाधिकारी) तो दूसरा जिले का एसपी (पुलिस अधीक्षक) है। डीएम साहब को अपने को जिले का प्रमुख हाकिम मानते हैं। साथ ही यह भी कि आईएएस हमेशा आईपीएस से ज्यादा काबिल होता है, इसलिए उसे ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं। उसी सोच के तहत वह चाहते हैं कि भले ही वह किसी जिले में पहली बार डीएम बने हैं, लेकिन जिले के एसपी को उनसे पूछकर ही बड़े एक्शन लेना चाहिए। साथ ही जिले के थानों में किसे थानाध्यक्ष बनाना है, यह वही तय करेंगे। उधर, डीएम साहब की इस सोच को जिले के कप्तान मानने को तैयार नहीं। उनका मानना है कि आईएएस और आईपीएस दोनों के दायित्व अलग-अलग हैं, इसलिए एसपी को कोई भी बड़ा फैसला लेने के पहले डीएम के पूछने की कोई जरूरत नहीं हैं। पुलिस महकमे के बड़े अफसर जिले के एसपी को सलाह देने के लिए काफी हैं। रही बात थानों में थानाध्यक्ष की तैनाती की तो इसकी व्यवस्था भी शासन ने तय की हुई है। उनके रहते जिले में उसी के अनुरूप थानाध्यक्ष की तैनाती होगी। इस मामले में डीएम की सलाह जरूर मानी जाएगी, लेकिन उनके रोज़मर्रा के हस्तक्षेप को नहीं माना जा सकता। लिहाजा ऐसी स्पष्ट सोच वाले युवा एसपी अपने अंदाज में जिले में क्राइम कंट्रोल करने में जुटे हैं और डीएम साहब पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बीते दिनों एक गांव में आग लगने की घटना में उन्होंने थाने के पुलिस अफसरों की लापरवाही बता दी। यही नहीं, एक मामले में तो उन्होंने पुलिस अफसरों के खिलाफ ही गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया। इसके अलावा कई अन्य मामलों में भी उन्होंने थानाध्यक्षों के खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणी की। कई प्रकरणों में पुलिस के खिलाफ मिली शिकायत पर मजिस्ट्रेटी जांच भी बैठा दी। पुलिस के खिलाफ उनके बढ़ते नकारात्मक रवैये को देख एसपी ने डीएम के तमाम मामले डीजीपी के संज्ञान में ला दिये। अब डीजीपी मुख्यालय से एसपी साहब को चुनाव तक शांत रहने की सलाह दी गई है। कहा गया कि डीएम साहब भले ही आईएएस की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों में शामिल रहे हों, पर अभी उन्हें बहुत सीखना है। डीएम साहब की यह पहली पोस्टिंग है, इसलिए उन्हें सहयोग करो। चुनाव बाद उन्हें किस विभाग या जिले में तैनात करना है, यह तय किया जाएगा। डीजीपी मुख्यालय के बड़े अफसरों ने फिलहाल इस मामले को मुख्यमंत्री सचिवालय के अफसरों तक पहुंचा दिया है। उन्हें बता दिया गया है कि दो युवा अफसर नए जोश में आपस में उलझ रहे हैं जो जिले के लिए ठीक नहीं है। डीएम को पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप करने से रोका जाए, ताकि जिले का यह विवाद आगे न बढ़े। कहा जा रहा है कि जिले में आईएएस और आईपीएस के इस टकराव व विवाद को खत्म करने के लिए चुनाव के बाद डीएम साहब को हटाया जाएगा। असल नतीजा, क्या निकलेगा-यह तो चुनाव बाद ही पता चलेगा।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

नीतीश को साथ लेकर भी घाटे में ही रह सकता है राजग

प्रियरंजन भारती, पटना।

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में भाजपा ने 'इंडिया' गठबंधन से अलग करके मुख्यमंत्री और जनता दल-यू के मुखिया नीतीश कुमार को अपने पाले में तो जरूर कर लिया, लेकिन उससे राजग गठबंधन को तात्कालिक तौर पर कोई बड़ा फायदा होता नहीं दिख रहा है। वजह यह है कि नीतीश कुमार की पाटी जदयू तो भाजपा के साथ तो जरूर हो गई, लेकिन कार्यकर्ताओं में नीतीश को लेकर मन से खटास गई नहीं है। कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने मन से नीतीश कुमार को स्वीकार ही नहीं किया है। रही-सही कसर प्रदेश की सभी 40 लोकसभा सीटों में से उन 16 सीटों को फिर से जदयू को दिये जाने ने पूरी कर दी, जिन पर नीतीश की पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी। सीट शेयरिंग का यह फैसला भी पार्टी के तमाम नेताओं को नागवार गुजरा है, लेकिन वे उसका खुलकर विरोध नहीं कर सकते, लिहाजा ऐन चुनाव के मौके पर उनकी खामोशी और उदासीनता ने प्रदेश में राजग की चिंता बढ़ा दी है। इस स्थिति में जदयू उम्मीदवारों को कई क्षेत्रों में भारी नुक़सान होता दिख रहा है, जिसका बड़ा खमियाजा अंततः राजग गठबंधन को ही उठाना पड़ेगा।

भाजपा दोहरा सकती है अपना इतिहास, लेकिन बढ़ेगी जदयू की मुश्किल

भाजपा और जदयू के बीच सीट शेयरिंग में जो 16 सीटें जदयू को मिली हैं, जदयू ने उनमे से दो-एक को छोड़ सभी क्षेत्रों में अपने निवर्तमान सांसदों को ही मैदान में उतार दिया है, जबकि ज़्यादातर सांसदों के खिलाफ एंटी इन्कम्बैंसी की स्थिति है। वैसे भी चुनाव में दो चरणों के मतदान पूरे होने के बाद जिस तरह का वोटिंग प्रतिशत कम और वोटरों में उत्साह की कमी देखी गई, उससे एनडीए की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। साथ ही जदयू के उम्मीदवारों को जिताने में भाजपा का पूरा सहयोग न मिलने से जदयू उम्मीदवारों को कई क्षेत्रों में भारी नुक़सान होता दिख रहा है। पूरी स्थिति और पांच चरणों की वोटिंग पूरी हो जाने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन इतना तो अभी ही साफ हो गया लगता है कि प्रदेश में जदयू को इस बार कम से कम सात सीटों का नुकसान हो सकता है और उस स्थिति में राजग को बिहार की 40 सीटों पर जीत का लक्ष्य ध्वस्त हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और जदयू ने राज्य की 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। भाजपा ने उसी लालच में नीतीश को इस बार फिर से साध लिया है। उधर, दोनों दलों के गठजोड़ में भाजपा जिन सत्रह सीटों पर चुनाव मैदान में है वहां भी मुकाबला कड़ा है, लेकिन फिर भी भाजपा की स्थिति जदयू प्रत्याशियों से बेहतर दिखाई दे रही है। राजग गठबंधन में शामिल चिराग पासवान तथा जीतनराम मांझी व उपेंद्र कुशवाहा की राह भी आसान दिखती है, पर जदयू उम्मीदवार सांसत में फंसे हैं और उसका खमियाजा भाजपा को ही झेलना पड़ेगा।

दरअसल, यह स्थिति प्रदेश की राजनीति में नीतीश कुमार की खत्म हो चुकी विश्वसनीयता और जनता में उनके पलटू राम वाली छवि के कारण नकारात्मक प्रभाव के चलते बनी है। भाजपा ने 'अबकी बार चार सौ पार' का टारगेट हासिल करने के चक्कर में नीतीश कुमार को गले लगाकर जदयू के साथ सूबे में सरकार बना ली और उदारता दिखाते हुए उसे भरपूर सीटें भी दे दीं। तब भाजपा

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

ने संभवतः यह कल्पना नहीं की होगी कि नीतीश कुमार के साथ मिल जाने से उसे फायदा नहीं नुकसान अधिक होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह सोचा नहीं होगा कि नीतीश कुमार के एनडीए में आ जाने के बाद खतरे बढ़ जाएंगे। प्रदेश में नीतीश कुमार के साथ करीब आठ फीसद वोट है। भाजपा नेतृत्व ने उसके जुड़ जाने की ही गणना की, मगर यह आंकलन किया ही नहीं कि नीतीश की सरकार से जनता की नाराज़गी और उनकी गिर चुकी विश्वसनीयता भाजपा पर ही भारी पड़ जाएगी। अब उसे चुनाव के दौरान यह सब देखना पड़ रहा है।

नीतीश कुमार ने उन्हीं निवर्तमान सांसदों को फिर टिकट दे दिए जिन्होंने जनता के बीच पिछले दो टर्म में न तो अपनी इमेज बनाई न ही लोगों से नजदीकी बढ़ाई। ऐसे आठ-दस उम्मीदवार हैं जो मतदाताओं के लिए एकदम फालतू कहे जा रहे हैं। ऐसे निवर्तमान सांसद दो बार से संसद में रहते हुए भी जनता के दिल में उतर नहीं पाए। अब वे भारी पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के बार-बार पलटने से बिहार के बहुसंख्यक समाज में उनके प्रति नाराजगी और रोष का वातावरण है। फिर राजद नेता तेजस्वी यादव के प्रति बिहार के युवाओं और बड़े वर्ग में बढ़ते लगाव ने भी नीतीश कुमार के प्रति विलगाव पैदा कर दिया है। जदयू के लोग बीजेपी के साथ कनेक्ट तो हो गये पर भाजपा के हर स्तर के कार्यकर्ताओं में नीतीश कुमार पच नहीं रहे हैं। उसका नतीजा यह रहा कि नीतीश के समर्थक मतदाता भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों को वोट दे दिये, लेकिन बीजेपी के वर्कर और वोटर्स जदयू से मुंह फेरे बैठे ही रह गये। कटिहार, पूर्णियां, किशनगंज, बांका, भागलपुर क्षेत्रों के मतदान में यह देखा जा चुका है कि भाजपा समर्थक घरों से न तो निकले न ही जदयू उम्मीदवारों के समर्थन में तनिक भी रुचि दिखाई। इसका सीधा खमियाजा जदयू उम्मीदवारों को झेलना पड़ रहा है।

उधर, इंडिया फ्रंट की सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों की सेटिंग में लालू यादव ने इस बार अलग से एनडीए के वोट बैंक में घुसपैठ करने की ऐसी चतुर व्यूह रचना कर डाली कि निशाने पर जदयू उम्मीदवार अधिक फंस गए हैं। लालू यादव ने जदयू बीजेपी और चिराग पासवान के सामाजिक जनाधार को खंडित कर सकने में सक्षम उन्हीं जातियों के दबंग और मजबूत उम्मीदवार मुकाबले में उतार दिए। जदयू को निशाने पर रखना लालू यादव के लिए इसलिए भी बहुत सरल रहा है क्योंकि नीतीश का गिरा ग्राफ और कम हुई साख उनके सामाजिक जातीय समर्थकों वाले जनाधार को अपनी ओर आकर्षित करना आसानी से सफल हो सकता है। लालू यादव की इस रणनीति ने भी नीतीश कुमार और एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चिराग पासवान की सीटों पर भी लालू यादव ने ऐसे ही उम्मीदवारों को खड़ा करवाया है जो उनकी परेशानी बढ़ा सकें। फिर चाचा पशुपति कुमार पारस के गुट में चले गए लोजपा के निवर्तमान सांसदों को टिकट से बेदखल कर चिराग ने खुद आफत मोल ले ली।

इस बीच, समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के गृहक्षेत्र समस्तीपुर में

इस बार लोकसभा का चुनाव बेहद रोचक हो गया है। रोचक इसलिए भी क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से वाली इस सीट पर रामविलास पासवान के परिवार से जुड़ा कोई उम्मीदवार इस दफा चुनाव नहीं लड़ रहा। रामविलास के पुत्र चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से मिली इस सीट से नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी लोजपा की प्रत्याशी हैं। वह एनडीए की आधिकारिक उम्मीदवार हैं, लेकिन रोचक तथ्य यह है कि नीतीश कुमार की सरकार में जदयू के ही दूसरे मंत्री और सांसदों में समस्तीपुर क्षेत्र से संसद का प्रतिनिधित्व कर चुके रामसेवक हजारी के पुत्र सन्नी हजारी कांग्रेस का उम्मीदवार बनकर एनडीए से सीधी लड़ाई में उतर आए हैं। लोजपा एनडीए का घटक दल है। इसके बावजूद जनता दल-यू 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा रामविलास की चुनावी रणनीति और चतुराई से विधानसभा में कम सीटों पर सिमटकर रह जाने की टीस से उबर नहीं पा रहा। नीतीश

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

कुमार के नज़दीकी जदयू के नेताओं और पार्टी की जिला इकाई ने अपने ही मंत्री अशोक चौधरी की बेटी और एनडीए की अधिकृत उम्मीदवार शांभवी चौधरी से दूरी बना ली है। उनके नामांकन से लेकर अब तक के चुनाव प्रचार में जदयू की स्थानीय इकाई के लोगों ने कोई हिस्सेदारी नहीं निभाई। हालांकि सन्नी हजारी के कांग्रेस का उम्मीदवार बनने पर इसे उनका निजी निर्णय कहकर पल्ला झाड़ चुके हैं, पर एनडीए उम्मीदवार के साथ होने का दम भरकर भी वह एनडीए के लिए प्रचार अभियान में वह प्रत्यक्ष रूप से कहीं नजर नहीं आ रहे।

कभी रोसड़ा संसदीय क्षेत्र कहे जाने वाले इस क्षेत्र में कर्पूरी ठाकुर के समाजवादी आधार की जड़ों से आगे बढ़े रामविलास पासवान सांसद थे। वर्ष 1991 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में रामविलास पासवान खुद यहां चुनाव लड़कर जीते थे।1996 के लोकसभा चुनाव में वह हाजीपुर चले गए। फिर 1998 के मध्यावधि चुनाव में रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान यहां से चुनाव लड़े, पर उन्हें हार मिली। वर्ष 1999 के चुनाव में रामचंद्र पासवान जनता दल के टिकट पर लड़े और विजयी हुए। रामविलास पासवान ने 2002 में जनता दल से अलग होकर लोकजनशक्ति पार्टी बनाई। 2004 के लोकसभा चुनाव में रामचंद्र पासवान ने यहां से भाई की पार्टी का उम्मीदवार बनकर जीत हासिल की। उसके बाद हुए परिसीमन में रोसड़ा संसदीय सीट विलोपित होकर समस्तीपुर क्षेत्र का हिस्सा बन गई। 2009 के चुनाव में रामचंद्र पासवान लड़े पर महेश्वर हजारी से पराजित हो गए,मगर 2014 के चुनाव में उन्हें विजय मिली। 2019 में रामचंद्र पासवान फिर जीते, मगर 21 जुलाई 2019 को उनका निधन हो गया। उसी वर्ष हुए उप चुनाव में लोजपा ने उनके बेटे प्रिंस राज को प्रत्याशी बनाया और पिता के निधन की सहानुभूति का लाभ लेते हुए वह चुनाव जीत गए। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी विरासत के उत्तराधिकार की जंग रामविलास पासवान के दूसरे भाई पशुपति कुमार पारस ने छेड़ी और उनके इकलौते पुत्र चिराग पासवान को छोड़ प्रिंस राज समेत अन्य सांसदों समेत अलग गुट बना लिया और केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बन गये। इस लोकसभा चुनाव से पहले चाचा भतीजे के गुट में रामविलास पासवान के असली वारिस होने की जंग लंबे अंतराल तक चली और आखिरकार बीजेपी ने चिराग पासवान गुट को ही पासवान का असली वारिस मानते हुए एनडीए का घटक दल माना और चाचा पशुपति पारस को उपेक्षित छोड़ दिया। चिराग पासवान के गुट को एनडीए की सीट शेयरिंग में समस्तीपुर समेत पांच सीटें दी गई हैं। 1991 के बाद यह पहला संसदीय चुनाव हो रहा है जिसमें रामविलास पासवान और उनके परिवार के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में पासवान परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में नहीं है।

बात इतनी ही नहीं, पासवान जाति के वोटरों को झटकने की छिड़ी जंग में कांग्रेस के सन्नी हजारी की ओर से यह हवा दी जा रही कि वही इस समाज के असली नुमाइंदा हैं। लोजपा प्रत्याशी शांभवी चौधरी को पासवान विरोधी बताया जा रहा है। अशोक चौधरी पासी जाति से आते हैं जबकि उनकी पत्नी ब्राम्हण हैं। शांभवी चौधरी का हाल ही में बहुचर्चित हनुमान भक्त पूर्व आइपीएस अधिकारी और महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल के पुत्र शायन कुणाल के साथ प्रेम विवाह हुआ है। कुणाल सवर्ण भूमिहार जाति के हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद उनके मंत्रिमंडल के दो सदस्यों के बेटे-बेटियों के बीच रोचक हुई चुनावी लड़ाई में दिलचस्प यह है कि एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में नीतीश कुमार की निकटस्थ लॉबी के लोग अशोक चौधरी से मुंह बिचकाए चल रहे दिखते हैं। रामसेवक हजारी कांग्रेस का समर्थन तो खुलकर नहीं कर सकते, लेकिन वह और उनकी पार्टी के नेता एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में खुलकर क्या दबी जुबान से भी कुछ नहीं बोल रहे। सबसे खास बात तो यह है कि नीतीश कुमार समस्तीपुर के चुनाव को लेकर एकदम चुप्पी साधे बैठे हैं।

बिहार में इन स्थितियों के चलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोदी की गारंटी और उनका मैजिक बिहार के जातीय सामाजिक समीकरणों में उछालें मारता नहीं दिख रहा है। इसके संकेत भाजपा और एनडीए प्रचारकों और खुद प्रधानमंत्री की सभाओं में उनकी भाषा शैली में प्रत्यक्ष बदलाव से दिखने लगे हैं। बिहार की जनसभाओं में मोदी हिंदुत्व कार्ड और ओबीसी कार्ड खेलने वाले भाषण दे रहे हैं। उससे

पता चल जाता है कि मोदी का मैजिक बिहार में जमीन पर नहीं है। हालांकि भाजपा के उम्मीदवारों को मोदी गारंटी और मोदी की इमेज का लाभ जरूर मिल रहा है, इसलिए अपेक्षाकृत बीजेपी की सीटें अधिक सुरक्षित मानी जा रही हैं, मगर इसे भी हल्के से नहीं लिया जा सकता कि इंडिया फ्रंट की जातीय किलेबंदी और वोटों का सामाजिक धरातल मोदी को किला फतह करने में बड़े रोड़े अटका सकता है। प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़ों के चलते घरों के भीतर कैद रहने की विवशता मतदान का प्रतिशत बढ़ने से रोक रही है। इसे इस रूप में भी देखा जा रहा कि बीजेपी के वोटर्स मोदी की वापसी को लेकर निश्चिंत भाव में घरों में दुबके बैठे रह जा रहे हैं, जबकि मोदी विरोधी मतदाता भरपूर उत्साह दिखाते हुए मतदान में दोगुनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और यह स्थिति राज्य में मोदी की राह को अधिक पथरीली बना रहा है। इस वास्तविकता से सहज ही समझा जा सकता है कि बिहार की क्रांतिकारी और सियासी संवेदनशीलता वाली जमीन पर भाजपा और मोदी की केंद्र की सत्ता में लगातार तीसरी वापसी का मार्ग कितना और कैसे जटिल हो गया है। यदि यही हालात कायम रह गये तो निश्चय ही बिहार इस बार एनडीए को निराश कर सकता है।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

बदले समीकरण से दिग्गजों के सामने वजूद बचाने की चुनौती

अंशुमान तिवारी की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है और इस बार वहां की सियासी तस्वीर सबसे ज्यादा उलझी हुई है। बीते वर्षों में राज्य के दो प्रभावी राजनीतिक दलों में टूट और दो बार हुए विधायकों के पालाबदल के बाद सत्ता परिवर्तन के चलते सारे सियासी समीकरण बदल गए हैं। उसका नतीजा यह है कि राज्य में सर्वाधिक छह राजनीतिक दलों की साख दांव पर लगी हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त जोर-आजमाइश हो रही है। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में इस बार चार दिग्गज नेताओं का सियासी भविष्य तय होने वाला है। ये चारों नेता सियासी मैदान में अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोकसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि उनकी आगे की राजनीति किस करवट बैठेगी।

राज्य की यह सियासी हकीकत सबके सामने है कि शिवसेना में बगावत के बाद दो गुटों में उसका बंटवारा हो चुका है। उसमें से एक गुट की अगुवाई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, जबकि दूसरे गुट की अगुवाई शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथ में है। इसी तरह महाराष्ट्र के दिग्गज नेता माने जाने वाले शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) भी दो फाड़ हो चुकी है। एक गुट की कमान पार्टी के संस्थापक शरद पवार के हाथों में है, जबकि दूसरे गुट की अगुवाई महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार कर रहे हैं। इन दोनों दलों में टूट के बाद पहला लोकसभा चुनाव हो रहा है और इस कारण लोकसभा चुनाव के नतीजे एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अजित पवार के सियासी वजूद का फैसला करेंगे। देखा जाए तो इस बार का लोकसभा चुनाव इन चारों नेताओं के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। इन चारों नेताओं के साथ ही भाजपा और कांग्रेस भी महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है।

सबसे ज्यादा मुश्किल में भाजपा, पिछली बार मिलीं 23 सीटों का इतिहास दोहराना बड़ी चुनौती

महाराष्ट्र के पिछले दो चुनावों में एनडीए अपनी ताकत दिखाता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गठबंधन था और तब उस गठबंधन ने राज्य की 48 में से 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में भाजपा ने राज्य में सर्वाधिक 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली थी। महाराष्ट्र में यूपीए गठबंधन के लिए 2019 का चुनाव बहुत खराब रहा था। यूपीए उस चुनाव में महज पांच सीटों पर सिमट गया था। वहीं एआईएमआईएम का एक निर्दलीय प्रत्याशी के पहली बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा था। राज्य के पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका था। कांग्रेस इस बार राज्य में न सिर्फ अपना खाता खोलने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है, बल्कि संकेत ऐसे हैं कि उसकी स्थिति इस बार बेहतर हो सकती है। इस बार कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा दबाव की स्थिति में भाजपा के लिए दिख रही है जिसने पिछली बार 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार शिवसेना व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में विभाजन के

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

सीट बंटवारे को लेकर खींचतान

महाराष्ट्र में दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर लंबे समय तक विवाद की स्थिति बनी रही। एनडीए के सीट बंटवारे में दिल्ली के नेताओं तक को दखल देना पड़ा। कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार फैसला लिया गया कि महाराष्ट्र में बीजेपी 28, शिवसेना (शिंदे) 14, एनसीपी (अजित पवार) पांच और राष्ट्रीय समाज पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के बड़े नेताओं के बीच सहमति बनने के बावजूद विभिन्न लोकसभा क्षेत्र में सहयोगी दलों के बीच ही खींचतान की स्थिति बनी हुई है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तस्वीर भी इससे अलग नहीं है। विपक्षी महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर काफी घमासान मचा रहा। आखिरकार फैसला लिया गया कि शिवसेना (यूबीटी) 21, कांग्रेस 17 और एनसीपी (शरद पवार गुट) 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि सीट बंटवारे के बाद विपक्षी महागठबंधन में भी कई सीटों को लेकर नाराजगी की बात सामने आई है। लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) भी मैदान में है। पिछली बार इस पार्टी ने सात फ़ीसदी वोट हासिल करके कई प्रत्याशियों की हार-जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। वैसे भाजपा को उसका ज्यादा फायदा मिला था। इस बार भी यह पार्टी कई सीटों पर प्रत्याशियों की हार-जीत में अहम भूमिका निभा सकती है।

चलते चार अलग-अलग दलों का गठन हो चुका है और उनके साथ भाजपा और कांग्रेस की उपस्थिति दिख रही है।

एक तरफ भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना (शिंदे) और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की राकांपा की महायुति है, जो एनडीए का हिस्सा है। दूसरी ओर विपक्ष गठबंधन का हिस्सा महाविकास अघाड़ी (एमवीए) है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी (शरद) व शिवसेना (उद्धव) शामिल हैं। ऊपरी तौर पर देखने पर यह दो गठबंधनों के बीच सीधा मुकाबला दिखता है, मगर सच्चाई यह है कि सभी राजनीतिक दल राज्य में अपना सियासी वर्चस्व कायम रखने के लिए एक-एक सीट की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीच सियासी वर्चस्व की इस जंग का बड़ा कारण यह भी है कि राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर ही विधानसभा चुनाव में भी सीटों का बंटवारा होगा, इसलिए सभी दल अपनी-अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

शिवसेना में बगावत से बदले सारे गणित

महाराष्ट्र की सियासत में उस समय बड़ा बदलाव दिखा था जब उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाने का फैसला किया था। शिवसेना नेता ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाया था और उस गठबंधन सरकार की अगुवाई उद्धव ठाकरे को सौंपी गई थी। हालांकि शिवसेना के भीतर असंतोष की चिंगारी भी सुलग रही थी जो बाद में बम बनकर फूटी। शिवसेना में हुई बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। शिवसेना में हुई उस बगावत के पीछे भाजपा की भी बड़ी भूमिका थी। दरअसल भाजपा उद्धव ठाकरे की ओर से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन न दिए जाने से उनसे नाराज थी और हिसाब बराबर करने की कोशिश में जुटी हुई थी। यही कारण था कि पार्टी ने शिवसेना में बगावत की अगुवाई करने वाले एकनाथ शिंदे को भरपूर मदद दी थी। एकनाथ शिंदे ने भाजपा से हाथ मिलाकर राज्य में नई सरकार का गठन किया था। भाजपा ऐसे ही मौके की ताक में थी और इसीलिए भाजपा ने तुरंत समर्थन देकर मुख्यमंत्री पद पर शिंदे की ताजपोशी करा दी थी।

उद्धव ठाकरे और शिंदे की अग्निपरीक्षा

शिवसेना में बगावत के बाद पार्टी पर कब्जे को लेकर लंबी जंग चली और आखिरकार अब शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को असली शिवसेना की मान्यता मिल चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना (यूबीटी) की अगुवाई कर रहे हैं मगर उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वे शिवसेना का चुनाव निशान भी गंवा बैठे हैं। शिंदे भाजपा और अजित पवार गुट के साथ मिलकर चुनाव मैदान में कूदे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार गुट) के साथ मिलकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। शिवसेना में बगावत के बाद से ही उद्धव ठाकरे ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनका आरोप है कि भाजपा की मिलीभगत से ही उनकी पार्टी को तोड़ने का खेल खेला गया। मान्यता की जंग में शिंदे गुट की जीत के बाद उद्धव ठाकरे समय-समय पर यह कहते रहे हैं कि जनता की अदालत में ही इस बात का फैसला होगा कि असली शिवसेना कौन है ? उनका कहना है कि दलबदल के जरिए अपनी ताकत बढ़ाने वाले शिंदे को चुनाव में अपनी असली ताकत का पता चल जाएगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे से मतदाताओं पर दोनों नेताओं की सियासी पकड़ का फैसला होना है।

शरद पवार को अजित पवार की चुनौती

एक दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना जैसी स्थिति एनसीपी में भी दिख रही है। शिवसेना की तरह ही एनसीपी में भी दो गुट बन चुके हैं। एनसीपी की स्थापना शरद पवार ने की थी, मगर पिछले साल उनके भतीजे अजित पवार ने बगावत करके उनकी सत्ता को बड़ी चुनौती दी थी। बगावत के बाद अजित पवार ने भाजपा और शिंदे गुट से हाथ मिला लिया था और राज्य में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। शरद पवार को यह बात काफी

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

कचोटने वाली थी कि उनकी पार्टी के अधिकतर विधायक भी अजित पवार गुट में शामिल हो गए थे।

एनसीपी पर भी कब्जे के लिए शरद पवार और अजित पवार के बीच चुनाव आयोग और अदालत में जंग लड़ी गई। बाद में शरद पवार को उस समय भी करारा झटका लगा था जब एनसीपी का मूल नाम और चुनाव निशान भी उनसे छिन गया था। हालांकि शरद पवार और उनके साथी नेताओं ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया था, मगर सच्चाई यह है कि शरद पवार पार्टी और चुनाव निशान दोनों से हाथ धो बैठे हैं। अब लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों गुट अपनी-अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। शरद पवार के लिए यह लोकसभा चुनाव अजित पवार से ज्यादा बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इस लोकसभा चुनाव के जरिए उन्हें यह बात साबित करनी है कि जनता की अदालत में अभी भी उनकी अगुवाई वाली एनसीपी को ही समर्थन हासिल है। यही कारण है कि शरद पवार ज्यादा उम्र और खराब स्वास्थ्य के बावजूद इस बार के लोकसभा चुनाव में काफी मेहनत कर रहे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि यह लोकसभा चुनाव शरद पवार के लिए वजूद की आखिरी जंग साबित हो सकता है।

बारामती से निकलेगा बड़ा संदेश

सुप्रिया सुले

सुनेत्रा पवार

पवार फैमिली का गढ़ माने जाने वाले बारामती लोकसभा क्षेत्र में इस बार दिलचस्प जंग हो रही है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले उस लोकसभा सीट से तीन बार की सांसद हैं और शरद पवार ने एक बार फिर उन्हें इस सीट से ही चुनाव मैदान में उतारा है। बारामती में सुप्रिया सुले को चुनौती देते हुए डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अजित पवार की पत्नी के चुनाव लड़ने के कारण पिछले तीन चुनावों में आराम से जीत हासिल करने वाली सुप्रिया सुले कड़े मुकाबले में फंस गई हैं। उस सीट को पवार फैमिली का गढ़ यूं ही नहीं माना जाता। दरअसल शरद पवार खुद इस लोकसभा सीट से 6 बार चुनाव जीतकर सांसद बने। शरद पवार के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले पिछले तीन चुनावों से लगातार इस सीट पर जीत हासिल करती रही हैं, जबकि अजित पवार भी इस लोकसभा सीट का एक बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यदि पिछले 27 वर्षों की बात की जाए तो लगातार इस सीट पर पवार फैमिली का प्रतिनिधि ही चुनाव जीतता रहा है। इस बार भी बारामती लोकसभा क्षेत्र में पवार फैमिली का प्रतिनिधि ही चुनाव जीतेगा, मगर इस बार पवार कुनबे में आपस में ही सियासी प्रभुत्व की जंग छिड़ गई है। शरद पवार के खिलाफ बागी तेवर दिखाने के बाद अब अजित पवार ने उनकी बेटी की सियासी सत्ता को भी चुनौती दे डाली है। जानकारों का कहना है कि बारामती में शरद पवार अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर यहां सुप्रिया सुले को हार का सामना करना पड़ा तो शरद पवार के साथ ही सुप्रिया सुले के सियासी भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। सियासी जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में सबसे दिलचस्प सियासी जंग बारामती में ही लड़ी जा रही है और इस सीट के चुनाव नतीजे से बड़ा संदेश निकलने वाला है।

चुनाव निशान छिन जाने से बढ़ी मुसीबत

इस बार के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट के लिए अपना-अपना चुनाव निशान मतदाताओं के दिल-दिमाग में बैठाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। बाल ठाकरे के शिवसेना का चुनाव निशान धनुष-बाण था। शिंदे यह चुनाव चिह्न लेने में कामयाब हो गए। इसी तरह अजित पवार का गुट एनसीपी के चुनाव निशान घड़ी को झटकने में कामयाब रहा। शरद पवार गुट अपनी चुनावी सभाओं में यह बताने की कोशिश में जुटा हुआ है कि उनका नया चुनाव निशान तुतारी (तुरही) है। शरद पवार गुट के प्रत्याशी बार-बार यह अपील कर रहे हैं कि तुतारी का बटन दबाना है। अपने चुनाव निशान की लोकप्रियता के लिए शरद पवार गुट के प्रत्याशी अपनी चुनावी सभाओं में तुतारी बजवा भी रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के साथ भी यही स्थिति दिख रही है और यह गुट भी अपने चुनाव निशान को लोगों के बीच स्थापित करने की कोशिश में जुटा हुआ है।

विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा नतीजे का असर

महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे का विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ना तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही महाराष्ट्र के इन सियासी दिग्गजों और उनके राजनीतिक दलों की ताकत का संकेत मिलेगा। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना इन सियासी दिग्गजों के लिए इसलिए भी जरूरी माना जा रहा है ताकि वे अपने गुट को एकजुट रख सकें और विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों को लेकर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर सकें। सियासी जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र के चार सियासी दिग्गजों उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, शरद पवार और अजित पवार के सियासी भविष्य का फैसला करेंगे। यह इन नेताओं के लिए सियासी वजूद बचाने की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे से ही कई दिग्गज नेताओं का सियासी कद तय होने वाला है। अब यह देखने वाली बात होगी कि कौन नेता अपना सियासी वजूद बचाने में कामयाब हो पाता है।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

तृणमूल व भाजपा में है कांटे की टक्कर

वामदल व कांग्रेस हाशिए पर

पश्चिम बंगाल में इस बार के लोकसभा चुनाव में कई चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। राज्य में पहले चरण के मतदान के बाद ही उसके संकेत मिलने लग गए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें और मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 18 सीटें मिली थीं। लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले वाममोर्चा की अगुवा सीपीआई (एम) को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा सत्तारूढ़ दल को अधिकतर सीटों पर कड़ी चुनौती दे रही है। चुनाव सर्वेक्षणों के आधार पर चुनावी विश्लेषक भी भाजपा को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बराबर या उससे अधिक सीटों पर जीत हासिल करने की बात कह रहे हैं।

विनय बिहारी सिंह, कोलकाता।

इस बार के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच, छापा मारने गई राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) पर हमला और संदेशखाली की घटना ने विपक्षी राजनीतिक दलों को ईंधन दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बार-बार बंगाल दौरा इन मामलों को और गरमा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट यह फैसला सुना चुका है कि संदेशखाली के सभी मामलों की जांच सीबीआई करेगी। साथ ही उसने संदेशखाली में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और स्ट्रीट लाइट की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल पुलिस संदेशखाली की जांच में कोई दखल नहीं दे सकती। संदेशखाली में सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी के कुछ नेताओं पर गरीब किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा और उनकी औरतों के साथ अशालीन आचरण का जो गंभीर आरोप लगा है, वह इस चुनाव में केंद्रीय मुद्दा बन गया है। उधर, हाईकोर्ट के जिस जस्टिस अभिजीत गांगुली ने पश्चिम बंगाल सरकार के कुछ अधिकारियों/ नेताओं के भ्रष्टाचारों के खिलाफ कड़े फैसले सुनाए थे, वे तमलुक सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उधर संदेशखाली की जो युवा महिला सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं के खिलाफ खुल कर सामने आई और जमीन हथियाने से लेकर अशालीन आचरण का खुल कर प्रचंड विरोध किया, उस रेखा पात्रा को विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने संदेशखाली से ही चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया है और उसे खूब समर्थन मिल रहा है। रेखा के पति तमिलनाडु में मजदूरी करते हैं, इसीलिए पश्चिम बंगाल में यह लोकसभा चुनाव दिलचस्प तथ्यों को रेखांकित कर रहा है।

दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भाजपा ने अभिजीत दास उर्फ बाबी को टिकट दिया है। बाबी दक्षिण चौबीस परगना जिले के नेता हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। वे ऑटो एंड वर्कर्स यूनियंस में अलग-अलग पदों पर रह चुके हैं। बाबी पहली बार सन 2009 में डायमंड हार्बर सीट पर भाजपा के ही टिकट पर खड़े हुए थे, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। तब वे तीसरे नंबर पर थे। वे 2014 में भी डायमंड हार्बर से भाजपा के टिकट पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ संसदीय चुनाव लड़े थे लेकिन एक बार फिर हार गए थे। डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के समूचे इलाके में उनकी पकड़ अच्छी है, लेकिन फिर भी जीत उनकी झोली में अब तक नहीं आ सकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

के खिलाफ डायमंड हार्बर से भाजपा के नीलांजन राय लड़े थे। अभिषेक बनर्जी को 7,91,127 और नीलांजन राय को 4,70,533 वोट मिले थे। यानी भाजपा दूसरे नंबर पर थी। चूंकि अभिषेक बनर्जी तृणमूल में ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर के प्रभावशाली नेता हैं, इसलिए उनके खिलाफ लड़ाई कड़े मुकाबले वाली होती रही है।

रेखा पात्रा

जस्टिस अभिजीत गांगुली

इस बीच, बीते अपैल के दूसरे हफ्ते में एक दिलचस्प घटना घटी। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बेहाला फ्लाइंग क्लब में अभिषेक बनर्जी के भाड़े पर लिए गए हेलीकॉप्टर का परीक्षण चल रहा था, तभी आयकर विभाग के अधिकारियों की एक टीम पहुंची और बड़े पैमाने पर उसकी तलाशी ली। आयकर विभाग के सूत्रों ने दावा किया कि तलाशी या सर्वेक्षण जैसी कोई कार्रवाई ही नहीं की गई है। निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर मालदा से बेहाला फ्लाइंग क्लब में एक हेलीकॉप्टर के आगमन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आयकर विभाग की एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम को रूटीन जानकारी के लिए से भेजा गया था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस संबंध में शिकायत की। तब केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से आयकर विभाग की इस कथित तलाशी पर रिपोर्ट मांगी। पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट तत्काल भेज दी। इस बीच एक और दिलचस्प घटना घटी। चुनाव आयोग ने मुर्शिदाबाद रेंज के पुलिस डीआईजी श्री मुकेश को ऐसी जगह स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है जहां चुनाव संबंधी कोई काम उनके जिम्मे न हो। उस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गईं और कहा कि यदि मुर्शिदाबाद और मालदा में दंगे भड़कते हैं तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी पड़ेगी। ममता बनर्जी ने धमकी दी कि यदि चुनाव आयोग इसी तरह बंगाल पुलिस के अधिकारियों का तबादला करता रहा तो वे 55 दिनों की भूख हड़ताल करेंगी।

राज्य में चुनावी नारे तो और भी दिलचस्प हैं। उधर भाजपा ने 'अबकी बार, चार सौ पार', 'नो वोट टू ममता' और 'चोर हटाओ, बंगाल बचाओ' का नारा लगाया है तो तृणमूल कांग्रेस 'भाजपा हटाओ, माछ भात खाओ' और 'गली गली में गर्जन, बीजेपी का विसर्जन' नारा लगा रही है। इसके साथ ही पार्टी चिह्न वाली साड़ियों, झंडों, टोपियों, टी शर्ट और गमछे आदि की भारी मांग है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के अगले चरणों के मतदान के पहले पश्चिम बंगाल में हर राजनीतिक पार्टी मतदाताओं को लुभाने के लिए हर तरह के दाव-पेंच अपना रही है, लेकिन मुख्य लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है। तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों के कारण विपक्ष के राजनीतिक हमले झेल रही है। बंगाल के चुनाव को तगड़ा त्रिकोणीय मुकाबला कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वाममोर्चा की कम्युनिस्ट पार्टियों, कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट (आईएसएफ) की लड़ाई कुछेक इलाकों में ही असर डालेगी। पूरे बंगाल में तो टक्कर ममता बनर्जी की पार्टी और भाजपा के बीच ही है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में भाजपा वैसे भी कुल 42 में से 18 सीटें जीत गई थी। ममता बनर्जी कई मौकों पर बंगाली बनाम बाहरी मुद्दे को भुनाती रही हैं, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल सीट से, क्रिकेटर यूसुफ पठान बहरामपुर सीट से और कीर्ति आजाद बर्दवान-दुर्गापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से कोई भी बंगाली नहीं है। ऐसे में इस लोकसभा चुनाव में बंगाली और बाहरी के नारे के नाम पर लोगों से वोट मांगना मुश्किल लगता है। कीर्ति आजाद ने 2014 का लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ा था और बिहार की दरभंगा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे, लेकिन 23 दिसंबर, 2015 को उनको भाजपा से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद वह 2019 के लोकसभा चुनावों के समय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने तब उनको झारखंड की धनबाद सीट से खड़ा किया था, लेकिन उन्हें भाजपा के पशुपति नाथ सिंह ने करीब 4.8 लाख के वोटों के अंतर से हरा दिया था। कीर्ति आजाद नवंबर 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनके खिलाफ भाजपा ने बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और दिग्गज नेता दिलीप घोष को मैदान में उतारा है।

राज्य में चर्चा थी कि शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भाजपा की ओर से भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से पवन सिंह पीछे हट गए। फिर भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह की चर्चा चली। इन पंक्तियों के लिखने तक आसनसोल में भाजपा ने किसी को टिकट नहीं दिया है। जल्दी ही इसकी घोषणा होगी। चर्चा है कि यूसुफ पठान के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ेंगे। बहरामपुर उनकी अपनी सीट है। भाजपा ने क्रिकेटर यूसुफ पठान के खिलाफ निर्मल कुमार साहा को खड़ा किया है। बहरामपुर लोकसभा सीट के चुनावी अतीत की बात करें तो आजादी के बाद 1952 से 1980 तक यहां से रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के त्रिदिब चौधरी लगातार सात बार सांसद रहे। सन 1999 में अधीर रंजन चौधरी पहली बार इस सीट से सांसद

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

निर्वाचित हुए और तब से अब तक, वह लगातार पांच बार सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। संभव है यूसुफ पठान बहरामपुर के अल्पसंख्यक मतदाताओं के वोटों का कुछ प्रतिशत अपनी झोली में डालने में कामयाब हो जाएं लेकिन अधीर रंजन चौधरी जैसे बड़े नेता के कारण यूसुफ पठान की जीत आसान तो नहीं ही होगी।

इस बीच तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (पीएमएलए एक्ट) के तहत मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में वे कृष्णनगर सीट से जीती थीं। इस बार भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें कृष्णनगर सीट से ही टिकट दिया है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ भाजपा के टिकट पर राजमाता अमृता राय चुनाव लड़ रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में महुआ यहां से आसानी से जीत गई थीं। उन्होंने तब भाजपा के कल्याण चौबे को हराया था, लेकिन इस बार राजमाता से उन्हें कड़े मुकाबला का सामना करना पड़ रहा है।

तमलुक सीट पर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व जज अभिजीत गांगुली के खिलाफ सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के युवा प्रत्याशी देवांशु भट्टाचार्य हैं। राज्य में बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार समेत तमाम मामलों में सीबीआई जांच समेत अन्य कड़े फैसले देकर सुर्खियों में रह चुके तत्कालीन जस्टिस गांगुली ताकतवर प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं। देवांशु तृणमूल कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। वह पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय रहते हैं। वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के अत्यंत करीबी हैं। तमलुक का इलाका बंगाल भाजपा के विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के परिवार का गढ़ है। जस्टिस गांगुली को भाजपा में ले आने वालों में शुभेंदु अधिकारी की प्रमुख भूमिका रही है, इसलिए जस्टिस गांगुली की जीत की उम्मीद की जा सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव के समय शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में थे, इसलिए इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी जीते थे। अब दिव्येंदु अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं।

इस बीच एक और सनसनीखेज घटना हो गई। अप्रैल के पहले हफ्ते में छह तारीख को पूर्वी मिदनापुर जिले के भूपतिनगर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक टीम पर हमला हो गया। एनआईए अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर पर दो साल पहले हुए विस्फोट के मामले की जांच के लिए वहां पहुंचे थे। यह घटना एकदम सवेरे करीब 5.30 बजे हुई। एनआईए ने दिसंबर 2022 में हुए एक विस्फोट से संबंधित पूछताछ के लिए भूपतिनगर निवासी मनोब्रत जाना, बलाई चरण माइती सहित टीएमसी के कुछ स्थानीय नेताओं को समन दिया था, लेकिन इन लोगों ने समन को कथित रूप से नजरअंदाज कर दिया। इस पर एनआईए की टीम सुबह-सुबह भूपतिनगर पहुंची और मनोब्रत जाना तथा एक और नेता को हिरासत में ले लिया। जब उन्हें (बलाई चरण माइती और मनोब्रत जाना को) वाहन में बैठाकर एनआईए अधिकारी वापस जा रहे थे, तो ग्रामीणों के एक समूह ने वाहन को रोका और दोनों को छोड़ने की मांग की, लेकिन एनआईए के अधिकारियों ने उन्हें छोड़ने ने इनकार कर दिया। इस पर 100 से अधिक लोगों के समूह ने वाहन पर हमला कर दिया और उसके शीशे तोड़ दिए। इस हमले में एनआईए के दो अधिकारियों को कुछ चोटें आईं। हालांकि, वे मौके से निकलने और स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचने में सफल रहे। उधर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनआइए पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया। उन्होंने कहा कि एनआईए के अधिकारी रात में छापे मारने क्यों गए थे? क्या छापा मारने के पहले एनआईए की टीम ने पुलिस को जानकारी दी थी? पुलिस को पहले जानकारी दी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा- ऐसा ही होता है जब गांव के लोग आधी रात में किसी अजनबी को देखते हैं। चुनाव के दौरान गिरफ्तारी क्यों? भाजपा को लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर वे हमें हरा देंगे। क्या ऐसा करने से वे चुनाव जीत पाएंगे? इस पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा कि जब सेंट्रल एजेंसी पर इस राज्य में हमला हो रहा है तो आम आदमी का क्या हाल है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी तानाशाह हैं और राज्य में कोई कानून-व्यवस्था ही नहीं है।

पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के लोग अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं। मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से हिंदू शरणार्थी के तौर पर पश्चिम बंगाल में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस समुदाय को सम्मान के साथ नागरिकता दी जाएगी। मतुआ समुदाय के लोग उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, हावड़ा, कूच बिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और मालदा में रहते हैं। इस तरह जैसे-जैसे समय बीत रहा है, चुनावी दृश्य दिलचस्प होते जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों को आशंका है कि इस चुनाव में कहीं-कहीं हिंसा हो सकती है। लेकिन नतीजे चौंकाने वाले होंगे, यह तय है। राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ बरानगर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। कारण दिलचस्प है।

बरानगर के विधायक तापस राय तृणमूल कांग्रेस और विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा के टिकट पर इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उसके चलते वह सीट खाली हो गई है। वहां से भाजपा ने सजल घोष को खड़ा किया है, जो इस समय पार्षद हैं। उनके खिलाफ बरानगर विधानसभा सीट से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अभिनेत्री सायंतिका बनर्जी को मैदान में उतारा है। बरानगर विधानसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर है।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

विजय विद्रोही, जयपुर।

राजस्थान में लोकसभा चुनाव निपट चुका है और उसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस ने अपनी-अपनी हार-जीत को लेकर कयास लगाने शुरू कर दिये हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में यहां की सभी 25 सीटें जीत ली थीं, लेकिन इस बार वह इतिहास दोहराए जाने की कतई उम्मीद नहीं है। कुल मिलाकर कुछ बातें शीशे की तरह साफ हैं। एक- इस बार राजस्थान में कहीं कोई मोदी लहर नहीं दिखी। दो-कांग्रेस के पक्ष में भी कोई लहर नहीं रही। तीन- मतदान भी पिछली बार के मुकाबले करीब सवा चार प्रतिशत कम हुआ। चार- कांग्रेस ने पूरा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा। पांच पूरा जाति बनाम जाति चुनाव हो गया। ऐसा लगा कि कुछ सीटों पर दोनों दल आपस में नहीं लड़ रहे, बल्कि एक जाति दूसरी जाति से लड़ रही है। इससे साफ है कि कुछ तो है जो इस बार पूरे राजस्थान में मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है। उधर, भाजपा के लिए वसुंधरा राजे जैसे बड़े नेताओं की उपेक्षा भारी पड़ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस सब स्थिति के चलते डबल इंजन सरकार के दावों की हवा सरकती हुई नजर आ रही है, जिससे सबसे ज्यादा परेशान भाजपा ही है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उसके पास यहां खोने को बहुत कुछ है और कुछ अधिक पाने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं।

खोना तो भाजपा को ही है और पाना कांग्रेस को

कांग्रेस ने राजस्थान में पहली बार तीन लोकसभा सीटों पर गठबंधन करके नया प्रयोग किया है। उसके चलते उसे फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि इस बार यहां भाजपा को वोट दिलाने में मोदी का चेहरा बहुत कारगर नहीं रहा। एक सहयोगी को छोड़ सारे सांसद भाजपा के ही रहे हैं और इस बार यहां उनके खिलाफ भरपूर सत्ता विरोधी लहर (एंटी इन्कम्बैंसी) दिखाई दी। इन सब कारणों के बावजूद अभी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि राज्य में भाजपा कितनी सीटें हार रही है या कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है, लेकिन यह तो दीवार पर लिखी इबारत जैसा है कि भाजपा इस बार यहां घाटे में ही रहेगी। इसके साथ ही बाड़मेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रवीन्द्र सिंह भाटी क्या चमत्कार करने वाले हैं ? उस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इन स्थितियों में इतना तो तय है कि यहां इस बार कांग्रेस का खाता हर हाल में खुलने वाला है। अब तो इस बात को यहां के भाजपा नेता भी स्वीकारने लगे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा 25 में से 17-18 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जबकि कांग्रेस गठबंधन तीन-चार सीटों पर मजबूत स्थिति में है। बाकी की चार-पांच सीटें बुरी तरह फंसी हुई हैं। सबसे रोचक मुकाबला बाड़मेर, बांसवाड़ा और कोटा सीट पर है। तीनों जगह जबर्दस्त मतदान हुआ है। वहां महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया है। तीनों जगह 18-19 साल के पहली बार वोट डालने वाले युवा वोटरों ने बाकी सीटों के बजाय ज्यादा उत्साह दिखाया है। वहां गांवों में ज्यादा वोटिंग हुई है। साफ है कि तीनों सीटों पर चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं यानि भाजपा निपट सकती है। बाड़मेर में मुख्य मुकाबला कांग्रेस के उम्मेदा राम बेनीवाल और निर्दलीय भाटी के बीच है। भाजपा के कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर बताए जा रहे हैं जो केंद्र की मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री भी हैं। अगर जाट, मुस्लिम, मेघवाल (दलित) कांग्रेस की तरफ हो गये तो जीत तय मानी जा रही है। भाटी की उम्मीदें राजपूत, ओबीसी और कुछ हद तक मुस्लिम वोटर पर है। बांसवाड़ा में मोदी ने जिस तरह हिंदू महिलाओं के मंगल छिन जाने को लेकर है कांग्रेस पर हमला बोला, उसके बाद मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल को वोट देगा इसमें संदेह नजर आता है।

बांसवाड़ा में कांग्रेस से भाजपा में गये महेन्द्र जीत सिंह मालवीय और बाप (भारतीय आदिवासी पार्टी) के राजकुमार रोत में है। कांग्रेस ने यहां गफलत पैदा नहीं की होती तो भारतीय आदिवासी पार्टी आराम से सीट निकाल लेती, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम वापस नहीं लेना, कांग्रेस का उसे पार्टी से निकाल देना और उसका चुनाव मैदान में खड़े रहना...इस विवाद से परे होकर आदिवासी वोटर ने रोत का साथ दिया तो भाजपा मुश्किल में पड़ सकती है। उधर मालवीय को पैराशूट उम्मीदवार बता कर भाजपा के नेता भी अंदरखाने विरोध कर रहे हैं। तीसरी सीट कोटा की है जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चुनाव लड़ रहे हैं। कायदे से बिरला की एकतरफा आसान जीत होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने सचिन पायलट के कहने पर रोचक दांव खेल दिया। उसने भाजपा के पूर्व

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

भाजपा को भारी पड़ सकती है वसुंधरा राजे जैसे बड़े नेताओं की उपेक्षा

गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजल को टिकट दे दिया जो बिरला के साथ मिलकर अब तक कांग्रेस को हराते आए थे। कहा जा रहा है कि गुंजल यह चुनाव बिरला स्टाइल में लड़ रहे हैं और मुकाबला कांटे का हो गया है।

राज्य की बाकी 22 सीटों की बात की जाए तो मेवाड़, मारवाड़ में भाजपा मजबूत नजर आती है। मेवाड़ की भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर में भाजपा को आगे माना जा रहा है। पिछले चुनाव में भाजपा ने भीलवाड़ा सीट तो छह लाख के अंतर से जीती थी, फिर भी वहां दो बार के विजयी सांसद का इस बार टिकट काट दिया गया है। इसके पीछे संघ का दबाव बताया जा रहा है। राजसमंद से मेवाड़ राजघराने की महिमा सिंह को टिकट दिया गया है। मारवाड़ की सिरोही जालौर सीट पर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव मैदान में हैं, लेकिन उनकी कमजोर स्थिति हैं। जोधपुर में भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत कड़ी टक्कर के बाद भी चुनाव निकालने की स्थिति में बताए जाते हैं। चार लाख से ज्यादा के अंतर से जीती पाली और अजमेर की सीट पर भी भाजपा अपने को सुरक्षित मान रही है, लेकिन नागौर और शेखावाटी की तीन सीटों (चुरू, झुंझुनूं, सीकर) में भाजपा कड़े मुकाबले में है। नागौर में कांग्रेस की ज्योति मिर्धा भाजपा से चुनाव लड़ रही हैं तो कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल को गठबंधन का साथी बनाया है। शेखावाटी की तीनों सीटों पर कांग्रेस अपने को मजबूत मान कर चल रही है। चुरू में भाजपा से कांग्रेस में आए राहुल कस्वां मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं तो झुंझुनूं में बृजेन्द्र ओला कांग्रेस के खेवनहार बन सकते हैं। सीकर में वाम मोर्चे से अमरा राम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं।

उधर, इस चुनाव में सचिन पायलट के दो उम्मीदवार कांग्रेस के लिए खुशी ला सकते हैं। दौसा से मुरारीलाल मीणा हैं तो टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा। दोनों की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है, लेकिन पायलट के समर्थक अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण सीट पर फंसे हुए हैं। जयपुर शहर की सीट पर भाजपा की जीत में किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन भरतपुर और करोली धौलपुर सीटें पूरी तरह फंसी हुई हैं। वैसे दोनों पर किसी की जीत हो सकती है, लेकिन फिलहाल दोनों जगह कांग्रेस को बढ़त पर बताया जा रहा है।

भाजपा ने इस बार कांग्रेस से आए दो नेताओं को लोकसभा का टिकट दिया था। इस बार यहां दूसरी पार्टी के सैकड़ों छोटे-बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया, लेकिन वसुंधरा राजे जैसे बड़े नेता को एक तरह से घर बिठा दिया गया। बीते 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत सिंह के चुनाव क्षेत्र बारां झालावाड़ तक सिमट कर रह गयीं। वसुंधरा जैसे बड़े नेताओं की उपेक्षा से राज्य में पार्टी के सामाजिक समीकरण बिगड़े हैं। परंपरागत रूप से भाजपा का साथ दे रही कुछ जातियां छिटकी हैं। सोशल इंजीनियरिंग बदली है। कहीं राजपूत तो कहीं जाट नाराज, तो कहीं गुर्जर सचिन पायलट के साथ। वसुंधरा अगर सक्रिय होतीं तो ऐसे समीकरण बिगड़ने नहीं देतीं। या फिर वे उन्हें नाराज होने का मौका ही नहीं देतीं। इस बीच कुछ सीटों पर भितरघात की खबरें भी सामने आई हैं। माना चुनाव मोदी के चेहरे , उनकी गारंटी, उनकी रैलियों के आधार पर लड़ा जा रहा है, लेकिन रोजमर्रा के झगड़े सुलटाने के लिए मोदी रोज-रोज जयपुर नहीं आ सकते और न ही अमित शाह उतना समय निकाल सकते हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे जैसे नेताओं की उदासीनता का खमियाजा क्या भाजपा को उठाना पड़ सकता है, यह देखना दिलचस्प होगा। .

दूसरी तरफ, ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है लेकिन यह जमीनी हकीकत है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ खोना है तो भाजपा को ही खोना है। भाजपा ने पिछली बार 25 में से करीब बारह सीटें चार लाख वोट के अंतर से जीती थीं। दौसा की सीट 78 हजार, भरतपुर और टोंक-सवाई माधोपुर की सीट करीब एक लाख वोट से जीती थी। बाकी पर मार्जिन दो लाख से ज्यादा का था। भाजपा को लगता है कम वोटिंग, सत्ता विरोधी रुझान और उदासीनता के बावजूद वह 22 सीटें तक निकाल ही लेगी, भले ही वहां उसकी जीत का मार्जिन कम हो जाए। उधर कांग्रेस आठ से दस सीटों पर खुद को टक्कर में देख रही है। अगर स्ट्राइक रेट पचास फीसद भी रहता है तो कांग्रेस चार से पांच सीटों में अपने लिए जीत देख रही है। दोनों के दावों में दम है लेकिन मूल बात है कि जनता अगर हराने उतरती है तो पिछली बार के जीत के मार्जिन को नहीं देखती है। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में अगर 200 विधानसभा सीटों में से 173 पर वोटर उदासीन है और राज्य की हर तीसरी सीट पर महिला वोटर आगे रही हैं तो इसका क्या मतलब है ? जाहिर है कि राम मंदिर, राष्ट्रवाद, मोदी का चेहरा, उनकी गारंटी जैसे मुद्दों पर जनता गौर कर रही होती तो इस कदर उदासीन नहीं रहती। साफ है कि महंगाई, बेरोजगारी, घर चलाने में आ रही दिक्कत ऐसे कुछ मुद्दे हो सकते हैं जिसकी वजह से वोटर उदासीन हो। ऐसे में यहां सवाल उठता है कि अगर महंगाई बेरोजगारी को लेकर जनता में इतनी ही नाराजगी है तो जनता विरोध जताने बाहर क्यों नहीं निकली? और सिर्फ तीन लोकसभा सीटों पर ही ज्यादा मतदाता क्यों वोट डालने निकले। ऐसा लगता है जनता नाराज तो है लेकिन इतनी भी नाराज नहीं है कि वह भाजपा को निपटाना ही चाहती हो, हां, उसे सिमटाना जरुर चाहती है। इस तरह निपटाने और सिमटाने की आशंका और संभावना के बीच राजस्थान का पूरा चुनाव सम्पन्न हो चुका है और सबकी नजरें नतीजों पर टिकी हुई हैं।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

भारत के लिए मुश्किलें पैदा करने से पीछे नहीं हट रहा चीन

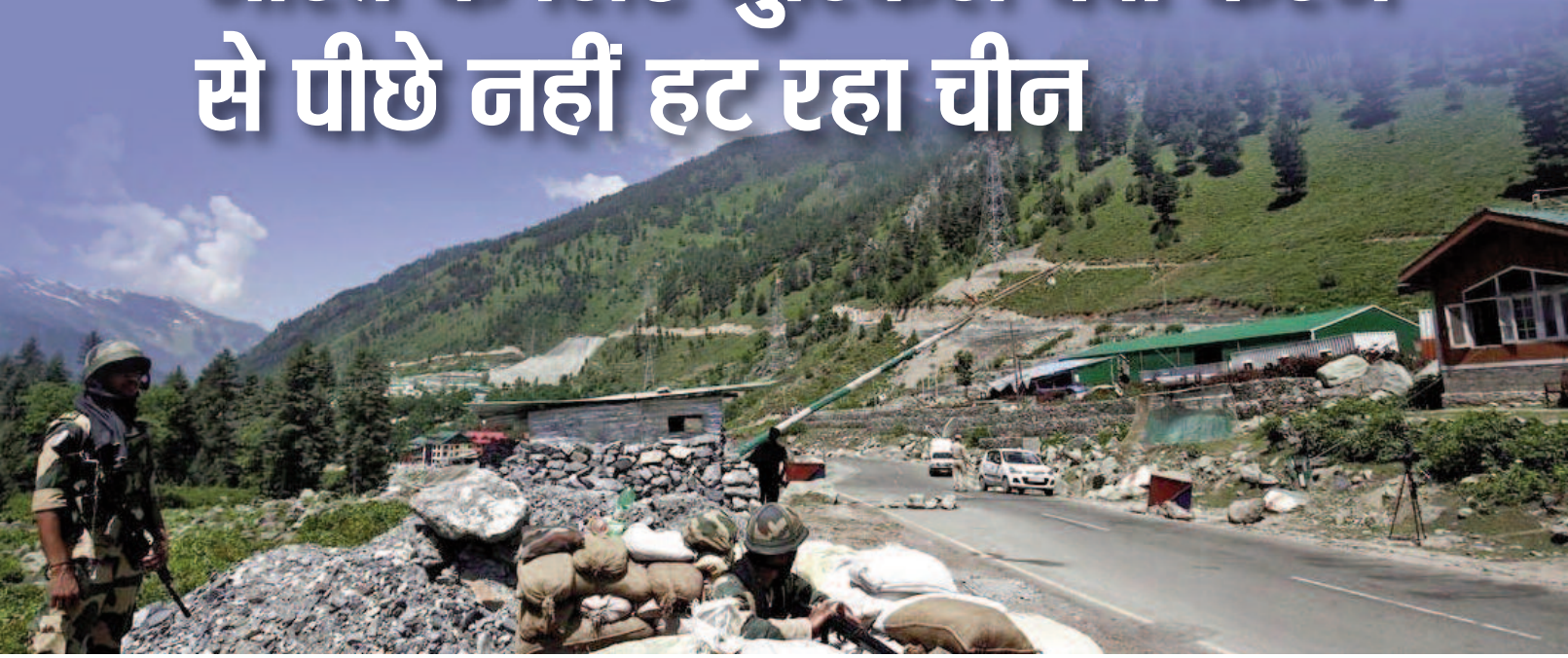

कामिनी त्रिपाठी, नई दिल्ली।

भारत और चीन के बीच रिश्तों की कड़वाहट दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है। पूर्वी लद्दाख में बना सैन्य गतिरोध लगातार जस का तस बना हुआ है। मौजूदा तनाव घटना तो दूर, चीन की तरफ से भारत के लिए नये-नये सिरदर्द पैदा ही होते रहते हैं। मसलन, पहले से चल रहे तनावों के बीच अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों का नया नामकरण करके भारत की मुश्किलों को और बढ़ा देता है। यह किसी से छिपा नहीं है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए पूर्वोत्तर के इस अहम सूबे में देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी दौरा लगने पर चीन फिर से आंखें दिखाने लगा था। लिहाजा केंद्र सरकार को उसे फिर से याद दिलाना पड़ा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अखंड हिस्सा है। अमेरिका भी बीच-बीच में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न बताते हुए बयान जारी कर संदेश देता है कि इस मसले पर चीन अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग है। पाकिस्तान जैसे कुछ चंद मुल्कों को छोड़कर चीन को भारत के सरहदी विवादों पर दुनिया के किसी और देश का साथ नहीं मिल पाता है।

वैसे चीन की नापाक हरकतों के खिलाफ भारत वैश्विक समुदाय के अहम सदस्य मुल्कों को कहीं न कहीं अपनी तरफ से खड़ा कर लेता

भारत के साथ सीमावर्ती इलाकों में नाम बदलने जैसी कर रहा हरकतें

है। बीते कुछ रोज पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विदेशी पत्रिका को दिये साक्षात्कार में कहा था कि भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबध पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए अहम हैं। उन्होंने कहा था कि उनका मानना है कि हम दोनों को अपनी सीमाओं पर लंबे सयम से चली आ रही स्थिति पर तत्काल बातचीत करने की जरूरत है ताकि हमारी द्विपक्षीय बातचीत में मतभेदों को पीछे छोड़ा जा सके। पीएम मोदी के उस बयान को रिश्ते सुधारने की दिशा में भारत की दिलचस्पी का नए सिरे से इजहार माना जा रहा था, लेकिन पीएम के बयान उस हिस्से पर नजर डालें जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और चीन के बीच रिश्तों में नरमी पूरी दुनिया के लिए अहम है तो उसमें साफ संकेत यही था कि यह भारत की तरफ से दुनिया को अपने पाले में लाने की कोशिश थी। भारत चाहता है कि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम ताकतवर देश चीन पर दबाव बनाते रहें ताकि वह भारतीय सरहदों पर अपनी हरकतों से बाज आए।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

यही वजह है कि चाहे पीएम हों या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ने ही कूटनीतिक तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की है कि भारत और चीन के बीच तनाव से पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। इसका कुछ असर इस रूप में देखने को मिला कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से हालिया बयान आया है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर हालात स्थिर हैं। न्यूजवीक मैगजीन के साथ साक्षात्कार में पीएम मोदी के इस बयान कि भारत और चीन के बीच तनाव दुनिया भर के लिए ठीक नहीं है, के बाद अभी चंद रोज पहले चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने कहा है कि वर्तमान में भारत और चीन के बीच सीमा क्षेत्रों की स्थिति सामान्यतः स्थिर है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देश सैन्य चैनलों के माध्यम से प्रभावी कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश जल्द ही एक ऐसे समाधान पर पहुंचने पर सहमत हुए हैं जो दोनों पक्षों को मंजूर हो। उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि चीनी सेना कहीं से भी आगे कोई हरकत नहीं कर रही है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि बीजिंग में बैठे कम्युनिस्ट शासकों की भारत विरोधी सोच थम नहीं रही है और वे कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे रिश्तों में खटास दूर करने की कोशिशों पर पानी फिर जाता है।

यह कम हिमाकत की बात नहीं है कि बीते अप्रैल माह की शुरुआत में ही अरुणाचल प्रदेश के तकरीबन तीस स्थानों को नया नाम देकर चीन ने इस सूबे को अपना बताने की कोशिश की। दरअसल भारत में लोकसभा चुनाव के ऐलान के कुछ दिनों के बाद चीन ने यह काम किया। अरुणाचल प्रदेश में भी चुनावों की खबर से बौखलाए चीन ने ऐसी हरकत की। वहीं बीजिंग इस बात पर भी खफा है कि मोदी सरकार ने नई पहल के तहत चीन के कब्जे वाले तिब्बत की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के आखिरी गांव को देश का सबसे पहला गांव क्यों कहा ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मौके पर जोर देकर कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के सरहद पर स्थित गांव को उनकी सरकार ने पहला गांव माना है और उसका विकास उसी के अनुसार हो रहा है। देखा जाए तो भारत सरकार जब-जब अरुणाचल प्रदेश को लेकर कोई विकास कार्यक्रम करती है या फिर सक्रिय होती है तो चीन नामकरण या फिर सूबे के किसी खिलाड़ी को स्टेपल वीजा देकर या किसी दूसरे मोर्चे पर अशांति फैलाकर अपनी नाराजगी जाहिर करता है।

सवाल यह है कि चीन की इन हरकतों का इलाज आखिर क्या है और उस पर रोक कैसे लगेगी। मोदी सरकार ने इस स्थितियों पर गंभीर विचार-विमर्श किया है और इस नतीजे पर पहुंची है कि सीमावर्ती इलाकों में विकास के कामों को तेजी लाने के साथ और सड़क कनेक्टिविटी को भी और सघन करना जारी रखा जाए। साथ ही सीमा पर सैन्य आधुनिकीकरण और उसकी तैनाती को और दुरुस्त किया जाएगा। चीन अगर अरुणाचल पर आंखें दिखाता है तो वहां विकास कार्यक्रम और बढ़ा दिए जाएंगे। साथ ही एलएसी के दूसरे हिस्सों पर भारतीय सेना की गतिविधि तथा चौकसी और बढ़ाई जाएगी जिससे बीजिंग को सख्त संदेश जाए। इसी क्रम में भारत ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर लगातार तनावपूर्ण बने हालात का आकलन किया है। भारत सरकार ने भी वहां सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया जो चीन को नागवार गुजर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय से तत्काल प्रक्रिया भी आई कि विवादित सीमा रेखा पर और अधिक सैनिकों को तैनात करने का भारत का कदम नई दिल्ली और बीजिंग के बीच तनाव कम करने के लिए अनुकूल नहीं है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने तो चीन से सीधा सवाल दागा कि एलएसी पर अमन के लिए भारत और चीन के बीच लिखित समझौते को आखिर बीजिंग ने तोड़ा क्यों। चीन ने उस संधि का कभी सम्मान नहीं किया और दूसरे देशों की संप्रभुता और अखंडता पर हमला किया और यह सवाल तो अब भी बना हुआ है। भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व संसदीय चुनावों में भी खलल डालने के मकसद से चीन अरुणाचल प्रदेश के मामले में दखलंदाजी कर रहा था। वह इस सूबे को अपना बताने में जुटा हुआ था।

जाहिर है कि अब लोकसभा चुनाव बाद केंद्र की सत्ता में काबिज होने वाली सरकार की अगली कूटनीतिक रणनीति पर चीन की नजरें रहेंगी। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने को लेकर पूरा विश्वास जता रहे पीएम मोदी ने संकेत दे दिया है कि उनकी सरकार भारत की विदेश नीति को और भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी। पीएम मोदी जब ऐसा कहते हैं तो उनका इशारा चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों की तरफ ज्यादा होता है जो भारत विरोधी गतिविधियों में जुटे रहते हैं। वहीं पीएम मोदी ने चुनावी रैलियों में कहा भी है कि यह नया भारत है और घर में घुसकर मारता है। यह सिर्फ पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयों के लिए नहीं है। इसे चीन को भी कहीं न कहीं संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए कि सीमा पर चीनी सेना ने हिमाकत दिखाई तो उन्हें न केवल खदेड़ा जाएगा बल्कि उनके खिलाफ जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा।

कहना गलत नहीं होगा कि चीन को मामले की संवेदनशीलता को समझना होगा। यह अपने आप में अहम है कि दोनों देश दुनिया की सबसे लंबी विवादित सीमा साझा करते हैं जो 3488 किमी लंबी सरहद है। यह तीन सेक्टर्स में विभाजित है- ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमा है जिसकी लंबाई 1,346 किमी है। मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सटी सीमा है जो 545 किसी लंबी है। इसके बाद वेस्टर्न सेक्टर है जो लद्दाख से सटी है जो चीन के साथ 1597 किमी लंबी सीमा साझा करता है।

लंबे प्रसार वाले इस क्षेत्र में नियंत्रण और सुरक्षा देखरेख भारत के लिए कोई मामूली बात नहीं है। वह भी तब जबकि चीन की तरफ से लगातार किसी न किसी हरकत की संभावना लगातार बनी रहती है।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

ऐसे में भारतीय सेना लगातार चौकस रहती है और चीनी सेना की तरफ से किसी भी हरकत का डटकर मुकाबला करती है। लद्दाख क्षेत्र में अक्साई चिन पर चीन से विवाद है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर भी बीजिंग अपना दावा ठोकता है।

विवाद के इतिहास में जाएं तो 2 मार्च 1963 को चीन और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5180 वर्ग किमी जमीन चीन को दे दी थी। यह तो जगजाहिर है कि पीओके में चीन किस तरह से अपनी मौजूदगी को बढ़ाता रहता है और पाकिस्तान उसमें उसकी मदद करता है। सीपीईसी को पीओके में से ले जाने की चीन की कोशिशों पर भारत के प्रहार की खबरें किसी से छिपी नहीं हैं।

उधर, लद्दाख में पेट्रोलिंग प्वाइंट को लेकर चीन विवाद उठाता रहता है। 1962 की जंग के बाद 1970 में पूर्वी लद्दाख से सटे एलएसी से भारत ने अपनी सेना हटा ली थी। उससे चीनी सैनिकों की घुसपैठ भी बढ़ गई। ऐसे में जहां सीमाएं तय नहीं थीं वहां पेट्रोलिंग प्वाइंट्स बनाए गए, जहां भारतीय सेना गश्त लगा सके। 1976 में भारत ने एलएसी पर 65 पेट्रोलिंग प्वाइंट तय किए। एक प्वाइंट काराकोरम में है तो बाकी चुमार में हैं। उन्हें पहचाना तो जा सकता है लेकिन उन्हें चिह्नित नहीं किया गया है। उनकी सीमाएं तय नहीं हैं लेकिन उनके कुछ प्रोटोकॉल हैं। कहा जाता है कि जब दोनों मुल्कों के सैनिक एक ही समय में पेट्रोलिंग के लिए आ जाएं तो प्रोटोकाल कहता है कि एक पक्ष जब दूसरे की पेट्रोलिंग टीम देख ले तो रुक जायें। ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष आपस में बात नहीं करते हैं सिर्फ एक दूसरे को पोस्टर दिखाते हैं कि आप भारत के इलाके में हैं वापस जाओ या आप चीन के इलाके में हैं वापस जाओ, लेकिन चीनी सेना ने पिछले कुछ सालों से नई हरकतें शुरू कर दीं। ऐसे मौकों पर वापस जाने के बजाए चीनी सैनिकों ने टकराव का रास्ता चुना। चीनी सरकार भले ही इसे सेना के स्तर पर हुआ टकराव बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करती रही है लेकिन इस मामले में बीजिंग में शीर्ष स्तर पर रणनीति बनी और उस पर पीएलए यानी चीनी सेना ने अमल किया। यही वजह है कि जहां औपचारिक तौर पर भारतीय सैन्य कमांडर अपने चीनी समकक्ष से बातचीत कर रहे हैं ताकि लद्दाख का मौजूदा गतिरोध दूर हो, तो वहीं भारत चीन के साथ शीर्ष स्तर पर कूटनीतिक चर्चा भी करने पर जोर देता रहा है। अब भारत ने राजनयिक स्तर पर औपचारिक बातचीत पर ब्रेक लगा दिया है क्योंकि सैन्य स्तर पर चीनी अधिकारी भारत की मांग को पूरा नहीं कर रहे जिसमें दिल्ली ने कहा था कि उसे पूर्वी लद्दाख सरहद पर अप्रैल 2020 वाली स्थिति वापस चाहिए। इससे कम पर भारत सरकार मानने को तैयार नहीं है। वहीं चीन अपना अड़ियल रवैया अपना रहा है। ऐसे में गतिरोध बना हुआ है।

भारत और चीन के बीच विवाद पैंगोंग त्सो झील पर भी है, जो लद्दाख में है। दरअसल एलएसी इस झील से गुजरती है जिसकी वजह से दोनों देशों के अपने-अपने दावे हैं जो विवाद को जन्म देते हैं। गलवान घाटी जो लद्दाख और अक्साई चिन के बीच मौजूद है, वह भी विवादित है। वहां पर एलएसी अक्साई चिन को भारत से अलग करती है। वहां 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। डोकलाम तो भूटान और चीन के बीच विवाद का क्षेत्र रहा है, लेकिन यह सिक्किम के पास होने की वजह से भारत के लिए अहम है। यह एक तरह से ट्राईजंक्शन है जहां से चीन, भूटान और भारत नजदीक है। भूटान और चीन दोनों इस पर दावा करते हैं और भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। याद करें तो 2017 में डोकलाम पर करीब ढाई महीने तक भारत और चीन के बीच गतिरोध बना हुआ था। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में तवांग पर चीन की नजरें गड़ी रहती हैं। 1914 में समझौते के अनुसार तवांग को अरुणाचल का हिस्सा बताया गया था, लेकिन 1962 की जंग में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया। फिर युद्धविराम के तहत उसे अपना कब्जा छोड़ना पड़ा था। नाथू ला हिमालय की पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम में है। भारत के लिए यह अहम इसलिए है क्योंकि यहीं से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्री गुजरते हैं। नाथू ला को लेकर यहां भी कभी कभी भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़पों की खबरें आती रहती हैं।

भारत और चीन के बीच कोई आधिकारिक सीमा नहीं रही। यही वजह है कि चीन इसका फायदा उठाकर अपनी मनमानी करता रहा है। कुछ जानकारों का मानना है कि मौजूदा सरकार का वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया पर जोर भी चीन को काफी खटक रहा है। आने वाले दिनों में इसे वह अपने आर्थिक हितों पर चोट की तरह से देख रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता निश्चित तौर पर चीन पर उसकी निर्भरता घटाएगी। भारत को अपने सामान के निर्यात से चीन भारी मुनाफा कमाता है। ऐसे में भारत सरकार की सोच है कि चीन को इस मोर्चे पर भी कमजोर किया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को आर्थिक और कारोबारी मोर्चे पर चीन को झटका देना होगा और यह रातों रात नहीं होगा। इसमें दूरगामी रणनीति ही काम करेगी। लोकसभा चुनावों के बाद बनने वाली सरकार को इस दिशा में गंभीर प्रयास करने होंगे, साथ ही उसे कठोर कूटनीतिक कदम भी उठाने होंगे।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

दावे और हकीकत से मेल नहीं खाती अर्थव्यवस्था की तस्वीर

संजय सिंह,नई दिल्ली।

भारतीय अर्थव्यवस्था काफी अच्छी हालत में बताई जाती है। भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि यदि उनकी सरकार को तीसरा मौका मिला तो वह 2027 तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित राष्ट्र बना देंगे। कुछ अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के इन दावों को हकीकत में बदलना संभव तो मानते हैं, लेकिन उसके साथ ही इस बात की ताकीद भी करते हैं कि इसके लिए सरकार को भारी मशक्कत करनी होगी और विकास दर को लगातार 8.5 फीसद से ऊपर बनाए रखना होगा जबकि पिछले दस सालों की विकास दर को देखते हुए यह बेहद कठिन काम लगता है।

कई अर्थशास्त्री इस बात की भी सलाह देते हैं कि सरकार को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मौजूदा नीतियों में कुछ बदलाव भी करने होंगे। उनका मानना है कि तेज विकास दर हासिल करने और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार ने अर्थव्यवस्था में कुछ आवश्यक सुधार किए हैं। उद्योगों को कर्ज की माफी, टैक्स में छूट के साथ कड़े श्रम कानूनों की जकड़न से मुक्त कर दिया है। इसके अलावा करोड़ों गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज के अलावा शौचालय, मकान और नल से जल, किसानों के खाते में पैसे, महिलाओं को गैस कनेक्शन भी प्रदान किए हैं, लेकिन इस सबके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई महंगाई एवं बेरोजगारी की स्थिति, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की दुर्दशा तथा आर्थिक असमानता पर सरकार लगाम लगाने में विफल साबित हुई है। इसलिए सरकार को इन मोर्चों पर तुरंत काम शुरू करना चाहिए। अन्यथा न तो तीसरी अर्थव्यवस्था किसी काम आएगी और न ही विकसित राष्ट्र बनने का कुछ लाभ होगा, क्योंकि उस स्थिति में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के बावजूद भारत गरीब ही रहेगा। इसी तरह भारत के विकसित देश बनने में भी तब तक अड़चन है जब तक कि यहां प्रति व्यक्ति आय दस गुना नहीं बढ़ जाती।

8.5
फीसद की विकास दर लगातार चाहिए भारत को 2027 में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह राय रखने और सरकार को इस तरह का मशविरा और नसीहत देने वाले विशेषज्ञों में वैसे तो कई अर्थशास्त्री शामिल हैं, लेकिन उनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दो पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव और रघुराम

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

राजन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन दोनों का कहना है कि भले ही जीडीपी के लिहाज से भारतीय अर्थव्यवस्था 2027 तक तीसरे नंबर पर पहुंच जाए, परंतु यदि ज्यादातर धन चंद अमीरों और कॉर्पोरेट्स के पास केंद्रित रहा और ज्यादातर आबादी उससे वंचित रही तो उस स्थिति में देश को कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग तब भी रोजी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। गरीबों को सहायता की जरूरत के बारे में भी दोनों के प्रायः एक जैसे विचार हैं, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हैं कि उन्हें हमेशा के लिए इस पर निर्भर बना दिया जाए। इसके बजाय वे सरकारी मदद पर निर्भर गरीबों की संख्या और सहायता की अवधि को क्रमशः सीमित करने तथा उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने पर ज़ोर देते हैं। देश की लगभग आधी आबादी को लगातार मुफ्त राशन दिए जाने को रघुराम राजन ने अनुचित ठहराया है और कहा है कि कोरोना के दौरान और कुछ समय बाद तक उन लोगों को इसकी जरूरत थी, लेकिन अब इस संख्या में कमी होनी चाहिए। इससे प्रतीत होता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है। साथ ही यह दावों और हकीकत में अंतर और विरोधाभास को भी दर्शाता है। मुफ्त राशन योजना को पांच वर्ष और बढ़ाए जाने का तो यही अर्थ हुआ कि सरकार भी मान रही है कि 2027 में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भी इतने लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत होगी। ऐसे में आरबीआई के इन पूर्व गवर्नरों के सुझावों को वास्तव में गंभीरतापूर्वक लेने की जरूरत नजर आती है।

रघुराम राजन जैसी राय तमाम विशेषज्ञों की है। उनकी मानें तो अभी भारत में प्रति व्यक्ति आय बमुश्किल 2500 डॉलर है, जबकि सबसे कमजोर विकसित देश की प्रति व्यक्ति आय भी 25000 डॉलर है। यानी हमसे 10 गुना, इसलिए विकसित देश बनने के लिए भारत को अपनी प्रति व्यक्ति आय को दस गुना न सही तो कम से कम 6-7 गुना अवश्य करना होगा। यह आसान काम नहीं है। 2027-28 तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था भले बन जाएं लेकिन प्रति व्यक्ति आय इतनी नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा यह दो गुना हो सकती है। वैसे यदि हम विकसित देशों को छोड़ दें, क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से वे हमसे बहुत छोटे देश हैं, और चीन से अपनी तुलना करें और तो वहां भी हमारी स्थिति बहुत कमजोर नजर आती है। चीन की प्रति व्यक्ति आय भी हमसे ज्यादा अर्थात 12500 डॉलर है, लेकिन इसके बावजूद चीन को अभी तक विकसित राष्ट्र का दर्जा नहीं मिला है। इसका यही कारण है क्योंकि अभी भी चीन की प्रति व्यक्ति

बेरोजगारी

गरीबी के अलावा किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का अंदाजा वहां रोजगार की स्थिति से भी लगाया जाता है, लेकिन भारत में बेरोजगारी की मौजूदा दर से ऐसा नहीं लगता कि अर्थव्यवस्था वास्तव में उतनी ही अच्छी है जितनी कि आंकड़ों के जरिए बताई जा रही है। हालांकि बेरोजगारी के सरकारी आंकड़े भी अर्थव्यवस्था की तरह ही गुलाबी हैं। सरकार का दावा है कि 2023 में देश में बेरोजगारी की दर 2022 के 3.6 फीसद के मुकाबले घटकर सिर्फ 3.1 फीसद रह गई है। ये आंकड़े नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (एनएसएसओ) की ओर से हर साल जारी किए जाने वाले पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हैं और उनके आधार पर सरकार का दावा है कि मार्च, 2020 में आई कोरोना महामारी के बाद देश में रोजगार की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। यानी सरकार स्वयं मान रही है कि वह उस दौर से तुलना कर रही है जब काम-धंधे लगभग ठप पड़ गए थे और लाखों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। वैसे भी एनएसएसओ का ही एक सर्वे यह भी कहता है कि 2016-2021 के दौरान देश की आधी आबादी की आमदनी घट गई। इसके अलावा यह सर्वविदित तथ्य है कि ज्यादातर निजी क्षेत्र में वेतन वृद्धि महंगाई के मुकाबले कम हो रही है।

स्पष्ट है कि लेबर फोर्स सर्वे के ये आंकड़े बेरोजगारी की सही तस्वीर पेश नहीं करते। सही तस्वीर उन आंकड़ों में दिखती है जो सीएमआईई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी) सीएसडीएस (सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज) और लोकनीति के संयुक्त सर्वे के जरिए और आईएलओ (इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन) की रिपोर्टों और सर्वेक्षणों के जरिए सामने आए हैं। सीएमआईई के अनुसार फरवरी, 2024 में भारत में बेरोजगारी की दर 8.0 फीसद थी, जो मार्च में मामूली कमी के बावजूद 7.6 फीसद दर्ज की गई। वहीं सीएसडीएस-लोकनीति सर्वे के मुताबिक देश के 27 फीसद लोग बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (आईएलओ) की रिपोर्ट से भी युवाओं में बेरोजगारी की स्थिति का सही अंदाजा मिलता है, जिसके मुताबिक भारत के पढ़े-लिखे युवाओं में बेरोजगारी का प्रतिशत जो 2000 में केवल 35.2 फीसद था, 2022 में बढ़कर 65.7 फीसद हो गया है।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

प्रति व्यक्ति आय और व्यय

किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का अंदाजा वहां के लोगों की आय और उसके मुकाबले किए जाने वाले व्यय से भी होता है। उस लिहाज से भी सरकारी रिपोर्टों और वास्तविक आंकड़ों में अंतर दिखाई देता है। सरकार की ओर से लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार पिछले आठ वर्षों के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में 35.12 फीसद का इजाफा हुआ है और वह 2015 के 72,805 रुपये के मुकाबले 2023 में बढ़कर 98,374 रुपये (2011-12 के स्थिर मूल्यों पर) हो गई। अर्थात 873 डॉलर से बढ़कर 1180 डॉलर। इसी तरह व्यय के बारे में सरकार (एनएसएसओ सर्वे- अगस्त, 2022-जुलाई, 2023) के आंकड़े कहते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति औसत खर्च बढ़कर 5518 रुपये (ग्रामीण 2008 रुपये, शहरी 3510 रुपये) मासिक अर्थात 66,216 रुपये वार्षिक हो गया है। एक अन्य सरकारी रिपोर्ट कहती है कि गत आठ वर्षों में घरेलू वस्तुओं पर लोगों का खर्च दो गुना होने के साथ जीवन शैली में सुधार हुआ है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खाने-पीने की बुनियादी चीजों के बजाय कपड़ों, टीवी, फ्रिज तथा मनोरंजन व घूमने-फिरने जैसी जीवन शैली से जुड़ी जरूरतों पर खर्च बढ़ा गया है। सरकार के आय और व्यय के इन आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को साल में औसतन 32158 रुपये की बचत हो रही है। यानी 30 हजार से ज्यादा बचत, लेकिन बचत का यह आंकड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी घरेलू बचत के आंकड़ों से मेल नहीं खाता। रिजर्व बैंक के मुताबिक 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण भारत में सकल घरेलू बचत दर बढ़कर 15.4 फीसद पर पहुंच गई थी। परंतु 2022-23 में वह पुनः घटकर 11.1 फीसद पर आ गई। सरकार और आरबीआई के बचत के आंकड़ों में भारी अंतर बताता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है।

आय गरीब से गरीब विकसित देश के मुकाबले कम है।

जहां एक तरफ कई अर्थशास्त्री एवं संगठन पूरी तरह अथवा कुछ शर्तों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की चमकीली व आशाजनक तस्वीर पेश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ आर्थिक विशेषज्ञों और संगठनों की ऐसी जमात भी है जो विरोधी तथ्यों के आधार पर इस तस्वीर को पूरी तरह खारिज करते हैं और आरोप लगाते हैं कि यह झूठी तस्वीर है जिसे आंकड़ों में हेराफेरी और मानकों में बदलाव कर प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार अपनी संस्थाओं के आंकड़ों के आधार पर यह तस्वीर दिखाती है। जबकि कुछ स्वतंत्र देशी-विदेशी संगठन भारत सरकार के इन्हीं आंकड़ों पर भरोसा करते हुए अर्थव्यवस्था के गुलाबी होने का सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन भारत और विदेश की ही कुछ अन्य संस्थाएं एवं स्वतंत्र अर्थशास्त्री इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। वे इसे या तो 'आधी हकीकत, आधा फसाना' अथवा पूरा फसाना बताते हैं। उनका कहना है कि सरकार के आंकड़ों में परस्पर विरोधाभास बताता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। यदि ऐसा न होता तो 2023 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) में भारत की रैंकिंग 125 देशों में 111वीं नहीं आती। यह रैंकिंग भारत को अफ्रीकी देशों की श्रेणी में रखती है जहां बड़ी आबादी को पोषण लायक भरपूर खाना उपलब्ध नहीं है और जहां बड़ी संख्या में बच्चों का वजन और लंबाई मानकों के मुकाबले कम है। यह इंडेक्स भारत सरकार के नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को झुठलाता नजर आता है, जिसके मुताबिक पिछले कुछ सालों में भारत में बहुआयामी गरीबी में लगभग 10 फीसद की कमी आई है और 2016 के 24.85 फीसद के मुकाबले 2021 में सिर्फ 14.96 फीसद आबादी बहुआयामी गरीब रह गई थी। बहुआयामी गरीबी के रूप में भारत सरकार ने गरीबी की नई परिभाषा गढ़ी है जिसके मुताबिक भारत के गरीबों में अत्यंत गरीब लोगों का प्रतिशत 47.14 फीसद से घटकर 44.39 फीसद रह गया है। साथ ही शहरों के मुकाबले गांवों में गरीबी में ज्यादा कमी आई है। यह सुधार सरकार की मुफ्त राशन योजना की वजह से आया है लेकिन सरकार के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि यदि भारत में सिर्फ 14.96 फीसद गरीब बचे हैं तो फिर सरकार देश की बड़ी आबादी को मुफ्त राशन क्यों दे रही है? उसे तो सिर्फ 14.96 फीसद लोगों को मुफ्त राशन देना चाहिए। इससे विपक्ष के उन आरोपों को बल मिलता है कि परिभाषा बदलकर सरकार ने गरीबी के नए आंकड़े तैयार किए हैं।

कुप्रबंधन के आरोप

उपरोक्त विसंगतियों के परिप्रेक्ष्य में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर के आरोपों की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रभाकर सीधे-सीधे सरकारी आंकड़ों पर सवाल खड़ा करते हैं और सरकार पर अर्थव्यस्था के कुप्रबंधन का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर वैसी नहीं है जैसी कि बताई जाती है। वे 7-7.5 फीसद जीडीपी विकास दर के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहते हैं कि नोटबंदी और खराब जीएसटी व्यवस्था लागू करने के कारण जीडीपी दर कभी भी 4 फीसद को पार नहीं कर सकी है। अर्थव्यवस्था ऐसे लोगों के हाथों में है जिन्हें इसके बारे में कुछ अता-पता नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान गई नौकरियां वापस नहीं आ पाई हैं। वे भारत में बेरोजगारी की वास्तविक दर के 12 फीसद होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

युवाओं में बेरोजगारी की दर 23 फीसद है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 35000 पदों के लिए सवा करोड़ लोग आवेदन करते हैं। बेरोजगारी के मामले में वे भारत का शुमार सर्वाधिक बेरोजगारी वाले देशों- लेबनान, सीरिया और ईरान जैसे देशों के साथ करने से नहीं चूकते और कहते हैं कि छोटे से पड़ोसी देश बांग्लादेश तक में बेरोजगारी की दर भारत से आधी है। प्रभाकर का आरोप है कि जब 2019 में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने कहा कि देश में बेरोजगारी की दर 45 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है तो सरकार ने उस संगठन को ही भंग कर दिया। प्रभाकर के अनुसार भले ही सरकार जीएसटी संग्रह से बहुत खुश है, लेकिन इससे न्यून आय वर्ग को कितना नुकसान हो रहा है, इसका उसे ज़रा भी अंदाजा नहीं है। छोटे व मझोले घरेलू उद्योगों की दशा दयनीय हो गई है। दस सालों में देश पर कर्ज में डेढ़ सौ लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में देश पर कुल 54 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था। आज यह कर्ज 205 लाख करोड़ रुपये है।

उधर, कुछ अर्थशास्त्री इस स्थिति के बावजूद 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के संकल्प को खारिज नहीं करते। उनका मानना है कि मौजूदा विकास दर जारी रही तो 2027 नहीं, तो 2030 तक भारत अवश्य तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है लेकिन उसके बाद प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने, असमानता में कमी लाने, गरीबी को पूर्णतया समाप्त करने के लिए सरकार को नीतियों में बदलाव करना होगा। इसके लिए समाज के वंचित वर्गों, गरीबों, दलितों और पिछड़ों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता में लेकर योजनाएं बनानी और चलानी होंगी। कमजोर व भूमिहीन किसानों, छोटे व्यापारियों और असंगठित क्षेत्र के उद्योगों और उनमें कार्यरत मजदूरों की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किए बगैर विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को पाना मुश्किल है।

आरबीआई का आकलन

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.4 फीसद की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। यह विश्व में सर्वाधिक है। इस दौरान विश्व की औसत विकास दर 2.9 फीसद रहेगी और भारत के बाद केवल चीन ही ऐसा देश है

जिसकी अर्थव्यवस्था भारत के बाद दूसरे नंबर पर 4.5 फीसद की दर से बढ़ेगी। बाकी कोई प्रमुख देश 2 फीसद की विकास दर भी हासिल नहीं कर सकेगा। इनमें अमेरिका, यूरोप के सभी देश, जापान, ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। आरबीआई के मुताबिक मौजूदा वैश्विक वातावरण में जहां रूस और यूक्रेन का युद्ध अनवरत जारी है, साथ ही इजराइल-हमास के बाद अब इजराइल और ईरान के बीच भी युद्ध के हालात हैं। इनसे जुड़े अनेक देश वित्तीय समस्याओं के साथ-साथ पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। खाद्य वस्तुओं की कमी के कारण हर देश में इनके मूल्यों में बढ़ोतरी देखने में आ रही है। क्रूड और पेट्रोलियम के दामों पर भी लगातार दबाव और अनिश्चितता की स्थिति बरकरार है। समुद्री व्यापार पर विद्रोही और आतंकी समूहों का साया मंडरा रहा है। ऐसे में दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों के समक्ष विकास दर को प्रभावित किए बिना महंगाई को नियंत्रण में रखने की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ब्याज दरें इतनी बढ़ चुकी हैं कि महंगाई को काबू में करने के लिए इनमें देर सबेर कमी करनी ही होगी। लेकिन इस संभावना से निवेशक परेशान हैं। उन्हें लगता है इससे विकास दर कम हो जाएगी और उन्हें नुकसान होगा, इसलिए महंगाई और विकास दोनों के हित में बेहद संतुलित कदम उठाने होंगे। कुछ भी हो, भारत की विकास दर अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर ही रहने वाली है।

जाने-माने संगठनों की राय

भारत की अर्थव्यवस्था और भविष्य को लेकर भारत सरकार और आरबीआई ही नहीं, बल्कि विश्व के जाने-माने संगठन भी बेहद आशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग की मानें तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबसे सत्ता संभाली है, तबसे लेकर अब तक 10 सालों में अर्थव्यवस्था में किए गए अनेक संरचनात्मक सुधारों के परिणामस्वरूप देश के बृहत आर्थिक बुनियादी कारक मजबूत हुए हैं। उन्हीं सुधारों की बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था जी-20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई है। वर्ष 2022-23 में उसने 9.1 फीसद तो 2023-24 में 7.3 फीसद की दर से विकास किया है, जबकि उससे पहले के दो वर्षों (2020-21 एवं 2021-22) के दौरान भी यह 7.2 फीसद की औसत दर से बढ़ी। कोरोना महामारी के कारण 2020-21 में जीडीपी दर ऋणात्मक होकर -5.83 फीसद पर जरूर आ गई थी, लेकिन 2021-22 में पुनः 9.05 फीसद पर पहुंच गई। यही नहीं, वित्त मंत्रालय के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था रोजगार भी पैदा कर रही है। इसका उदाहरण यह है कि कोरोना महामारी के झटके के बाद न केवल अर्थव्यवस्था तेजी से उभरी बल्कि, शहरी बेरोजगारी दर भी घटकर 6.6 पर आ गई। मई 2023 के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत जिस तरह 18-25 वर्ष की आयु के

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

वैश्विक संस्थानों का मत

अनेक वैश्विक संस्थाएं भी भारत सरकार के दावों की पैरवी करती हैं। उदाहरण के लिए विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए जहां वैश्विक विकास दर के 2.9 फीसद रहने का अनुमान लगाया है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.5 फीसद की दर हासिल करने की बात कही है। जहां तक 2024-25 के चालू वित्तीय वर्ष का प्रश्न है तो रूस-यूक्रेन युद्ध के लंबा खींचने के अलावा खाड़ी देशों में भी संघर्ष और उथल-पुथल के हालात के बीच विश्व बैंक को वैश्विक विकास दर के साथ ही साथ भारत की विकास दर में भी कुछ कमी आने का अंदेशा दिखाई दे रहा है। विश्व बैंक का मानना है कि 2024-25 में विकसित व विकासशील देशों की विकास दर में कुछ कमी आने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था केवल 2.4 फीसद की दर से बढ़ पाएगी, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.6 फीसद की विकास दर हासिल करने का अनुमान है।

एक अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्था डेलॉयट ग्लोबल इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर का कहना है कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में अपनी नीतियों और कदमों की बदौलत अर्थव्यवस्था को मजबूत पायदान पर ला खड़ा किया है। इसके लिए उसने लोकलुभावन नीतियों पर विराम लगाने, नोटबंदी लागू करने, एनपीए घटा कर बैंकों की बैलेंस शीट सुधारने तथा कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त वैक्सीन और राशन मुहैया कराने जैसे साहसिक कदम उठाए। कठिन समय में भारत ने विकसित देशों से कहीं ज्यादा समझदारी का परिचय दिया और दृढ़ एवं सुनियोजित फैसले लेकर देश के ज्ञान, प्रतिभा एवं क्षमता को अद्वितीय उत्पादों एवं समाधानों में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की। भारत ने न केवल तकनोलॉजी का उपयोग कर उच्च स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं स्थापित करने पर जोर दिया, बल्कि निर्यात के जरिये प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में सुधार करने में भी कामयाबी हासिल की। इन कदमों से तीन ऐसे उत्प्रेरक पैदा हुए हैं जिनसे विकास की राह तो आसान हुई ही है, अर्थव्यवस्था की बुनियाद भी मजबूत हुई है। इसी के साथ डेलॉयट ने 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.9-7.2 फीसदी या इससे भी कहीं ज्यादा दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है।

युवाओं का नया पंजीकरण लगातार 55 फीसद से अधिक दर से बढ़ा है, उससे इस बात की पुष्टि होती है।

इतना ही नहीं, आर्थिक प्रभाग ने पिछले दस वर्षों के दौरान हुए असाधारण इन्फ्रॉस्ट्रक्चर विकास को भी अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर की नजीर के तौर पर पेश किया है। उसका कहना है कि जहां आजादी के 67 वर्षों के दौरान देश में कुल 74 एयरपोर्ट बने थे। वहीं मोदी सरकार के दो कार्यकाल में एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है। सड़क और रेलवे के नेटवर्क में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, सामाजिक मोर्चे पर शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति भी बेहतर हुई है। मसलन उच्च शिक्षा को ही लें। जहां 2014 तक देश में कुल 723 विश्वविद्यालय थे, वहीं अब उनकी संख्या बढ़कर 1113 हो चुकी है। उच्च शिक्षा के लिए नामांकन कराने वालों में लड़कों की अपेक्षा अब लड़कियों की संख्या ज्यादा है। 2010 में जहां उच्च शिक्षा में नामांकन कराने वाले छात्रों का प्रतिशत 12.7 था, वहीं 2020 में यह बढ़कर 27.9 फीसद पर पहुंच चुका था। 2014 में उच्च शिक्षा में कुल 3.4 करोड़ छात्रों ने नामांकन कराया था, जबकि 2023 में नामांकन का आंकड़ा 4.1 करोड़ पर पहुंच गया। इसी तरह निजी क्षेत्र में अस्पतालों की संख्या काफी बढ़ गई है, जबकि सरकारी क्षेत्र में एम्स की संख्या 12 से बढ़कर 36 हो गई है। विशेष बात यह है कि ये उपलब्धियां तमाम प्रतिकूल हालात के बीच हासिल की गईं। इनमें कोरोना महामारी के अलावा रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां शामिल हैं, जिनके चलते वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति बाधित हुई, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने न केवल उचित कीमतों पर क्रूड खरीदने के इंतजाम किए, बल्कि घरेलू बाजार में भी डेढ़ साल तक पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रण में बनाए रखा। और तो और संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में राज्य सरकारों को एक लाख करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज भी उपलब्ध कराया, जबकि 2024 में 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण और उपलब्ध कराने का ऐलान भी किया।

वर्ष 2023 में इसमें से 97000 करोड़ से अधिक के कर्ज का राज्यों ने उपयोग किया। केंद्र सरकार ने इस कर्ज को 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता' मद के अंतर्गत 2024 के बजट में समायोजित किया। इस ब्याजमुक्त ऋण के सहारे राज्य सरकारें अपने यहां स्कूलों, ग्रामीण सडकों तथा बिजली इन्फ्रॉस्ट्रक्चर को मजबूत करने के कार्य कर रही हैं। इस कर्ज की बदौलत अप्रैल-सितंबर, 2023 के छह महीनों के दौरान राज्यों के पूंजीगत परिव्यय में 2022 की इसी अवधि के मुकाबले 47 फीसद का इजाफा दर्ज किया गया।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

अपनों को ही क्यों भूल जाना चाहती है हिंदी की बौद्धिक दुनिया

डॉ. जगन्नाथ दुबे

हिंदी समाज लगातार संवादविहीन समाज बनता जा रहा है। यह एक ऐसे समाज में परिवर्तित होता जा रहा है, जहां संवाद के लिए जगहें लगातार कम होती जा रही हैं। जिस समाज के पास वाद-विवाद-संवाद की इतनी सुदीर्घ विरासत हो, उसका यूं असंवादी होते जाना सिर्फ दुखद ही नहीं, बल्कि चिंताजनक भी है। इसे कई तरीके से समझ सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से यहां मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। साहित्य संस्कृति के मोर्चे पर एक तो यूं भी अकाल सा पड़ा हुआ है, दूसरे अगर कहीं कोई प्रयास हो भी रहा है तो उस पर हिंदी समाज ने शर्मनाक चुप्पी ओढ़ ली है।

अभी पिछले दिनों रज़ा फाउंडेशन ने हिंदी के नौ मूर्धन्य कवियों पर देशभर के करीब पचास युवा लेखकों को बुलाकर एक आयोजन किया। दो दिन तक चले उस आयोजन में स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता के नौ कवियों (धर्मवीर भारती, अजित कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजयदेव नारायण साही, श्रीकांत वर्मा, कमलेश, धूमिल, रघुवीर सहाय और राजमकल चौधरी) के बहाने हिंदी कविता के बदलते स्वभाव और स्वरूप पर भी बातचीत हुई। हिंदी समेत दूसरी भारतीय भाषाओं में भी इस तरह का यह पहला आयोजन था, जिसमें एक भाषा के इतने सारे कवियों पर पचास के करीब युवा लेखकों ने अपनी बात रखी। वह एक बेहद सफल और सार्थक आयोजन था, इसमें कोई शक नहीं, दुःख की बात यह है कि इस तरह के आयोजनों के बाद हिंदी समाज से जिस तरह की प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए वैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जिस समय में हिंदी के नाम पर बनी सरकारी संस्थाएं और लेखक संगठन खामोश हैं, उस समय में अशोक वाजपेयी और रज़ा फाउंडेशन जिस तरह हिंदी साहित्य और दूसरे कलारूपों के साथ सेतु का काम कर रहे हैं- यह बेहद महत्वपूर्ण है। जो काम लेखक संगठनों और संस्थाओं को करना चाहिए, वह काम रज़ा फाउंडेशन के माध्यम से अशोक वाजपेयी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले तीन युवा आयोजनों में प्रतिभागी के रूप में इन पंक्तियों के लेखक ने देखा है कि हिंदी साहित्य के वृहत्तर दायरे में रज़ा फाउन्डेशन जैसा लोकतांत्रिक और संवादी आयोजन अन्यत्र दुर्लभ है।

इस बार हिंदी के जिन नौ कवियों पर आयोजन हुआ, उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो विश्वविद्यालयों के सिलेबस का हिस्सा होने की वजह से अकादमिक जगत में पढ़े-पढ़ाये जाते रहे हैं, लेकिन कई कवि ऐसे हैं जिनकी चर्चा हिंदी समाज में प्रायः नहीं होती, जैसे कि कमलेश। कमलेश हिंदी कविता के एक ऐसे नाम हैं जिनसे बहुत कम लोगों का परिचय होगा, लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब दिल्ली की अकादमिक और साहित्यिक बहसों में कमलेश मुख्य किरदार हुआ करते थे। आयोजन के दौरान अशोक वाजपेयी जी ने कमलेश के तेजस्वी व्यक्तित्व के बारे में जो बातें बताईं, उनकी पुष्टि विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा तद्भव में लिखी जा रही उस श्रृंखला से भी होती है जिसमें वे सातवें दशक की दिल्ली के परिवेश के बारे में लिख रहे हैं। ऐसे ही एक कवि हैं अजित कुमार। अजित कुमार को हिंदी कविता के परिसर में बहुत कम जगह दी गयी। ऐसा क्यों हुआ? इस पर हिंदी समाज को विचार करने की जरूरत है। जिन कवियों की चर्चा हिंदी समाज में बार-बार होती रही, उनमें भी कितने कवि ऐसे हैं जिनकी कविता में मौजूद यथार्थ से हम अपने को संबद्ध कर पाते हैं? धर्मवीर भारती, धूमिल, श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और राजकमल चौधरी की चर्चा तो हिंदी आलोचना में पर्याप्त हुई है, लेकिन क्या इन कवियों के साथ हिंदी समाज का रिश्ता इतना भर बनता है कि हिंदी आलोचना ने उनका मूल्यांकन करने का कष्ट उठाया? क्या उन्होंने भारतीय समाज-राजनीति और भारतीय संस्कृति को लेकर जो प्रश्न खड़े किये, जो चिंताएं जाहिर कीं-उनकी तरफ ध्यान देने की, उन पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है? जाहिर सी बात है कि जरूरत है और यह जरुरत तब पूरी होगी जब इन कवियों की कविताओं और दूसरी विधाओं में लिखे गए उनके विचारों के आधार पर हिंदी समाज का बौद्धिक परिष्कार करने की कोशिश की जाएगी। उसके लिए सबसे जरूरी है कि उन कवियों पर बात की जाये।

श्रीकांत वर्मा अपनी कविताओं में जिस मगध और हस्तिनापुर की बात कर रहे हैं, वह मगध और हस्तिनापुर आज और ज्यादा खतरनाक रूप में हमारे सामने उपस्थित है। मगध में विचारों की कमी ने मगध को विचारहीन बनाने तक का रास्ता तय कर लिया है। धूमिल जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, वह लहूलुहान भारतीय लोकतंत्र आज किस स्थिति में है-उस पर बहस की बहुत गुंजाइश है और उसे बचाने के लिए हिंदी के बौद्धिक समाज के पास क्या रास्ता है? धर्मवीर भारती सत्ता के जिस अंधेपन की बात अंधा युग नाटक में करते हैं, वह लगातार किस तरह गहराता गया है। ऐसे में इस पर विचार करने की जरूरत है या नहीं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में जो भेड़िया दिखाई देता है, जिसकी आंखें सुर्ख लाल हैं। उस भेड़िये को मारने के लिए हमारे पास कोई हथियार है भी या नहीं? रघुवीर सहाय जिस भारत भाग्य विधाता के बारे में पूछ रहे थे, उसकी कोई शिनाख्त हमने की

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

भी या नहीं? (राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हरचरना गाता है?) भारत भाग्य विधाता मिलें या न मिलें, लेकिन हरचरना का फटा सुथन्ना और ज्यादा जर्जर अवस्था में दिखाई देता है। कितने रामदास हैं जिनका कोई मददगार इस विश्वबंधुत्व का नारा देने वाले हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देता। ऐसे में सवाल है कि हिंदी की अकादमिक और बौद्धिक दुनिया इन कवियों को क्यों भूल जाना चाहती है? क्या इसलिए कि ये हिंदी के बौद्धिक वर्ग से असुविधाजनक सवाल पूछते हैं? कारण जो भी हो, इतना तो तय है कि इन असुविधाजनक सवालों से बचकर हम नागरिक होने का धर्म नहीं निभा सकते। ऐसे सवाल पूछने वाले अपने पूर्वज कवियों पर हमें बार-बार विचार करने की जरूरत है। उनके पास जाने की जरूरत है, उनसे संवाद करने की जरूरत है। अपनी परंपरा से संवादी रिश्ता बनाकर ही कोई भी समाज आगे बढ़ता है और परंपरा निर्वात में खड़ी कोई इकाई नहीं है कि उसका नाम जपकर हम परंपरा से जुड़े रह सकते हैं। परंपरा से जुड़े होने की बुनियादी शर्त यह है कि हम अपने निकटतम अतीत से जुड़े रहें। हमारे निकटतम अतीत के ये कवि हमारे लिए किसी प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। रज़ा फाउन्डेशन ने इन कवियों पर दो दिन की जो चर्चा-परिचर्चा की, उसे आधार बनाकर हिंदी समाज को इन कवियों पर और इनके साथ ही स्वातंत्योत्तर हिंदी कविता के वृहत्तर परिसर पर विचार करने की जरूरत है। हिंदी समाज के बौद्धिक संस्कार के लिए हिंदी कविता और ये कवि उस वातायन की तरह हैं जो बाहर फैली हुई रोशनी को घर में लाने का काम करती है।

पुस्तकें

ईश्वर का दुःख

ईश्वर का दुःख हिंदी के प्रतिष्ठित कवि-आलोचक शम्भुनाथ का नया काव्य संग्रह है। हिंदी समाज में शम्भुनाथ जी की पहचान एक आलोचक की है। हिंदी आलोचना में उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण काम किया है जिसका प्रमाण हिंदी उपन्यासः राष्ट्र और हाशिया, हिन्दू मिथकः आधुनिक मन, भारत की अवधारणा और भक्ति आन्दोलन और उत्तर धार्मिक संकट जैसी पुस्तकें हैं। वे कविता की दुनिया के नए नागरिक हैं। मेरी जानकारी में यह उनका पहला काव्य संग्रह है। इस संग्रह के प्रकाशन से पूर्व कम से कम मैं तो उन्हें कवि के रूप में नहीं जानता था, लेकिन इस संग्रह की कविताओं को पढ़कर लगा कि ये एक सिद्धहस्त कवि की कविताएं हैं। एक ऐसे कवि की जिसके पास कविता का अपना मुहावरा है, कहने का अपना तरीका है, जो अपनी कविताओं में अलग से पहचान लिया जाए ऐसा कवि। पिछले दो-तीन दशकों में भारतीय लोकतंत्र ने जो रूप अख्तियार किया है उसने एक (राष्ट्र-राज्य) नेशन स्टेट के रूप में भारत के भविष्य को लेकर सोचने पर मजबूर किया है। भारत की आज़ादी, उसका लोकतांत्रिक स्वरूप और उसका संवैधानिक ढांचा जिन मूल्यों की बात करता है, उन मूल्यों को लेकर इस देश की राजनीति और राजनेता किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं- वह इसके भावी भविष्य को निर्धारित करेगा। यह संग्रह उदारीकरण के बाद बने भारत के समाज का यथार्थ दर्ज करने का काम करता है।

पिछले एक दशक में भारत की राजनीति जिस अधःपतन का शिकार हुई है, उससे हर संवेदनशील मनुष्य के भीतर एक गहरी पीड़ा पैदा हुई है। भारतीय लोकतंत्र और भारतीय राष्ट्र राज्य के मायने बदल गए हैं। हर तरफ झूठ-प्रपंच, छल-छद्म का वातावरण है। इतिहास के जो नायक हैं उन्हें विदूषक बनाने की परियोजना है, जो इतिहास और मानवता के हत्यारे हैं, वे पूजे जा रहे हैं। हर तरफ एक कुचक्र रचा जा रहा है। इतिहास को झूठा साबित करने की कोशिश हो रही है। झूठ और गप्प को इतिहास बनाने की परियोजना जोरों पर है और कहा जा रहा है कि देश बदल रहा है। इस मुश्किल दौर में शीर्षक कविता इस पूरी परियोजना का एक्सरे जैसा मालूम पड़ती है। कविता की पंक्तियां हैं, छूकर देखता हूं / इधर से उधर / पाता हूं/ यह नहीं है हमारी संसद/ यह नहीं है हमारा इतिहास/ यह नहीं है हमारा न्यूज चैनल/ इस शोर में शामिल नहीं है /हमारी आवाज / यह नहीं है हमारी भाषा/ वह जो हजारों साल से बहती/ प्रेम की नदी है। जाहिर सी बात है कि अगर यह सब हमारा नहीं है तो किनका है? इसी कविता की आरंभिक पंक्तियों में कवि यह भी बताता है कि यह सब किसका है। इस छद्म को रचने वाला कौन है? जो इस छद्म को रच रहा है उसका पहला काम है इस देश के लोगों को स्मृतिहीन करने का। ऐसा करके वह अपने मंसूबे में कामयाब हो सकता है। सत्ता संरचना के इस मंसूबे की बहुत बारीक पहचान इन कविताओं में देखने को मिलती है। इस संग्रह में कोरोना की पीड़ा से लेकर प्रकृति और मनुष्य सभी की पीड़ाएं दर्ज हैं। हिंदी समाज को इस संग्रह पर विचार करने की जरूरत है। इन कविताओं में जो राजनीतिक प्रतिबद्धता मौजूद है, वह लंबे समय तक याद रखी जाएगी।

असहमतियों के वैभव के कवि श्रीप्रकाश शुक्ल

युवा आलोचक कमलेश वर्मा के संपादन में सेतु प्रकाशन समूह से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है 'असहमतियों के वैभव के कवि श्रीप्रकाश शुक्ल'। यह किताब हिंदी के प्रतिष्ठित कवि श्रीप्रकाश शुक्ल के कवि व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर संपादित की गयी है।

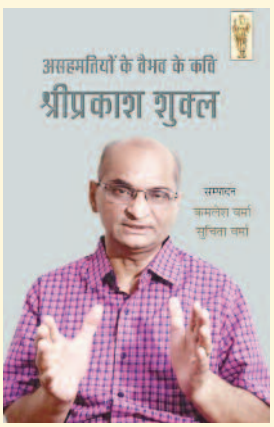

श्रीप्रकाश शुक्ल हिंदी कविता के परिदृश्य पर बीसवीं सदी के अंतिम दशक में आये। यह वही दशक है, जब एक तरफ उदार अर्थव्यवस्था अपनाई जा रही थी तो दूसरी तरफ मंडल बनाम कमंडल की बहस तेज थी। सांप्रदायिक शक्तियां अपना पांव पसार रही थीं। सोवियत संघ विघटित हो चुका था। ऐसे गहमा गहमी भरे परिवेश में एक युवा कवि हिंदी कविता में प्रवेश करता है तो उसके समक्ष भविष्य के हिंदुस्तान का जो नक्शा था, वह अस्पष्ट सा था। नई सदी का हिंदुस्तान कैसा होगा ? उसकी पहचान कर सकना और आने वाले खतरों के प्रति खुद तो सावधान होना ही साथ ही साथ हिंदी समाज को भी सावधान करना एक बड़ी चुनौती थी। आज उस घटनाक्रम के तीन दशक से भी ज्यादा बीत जाने के बाद लगता है कि उस पूरी प्रक्रिया को ठीक ढंग से समझकर जिन कवियों ने अपनी पोजीशन ली, उनमें श्रीप्रकाश शुक्ल का नाम बेहद महत्वपूर्ण है।

ग्लोबल होती जा रही दुनिया में उन्होंने लोकल के

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

महत्व को समझा और लोकजीवन की विविध छवियों को हिंदी कविता के परिसर में जगह दी। एक कवि के रूप में श्रीप्रकाश शुक्ल के महत्व पर टिप्पणी करते हुए पुस्तक के संपादक कमलेश वर्मा भूमिका में लिखते हैं, वे परम्परा को जानते हैं लेकिन परम्परावादी नहीं हैं, वे काव्यशास्त्र के गहरे अध्येता हैं लेकिन रीतिवादी नहीं हैं, वे काशी को खूब समझते हैं, मगर महिमा का पाखंड नहीं पालते। वे सिद्धांतों के जानकार हैं मगर वे ऐसे किसी विषय पर कविता नहीं रचते जिसका जीवन के स्तर पर अनुभव न रखते हों, उनकी कविताएं सिद्धांत कथन नहीं हैं।

श्रीप्रकाश शुक्ल महानगर को जीवन के स्तर पर नहीं जीते हैं, इसलिए वे महानगरीय जीवन की कविता नहीं लिखते हैं। वे जिस जीवन को जानते हैं, उसे अपनी सहमति, असहमति के साथ कविता में उतारते हैं। कहने का आशय यह कि साहित्य में जिस भोगे हुए यथार्थ को साहित्य साधना के लिए आवश्यक माना गया है श्रीप्रकाश शुक्ल उसके कवि हैं। उनकी कविता में बनारस, गाजीपुर, सोनभद्र यानी पूर्वांचल का भूगोल उपस्थित है। जीवन के सर्वाधिक वर्ष उन्होंने इन्हीं क्षेत्रों में बिताया है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर कविता की अंतर्वस्तु में उनकी उपस्थिति दिखाई देती है। लेकिन यहां यह भी ध्यान देने की बात है कि इस जिए गए जीवन के प्रति कोई अतिरिक्त मोह उनकी कविताओं में नहीं दिखाई देता। एक ख़ास किस्म का आलोचनात्मक विवेक उनकी कविताओं में मौजूद है। इधर आये दो कविता संग्रह (क्षीरसागर में नींद और वाया नई सदी) उनकी राजनीतिक रूप से मुखर कविताओं के संग्रह हैं। यह किताब उनके कवि व्यक्तित्व के इस बदलाव को भी दर्ज करने का काम करती है।

हिंदी के प्रतिष्ठित कवि अरुण कमल, मदन कश्यप से लेकर अनेक युवाओं ने श्रीप्रकाश शुक्ल के कवि व्यक्तित्व पर गंभीरता से विचार किया है। यह किताब श्रीप्रकाश शुक्ल के काव्य विकास को समझने का एक मजबूत आधार तैयार करती है।

■ जगन्नाथ दुबे, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खैर, अलीगढ़ के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।

मुहब्बत छलकती है पूनम की ग़ज़लों में

राकेश शर्मा

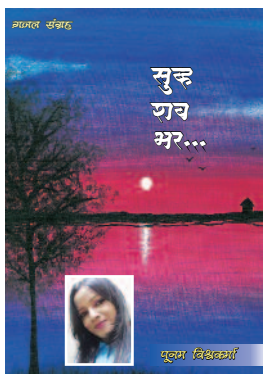

पूनम विश्वकर्मा का 'सुब्ह शब भर...' शीर्षक से जो पहला ग़ज़ल संग्रह आया है, वह प्रभावशाली और दमदार है। संग्रह की रचनाएं हवा के ताज़ा झोंके की तरह एक भीनी-भीनी खुशबू से सराबोर कर देती हैं। उनकी ग़ज़लों से मुहब्बत ही मुहब्बत छलकती है। उनकी ग़ज़लों में प्रेम के विविध आयामों का दीदार होता है। वैसे भी परंपरा से ग़ज़ल विधा का केंद्रीय विषय भी मुहब्बत ही रहा है। उसको पूनम ने बखूबी निभाया है। संग्रह के अमूमन हर शेर में परिपक्वता है। शेर कहने का उनका अपना अंदाज है, उनमें जो सलाहियत है, वह अद्भुत है। उनके कुछ शेर देखिए...

मुझमें इक डर बना रहे हो तुम, मुझको बेहतर बना रहे हो तुम।
तुमको मालूम ही नहीं शायद, मुझमें अब घर बना रहे हो तुम।

ग़ज़ल मूलतः एक गेय विधा है, जिसे लोकप्रिय होने के लिए संगीत के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। इस संग्रह में ढेर सारी ग़ज़लें हैं जिन्हें गाया जा सकता है, लेकिन अगर उन्हें तहत में पढ़ा जाए तो भी वे सुंदर और संजीदा कथ्य और ख़याल की बदौलत प्रभाव छोड़ती हैं। संग्रह के शेर ऐसे हैं कि पहली बार सुनते ही श्रोता की ज़बान पर चढ़ जाते हैं। लोगों को कंठस्थ हो जाते हैं। किसी भी नए ग़ज़लकार को अब और क्या चाहिए?

क्या कहूं किस मुसीबत में हूं, मैं खुद अपनी अदालत में हूं।
एक औरत के हूं जिस्म में,इसका मतलब हिरासत में हूं।

किसी शायर के शेर अगर पहली ही बार सुनने पर पाठक की पसंद बन जाएं तो वह शायर सफल माना जाता है। पूनम की ग़ज़लें इस कसौटी पर खरी उतरती हैं।

ग़ज़ल गायिका रूना रिज़वी कहती हैं, सुब्ह शब भर... की हर ग़ज़ल गाने लायक है। कई ग़ज़लें मैं कंपोज़ कर रही हूं। हम फीमेल सिंगर्स को पुरुष शायरों की लिखी ग़ज़लों को मंच पर गाने में अटपटा महसूस होता है,जब कभी-कभी 'करता हूं... या दीवाना हूं...' जैसे रदीफ़ प्रयोग किए जाते हैं। पूनम की ग़ज़लें गाते हुए यह दिक्कत नहीं है। शास्त्रीय गायिका पद्मश्री डॉ. सोमा घोष कहती हैं कि पूनम की ग़ज़लों में मुहब्बत की खुशबू तो है ही, लेकिन उनकी ग़ज़लें हमारे समाज में गाहे-बगाहे स्त्री के साथ होने वाले दोयम दर्जे के व्यवहार के प्रति भी एक स्त्री की चीख की तरह निकली हैं।

मैं भी इंसान हूं, ये बताया गया, पर मैं औरत हूं, ये भी सिखाया गया।

ये मकां खूबसूरत तो था पहले भी, मुझको ला कर, इसे घर बनाया गया।

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और हिंदी ग़ज़ल के शलाका पुरुष प्रो. नंदलाल पाठक संभवतः इसीलिए कहते हैं, पूनम के शेर सुनकर हर शायर मन में यही सोचता है कि काश! उस शेर के सृजक की जगह उसका नाम लिखा होता। ईमानदारी से कहूं तो मैं भी अपवाद नहीं हूं।

शायर सागर त्रिपाठी कहते हैं, पूनम के यहां ग़ज़लगोई का आग़ाज़ बेहद फ़रहतबख्श हुआ है, गोकि मुस्तक़बिल का सफ़र आसान भी नहीं है। यह ऐसी नायाब सिन्फ़ है जिसने तमाम अदबी कायनात को अपने जादुई, करिश्माई गोशे में समेट रक्खा है। ग़ज़ल के अशआर पढ़कर हैरत, मसर्रत का खुशनुमा एहसास तारी होता है, ग़ज़लगोई की पुख़्तगी क़ाबिल-ए-सिताइश है।

चूंकि पूनम पिछले दो दशक से ज़्यादा समय से फिल्मों में गीत लिखती रही हैं, उन्हें बह्र और वज़्न की समझ है, इसलिए उनकी ग़ज़लों में परिपक्वता है। वैसे इस ग़ज़ल संग्रह में शायर दीक्षित दनकौरी, गीतकार देवमणि पांडेय, शायर नवीन जोशी नवा ने भी अपनी टिप्पणियों में पूनम की काव्य प्रतिभा को सराहा है। मानवीय मन, विशेषकर महिला मन की पीड़ा और अंतर्द्वंद्व को शब्दों में पिरोने में शायरा का प्रयास सराहनीय है। उनके कुछ अशआर देखिए...

हम बेटियां तो हैं मगर इंसान ही तो हैं, सामान तो नहीं हैं हमें दान मत करो।

आ जाओ जी-हुज़ूरी से अब बाज़ तुम ज़रा, इंसां भी जो नहीं उसे भगवान मत करो

■ (समीक्षक सुप्रसिद्ध ग़ज़लकार और हिंदी ब्लिट्ज़ के पूर्व संपादक हैं।)

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

दरबार

अंकल कहीं का!

अनूप मणि त्रिपाठी

सूरज आ चुका था और आकर उनके छत पर पिछले एक पहर से विश्राम कर रहा था। वे अभी उसी छत पर मकड़ी की तरह अपने खयाल के जाले बुन रहे थे। अपने रंगे बालों में हाथ फेरते हुए वे दोपहर में नीम, गिलहरी, चिड़िया, आसमान देख रहे थे। सब में उन्हें कुछ बात नजर आ रही थी। सब में कुछ न कुछ खास होता ही है! उन्हें भान हुआ कि वे गजब के पारखी हैं। उन्होंने अपने मस्तिष्क पर जोर डाल के कुछ याद किया। 'अमंत्रं अक्षरम् नास्ति , नास्ति मूल अनौषधम् योजकः तंत्र दुर्लभः', जिसका अर्थ यही निकलता था। उन्हें लगा कि भारतीय साहित्य में उनकी तरफ से भी कुछ योगदान अवश्य होना चाहिए। उनके मुख से कविता टाइप कुछ फूटने ही वाला था कि 'अंकल! अंकल!' की आवाज ने अभी-अभी जन्मने वाले कालजयी साहित्य को असमय ही काल कवलित कर दिया। इस वियोग में उनके मुंह से अपने लिए 'आह!' निकली और उस बच्चे के लिए 'गान' जिसने उनके 'बको ध्यानं' को भंग कर दिया था।

'अंकल पतंग!' उस बच्चे ने गुहार लगायी। उन्होंने देखा कि एक दोरंगी पतंग उनके श्री चरणों मे गिरी हुई है। ठीक उसी तरह से जैसे मुहावरे की भाषा में कहते हैं कि सफलता उनके कदम चूम रही थी। ओह! तो मैं प्रकृति प्रेम में इतने गहरे उतर गया था कि पतंग मेरे पैरों पर कब से गिरी पड़ी है और मुझे पता भी न चला। यह सोच कर वह खुद पर रीझ गए कुछ वैसे-जैसे फूलों से लदा नेता अगले दिन अखबार में अपनी तस्वीर देख कर होता है।

'अंकल अंकल पतंग!' बच्चे ने फिर आवाज लगायी। उन्होंने मुलमुलाई आंखों से बच्चे को देखा। मरगिल्ला- सा। मगर चौकन्ना। गेहुंए रंग का। मैले कपड़े। बाल बड़े, बिखरे हुए। बमुश्किल तेरह-चौदह का होगा! उन्होंने गेस किया। फिर ठंडी सांस छोड़कर अपनी नजरें घुमा लीं। मगर वह बच्चा लगातार पतंग के लिए जान दिये जा रहा था। वे झुके। पतंग को पकड़ा। उठे। इस बीच लड़के ने फिर आवाज लगाई 'अंकल दे दीजिये न! अंकल!' यह क्या! पतंग को उन्होंने हाथों से छोड़ दिया। पतंग बल खाकर छत पर पुनः उनके श्री चरणों में आ गिरी। जैसे चुनाव के बाद जनता की उम्मीदें। बच्चा कसमसा कर रह गया। वे मुस्कुराए।

लड़का छत के नीचे, वे छत पर और उन दोनों के बीच दोरंगी पतंग। बीच-बीच में हवा कुछ तेज हो जाती थी और बीच-बीच में 'अंकल! अंकल!' करते लड़के की आवाज भी। कुछ सोचकर उन्होंने बच्चे पर ध्यान न देने की ठानी। वे इधर-उधर दूसरी छतों पर देखने लगे। तितलियां नहीं दीख रहीं। कोई बाल भी नहीं सुखा रही आज! वे खुद से बोले। उधर लड़का 'अंकल अंकल' की रट लगाए जा रहा था। तभी उन्हें सामने की छत पर कोई दिखा, जिसके हाथ में प्लास्टिक की बाल्टी थी। उन्होंने किसी एग्जिट पोल की तरह पहले ही नतीजा बता दिया कि बाल्टी में क्या और कितना होगा!

अभी वह किसी नतीजे पर पहुंचते कि 'अंकल अंकल!' की आवाज ने उनके चिंतन में खलल डाल दी। इस बार वह लड़का लगातार बोले जा रहा था। मगर उनका दिल नहीं पसीजा। उन्होंने लड़के को एक नजर भी न देखा। उन्होंने तो बस यह देखा कि किसी की नजरें उनसे अभी-अभी टकराई हैं। वह बड़बड़ाती हुई पैर पटकते सीढ़ी से नीचे उतर गयी। यह देखकर वे मुस्कुराए। हालांकि उनकी उस महीन मुस्कुराहट को देखने वाला वहां कोई नहीं था। सिवाय उस कौवे के जो उस वक्त नीम पर बैठा था। उस वक्त उन्होंने यही सोचा।

यकायक उन्हें कुछ कमी महसूस हुई। उन्होंने मुड़कर देखा कि पतंग मांगने वाला लड़का मंजर से गायब है। वह जा चुका था। उन्होंने विजेता की तरह इधर-उधर देखा, मगर वहां कोई ऐसा न था जो उन्हें चुनौती दे सके। वे अजेय थे। अपराजित थे। उन्होंने पतंग को ऐसे उठाया जैसे अपनी विजय पताका उठायी हो! अभी वे उसे कहीं संभालकर रखने ही जा रहे थे कि 'भइया! भइया पतंग!' की आवाज उनके कानों से टकराई। उन्होंने देखा कि अब एक दूसरा बालक उनसे पतंग की गुहार कर रहा है। 'भइया! भइया!' वह हाथ हिलाकर पतंग की ओर इशारा कर रहा था। वे हंसे और पतंग को नये बच्चे की ओर लहरा लिया। पतंग जैसे-जैसे जहां-जहां डोल रही थी, बच्चे की आंखों की पुतलियां भी वैसे-वैसे वहां-वहां डोल रही थीं। जैसे पंतग पर बच्चे की आंखें चिपक गयीं हों! कुछ देर में ही पतंग की डोर बच्चे के हाथों में थी। वह बिजली की तरह सड़क से कुलांचे भरता हुआ गली में घुस गया।

'तू जीत गया भाई!' बच्चे ने पतंग देते हुए एक बच्चे से कहा। यह वही बच्चा था जो अभी अपने मिशन से नाकाम हो कर लौटा था।

'मान गये बेटा! क्या काटा है तूने!' अपने मित्र के कौशल पर वह मुग्ध था।

वह कुछ न बोला। बस मुस्कुरा कर पतंग को जीभर कर देखे जा रहा था। लड़का पतंग लेकर वापस सड़क पर पहुंचा। पीछे-पीछे उसका दोस्त भी।

वे छत से नीचे उतर ही रहे थे कि 'भइया!' की आवाज पर वे चौंके। पलट कर देखा। अरे यह तो वही बच्चा है! पतंग उसके हाथों में कैसे! अभी वे कुछ समझ पाते कि पतंग को हवा में ठुनकी देते 'अंकल कहीं का' कह कर बच्चा जोर से हंसा। जैसे-जैसे पतंग उनकी छत से ऊपर जा रही थी, वैसे-वैसे उनका मुंह और वे दोनों उतर रहे थे...।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

राजनीति में भी कम जलवा नहीं रहा है खिलाड़ियों का

रत्ना श्रीवास्तव, नई दिल्ली।

देश में इन दिनों लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। चुनावों में हर वर्ग और हर पेशे के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, इससे भी बेहतर क्या हो सकता है। हमारे देश में जनप्रतिनिधियों की बात करें तो उनमें अगर खांटी नेता होते हैं तो बॉलीवुड और खेल जगत के लोगों ने भी राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। यह अलग बात है कि खेल से जुड़ी हस्तियां राजनीति में कम ही रही हैं, लेकिन उनकी भागीदारी तो रही ही है और अब भी है। देश की आजादी से पहले और बाद में भी राजनीति के दरवाजे पर खिलाड़ियों की दस्तक होती रही है। दरअसल खिलाड़ी वैसे भी लोगों के चहेते होते ही है और उनकी लोकप्रियता जल्दी ही कम नहीं होती ,लिहाजा इसे अब सियासी दल भी जरूरत के लिहाज से खिलाड़ियों की चमक को राजनीति के मैदान में भुनाने से पीछे नहीं हटते। वे कई बार उन्हें अपने दल के टिकट भी देते हैं और उनके संसद तक पहुंचने का जरिया भी बनते हैं।

पलवंकर बालू

देश में वैसे तो बहुत से खिलाड़ियों ने चुनाव लड़ा है। कुछ चुनकर विधानसभा में पहुंचे तो कुछ लोकसभा में और कुछ ने राज्यसभा में उपस्थिति दर्ज कराई। उनमें से कुछ तो सारे दांवपेच में माहिर होकर खांटी नेता भी बन गये। कुछ खिलाड़ी जीतने के बाद मंत्री भी बने। हालांकि ऐसे खिलाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं रही है। आमतौर पर एक खिलाड़ी का सियासी करियर तब शुरू होता जब वह सक्रिय खेल जीवन को अलविदा कह चुका होता है। वैसे सियासी जगत में अपने नामों को चमकाने वाले खिलाड़ी भी अपने खेल करियर में नामी गिरामी ही रहे हैं। कुछ ओलंपियन, कुछ पदक विजेता और कुछ देश के स्टार खिलाड़ियों ने राजनीति में भी खास मुकाम हासिल किया। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी दिग्गज क्रिकेटर रह चुके कीर्ति आजाद और युसुफ पठान तृणमूल कांग्रेस की ओर से पश्चिम बंगाल में अपना भाग्य आजमा रहे हैं।

रिकॉर्ड बताता है कि 1937 में एक क्रिकेटर ने बांबे संविधान सभा के चुनावों में भीमराव अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उनका नाम अब ज्यादातर लोग भूल चुके हैं। बात भी आखिर करीब 90 साल पुरानी हो गई। उनका नाम पलवंकर बालू था, वे संभवतः राजनीति में दस्तक देने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। 1890 के दशक में बालू जबरदस्त तेज गेंदबाज के रूप में पहचान बना चुके थे। वह दलित वर्ग से थे, लिहाजा उन्हें छुआछूत का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वह जिस टीम के खिलाफ खेलते, उसकी बैटिंग को तहसनहस कर देते। उन दिनों बाल गंगाधर तिलक ने एक समारोह में उनका सम्मान भी किया था। बालू की गेंदबाजी पर ब्रिटिश अखबारों में लेख लिखे जाते थे। उनकी तुलना महान ब्रिटिश गेंदबाजों से की जाती थी।1907 से लेकर 1911 तक खेले गए पांच मैचों में उन्होंने 40 विकेट लिए और हर विकेट के लिए उन्होंने 10 से भी कम रन खर्च किए। बीआर अंबेडकर भी उनके चहेतों में थे। कांग्रेस ने उन्हें 1937 में मुंबई संविधान सभा के चुनावों में अंबेडकर के खिलाफ खड़ा कर दिया। चुनाव टक्कर का हुआ। वह हारे तो लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं मात्र 2,025 वोट का था।

एक और हॉकी खिलाड़ी का नाम भी उसके बाद के दौर में चर्चा में आया। वह हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी थे। आदिवासी समाज से आते थे और नाम था जयपाल सिंह मुंडा। वह भारतीय राजनीतिज्ञ और लेखक भी थे। वह उस संविधान सभा के सदस्य थे जिसने भारतीय

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी बनाकर 1952 के चुनावों में हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि बिहार विधान सभा में 32 सीटें भी जीतीं। 1962 में उनकी पार्टी ने 20 सीटें जीतीं।

संघ के नये संविधान पर बहस की थी। उन्होंने एम्स्टर्डम में 1928 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फील्ड हॉकी टीम की कप्तानी की थी। बाद में वह आदिवासियों के हितों और मध्य भारत में एक अलग पहचान के लिए एक प्रचारक के रूप में उभरे। भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने पूरे आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाया। जयपाल सिंह मुंडा को प्रमोद पाहन के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म तीन जनवरी, 1903 को बंगाल के तत्कालीन रांची जिले के खूंटी उपखंड में एक मुंडा आदिवासी परिवार में हुआ था। बचपन में वह मवेशियों की देखभाल करते थे। उन्होंने बहुत कम उम्र से ही असाधारण नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया था। मिशनरी के लोग उन्हें पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ले गए जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में ऑनर्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

हॉकी में वह डीप डिफेंडर की पोजिशन पर खेलते थे। बाद में वह कोलकाता के मोहन बागान क्लब से जुड़े। बंगाल हॉकी एसोसिएशन के सचिव भी रहे। खास बात ये भी है कि सिंह को भारतीय सिविल सेवा में काम करने के लिए चुना गया, जिससे बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सिंह 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस से अलग राज्य झारखंड बनाने की जरूरत पर चर्चा की। बाद में झारखंड पार्टी बनाकर 1952 के चुनावों में हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि बिहार विधानसभा में 32 सीटें भी जीतीं। 1962 में उनकी पार्टी ने 20 सीटें जीतीं। वे बिहार में बिनोदानंद झा की सरकार में मंत्री बने। 1963 में अपनी पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया। 20 मार्च 1970 को नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मस्तिष्क रक्तस्राव से उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह देखें तो आदिवासी समुदाय से आने वाले दो खिलाड़ियों ने भारतीय राजनीति में सबसे पहले कदम रखा था। उसके बाद से अब तक भारतीय राजनीति में तमाम क्रिकेटरों और हॉकी के खिलाड़ियों ने पहचान बनाई, जिनमें कुछ पदक विजेता ओलंपियन भी हैं।

खिलाड़ियों की बात करें तो असलम शेर खान एक चर्चित नाम हैं। वे हॉकी के जबरदस्त खिलाड़ी और ओलंपियन भी थे। बैतूल से 1984 के चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए और चुनाव भी जीते। फिर केंद्रीय मंत्री भी बने। हालांकि बाद में पार्टी बदलकर भाजपा में चले गए और फिर भाजपा से

हॉकी खिलाड़ी असलम शेर खान कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने और केंद्र सरकार में मंत्री भी बने

कांग्रेस में आ गए। अपनी पार्टी भी बनाई लेकिन उसमें उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। असलम शेर खान ने मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा सीट से चार बार चुनाव लड़ा था, जिसमें दो में जीते और दो चुनाव हारे। श्री खान ने 2004 में भोपाल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और 2009 में सागर से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, दोनों बार उन्हें शिकस्त मिली। वे अब 70 साल के हैं और राजनीति से करीब-करीब किनारे हो चुके हैं।

भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान परगट सिंह ने 2016 में हॉकी से संन्यास लेने के बाद पंजाब की राजनीति में अकाली दल की ओर से एंट्री ली लेकिन जब उन्हें पार्टी ने सस्पेंड कर दिया तो वह कांग्रेस में चले गए। उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। जीते और फिर मंत्री

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

परगट सिंह

संदीप सिंह

भी बने। इसी तरह मशहूर ड्रैग फ्लिकर संदीप सिंह ने हरियाणा से राजनीति की शुरुआत करते हुए चुनाव लड़ा। जीते तो हरियाणा में खेल मंत्री बनाए गए लेकिन उनका सियासी करियर एक महिला कोच के यौनशोषण के आरोपों के बाद लड़खड़ा गया। उन पर बॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है। भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान प्रबोध तिर्की का अनुभव राजनीति में जरूर बहुत अच्छा नहीं रहा। उन्होंने पिछले साल भारतीय कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए इंडियन एयरलाइंस की अपनी अच्छी नौकरी छोड़ दी थी। कांग्रेस ने इस बार के चुनावों में पहले तो उन्हें ओडिशा की तलसारा विधानसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया लेकिन दूसरी सूची में उनका नाम काट दिया गया। अपने साथ हुए इस सलूक से वह खिन्न हैं, लेकिन ये भी सियासी खेल है, जो वहां अक्सर खेला जाता है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष रहे भारत के पूर्व कप्तान दिलीप टिर्की बीजू जनता दल से 2012 से 2018 तक राज्यसभा सदस्य रहे। उन्होंने 2014 में सुंदरगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। 2019 में उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। अबकी बार वे फिर बीजेडी से सुंदरगढ़ से लोकसभा उम्मीदवार हैं।

ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह ने 2019 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी। उन्हें साउथ दिल्ली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, लेकिन हार गए। अबकी बार कांग्रेस उन्हें मथुरा से भाजपा प्रत्याशी हेमामालिनी के खिलाफ टिकट देना चाहती थी लेकिन उन्होंने वहां से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। साथ ही उन्हें उनके घरेलू नगर भिवानी से टिकट की मांग नहीं मानने पर वह कांग्रेस से नाराज हो गए। अब पार्टी छोड़कर भाजपा में जा चुके हैं। विजेंदर ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था।

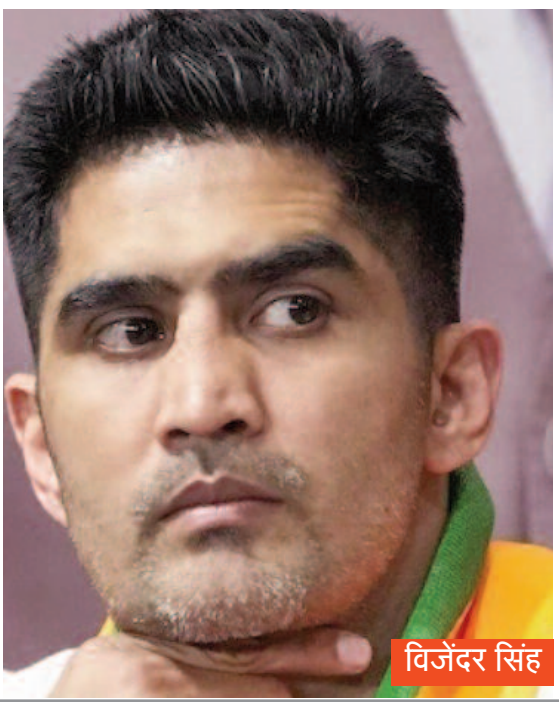
विजेंदर सिंह

महाराजा बीकानेर डॉ. करणी सिंह गजब के निशानेबाज थे। उन्होंने 1960 से लेकर 1980 तक ओलंपिक शूटिंग में शिरकत की। कई वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में खेले। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। वह 1952 से लेकर 1977 तक कांग्रेस के टिकट पर लड़कर लोकसभा पहुंचते रहे। राजस्थान के ही शूटिंग ओलंपियन और वर्ष 2004 के एथेंस ओलंपिक में डबल ट्रैप निशानेबाजी में सिल्वर मेडल जीतने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सेना में अफसर थे, लेकिन उन्होंने सेना से अवकाश लेकर राजनीति में आने का फैसला किया। 2013 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। कर्नल राठौड़ ने विभिन्न चैंपियनशिप में 25 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते। उन्होंने भाजपा के टिकट पर 2014 में पहला लोकसभा चुनाव जीता। फिर 2019 में दूसरी बात जीते। वह जयपुर ग्रामीण से सांसद रहे। केंद्र सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री के अलावा युवा मामलों और खेल महकमे के केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन उसके बाद भाजपा ने उन्हें पिछले साल राजस्थान विधानसभा चुनावों में झोटवाड़ा सीट से चुनाव लड़ाया, जिसमें वे बड़े अंतर से जीते। कह सकते हैं कि भाजपा के भीतर उनका कद गिरा है लेकिन एक कुशल सियासी खिलाड़ी की तरह वह चुपचाप अपनी बेहतर पारी का इंतजार कर रहे हैं। पैरालंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली दीपा मलिक 2019 में भाजपा में शामिल हुईं। उन्हें उम्मीद थी कि चुनाव में भाजपा से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है।

डिस्कस थ्रो एथलीट और दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल (2010) में स्वर्ण पदक प्राप्त कृष्णा पुनिया को राजनीति में कांग्रेस का साथ रास आया। उन्होंने 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में सादुलपुर(चूरू) से चुनाव लड़ा और विधायक निर्वाचित हुईं। हालांकि उसके अगले साल जब वह 2019 के लोकसभा चुनाव में जयपुर ग्रामीण सीट पर राज्यवर्धन राठौड़ का मुकाबला करने उतरीं तो चुनाव हार गईं। मध्यम दूरी की धाविका ज्योतिर्मय सिकदर ने भारत के लिए 800 मीटर में कई पदक जीते थे। वह पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुईं और 2004 में कृष्णानगर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

कृष्णा पुनिया

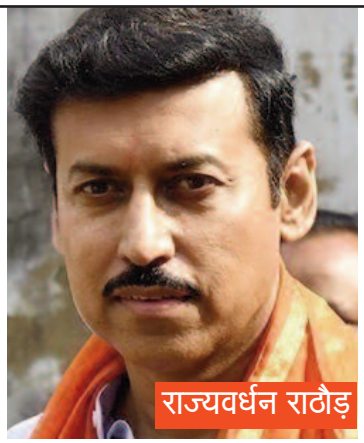
राज्यवर्धन राठौड़

बनीं, लेकिन उसके बाद अगले चुनाव में वह हार गईं। फिर वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गईं और अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं। राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज कलिकेश नारायण सिंह देव ओडिशा के बीजद (बीजू जनता दल) पार्टी से दो बार लोकसभा सांसद बन चुके हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रसून बनर्जी वर्ष 2014 में हावड़ा सीट से जीतकर तृणमूल कांग्रेस से सांसद बने थे। दो बार की तैराकी चैंपियन नफीसा अली ने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई। वह राजनीति के रण में भी उतरीं। 2004 में वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुईं। 2009 में सपा से चुनाव लड़ीं, लेकिन जीत नहीं पाईं। वे फिलहाल कांग्रेस में हैं। भारतीय स्टार शटलर साइना नेहवाल ने कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भालाफेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया को इस बार राजस्थान की चूरू सीट से टिकट दिया है।

राजनीति में क्रिकेटरों की आमद पर बात करें तो यह ही वह खेल है, जिससे सबसे ज्यादा लोगों ने इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। कई क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है। जीता है और मंत्री भी बने हैं। कुछ तो चर्चित नेता के तौर पर भी सुर्खियों में आए। वैसे इस बार दो बड़े क्रिकेटर जो चुनाव मैदान में हैं, उनके नाम कीर्ति आजाद और युसुफ पठान हैं। कीर्ति आजाद ने भाजपा से अपने सियासी करियर की शुरुआत की। फिर कांग्रेस में गए और तृणमूल कांग्रेस की ओर से 2024 के लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर लोकसभा सीट से मैदान में हैं। आजाद भाजपा उम्मीदवार के रूप में 1999, 2009 और 2014 के आम चुनाव में बिहार की दरभंगा सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ मुखर होने का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और वर्ष 2015 में भाजपा ने श्री आजाद को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया। फरवरी 2019 में श्री आजाद कांग्रेस में शामिल हो गये। इस साल लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल दलों के साथ सीटों की साझेदारी के तहत उन्हें दरभंगा से टिकट नहीं मिल सका। यह सीट राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के हिस्से में चली गयी। इससे पूर्व के चुनाव में कांग्रेस ने उनको झारखंड की धनबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, जहां से वह चुनाव हार गये। उनकी लगातार जीत का सिलसिला यहीं थम गया, लेकिन हार के बावजूद आजाद का जलवा कम नहीं हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ने बहरामपुर संसदीय सीट से क्रिकेटर यूसुफ पठान को अपना उम्मीदवार बनाया है।

वैसे पश्चिम बंगाल में मशहूर क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी अपने राजनीतिक कॅरियर की शुरुआत तृणमूल कांग्रेस से की है। वह राज्य सरकार में फिर मंत्री भी बने। शुक्ला ने 2016 में राज्य के हावड़ा उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा तथ भाजपा की उम्मीदवार रूपा गांगुली को पराजित किया। इसके अलावा आईपीएल स्टार और क्रिकेटर मनोज तिवारी भी तृणमूल से जीतकर विधायक हैं।

क्रिकेट के अलावा अनूठी शैली की टीवी क्रिकेट कमेंट्री से लोकप्रिय होने वाले नवजोत सिंह सिद्धू कई साल खांटी नेता के रोल में रहे, लेकिन इस बार वह चुनावों से बिल्कुल दूर हैं और आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं। सिद्धू ने लोकसभा चुनाव में जीत की तिकड़ी लगाई थी। फिर वह विधानसभा चुनाव में जीतकर मंत्री भी बने। वह पहली बार पंजाब की अमृतसर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। एक मामले में तीन साल की सजा होने के बाद उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। निचली अदालत के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी, जहां से उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी गयी। फरवरी 2007 में ही अमृतसर सीट के लिए उपचुनाव हुआ, तब सिद्धू फिर जीते। वर्ष 2009 के आम चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की। अप्रैल 2016 में उन्हें राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया। कुछ महीने बाद उन्होंने राज्यसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया। जनवरी 2017 में वह कांग्रेस में शामिल हो गये। अमृतसर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने, लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रदेश नेताओं से उनकी खींचतान

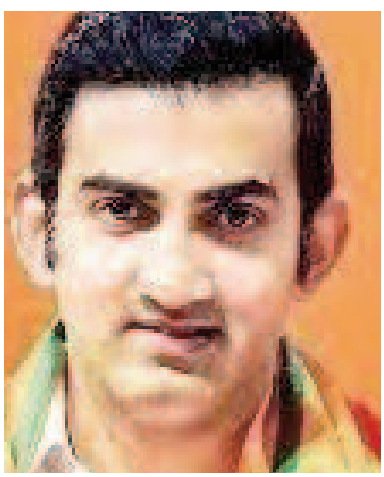

काफी चली। उन्हें कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया. इसके बाद जब वह एक साल की जेल की सजा काटने गए तो सियासत ने भी उन्हें हाशिए पर फेंक दिया। अब सिद्धू फिर से सियासत में उतरेंगे या नहीं ये भविष्य के गर्भ में है। देश के एक और दिग्गज क्रिकेटर गौतम गंभीर वर्ष 2011 में वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य थे। कोलकाता

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

नाइट राइडर्स के कप्तान के रूप में उन्होंने खूब धूम मचाई। वर्ष 2019 में वह भाजपा के टिकट पर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सीटे। हालांकि अबकी बार वह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। रणजी ट्राफी में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहसिन रजा को भी सत्ता का स्वाद चखने को मिला। रजा 2014 में भाजपा में शामिल हुए। दूसरे ही साल पार्टी के प्रवक्ता बनाये गये। 2017 में जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुआई में भाजपा सरकार बनी तो वह मंत्री बने। हालांकि दूसरे टर्म में जब फिर योगी सरकार जीतकर वापस आई तो वह किनारे कर दिए गए।

रेडियो पर 80 के दशक में जिसने भी कमेंट्री सुनी होगी, उन्हें याद होगा कि किस तरह भारतीय क्रिकेट टीम की बैटिंग जब शुरू होती थी तो सुनील गावस्कर के साथ चेतन चौहान दमदार सलामी पार्टनर की भूमिका निभाते थे। उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद राजनीति में कदम रखा। 1991 और 1998 में वह अमरोहा सीट से सांसद चुने गए। हालांकि वह वहां से 1996, 1999 और 2004 का चुनाव हारे भी। इसके बाद वह 2017 में विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। फिर उत्तर प्रदेश के खेल और युवा मामलों के मंत्री बने। 2020 में वह कोविड की चपेट में आ गए। अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।

मोहम्मद अजहरुद्दीन भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज कप्तान रहे। बाद में मैच फिक्सिंग ने उनके करियर को न केवल कलंकित किया बल्कि उनके करियर पर भी फुल स्टॉप लग गया। हालांकि बाद में वह मुकदमा लड़कर कोर्ट से बेदाग हो गए। अजहरुद्दीन ने 2009 में मुरादाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और जीते, लेकिन अगले चुनाव में वह हार गए। कुछ समय पहले तेलंगाना विधानसभा चुनावों में भी वह खड़े हुए थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। मनोज प्रभाकर ने भी 1996 में कांग्रेस-एनडी तिवारी की ओर दिल्ली साउथ से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। पंजाब से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले अश्विनी मिन्ना ने वर्ष 2014 में भाजपा की ओर से करनाल सीट पर चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद बन गए। अंडर19 में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले और इस आयु वर्ग में भारतीय टीम के मेंबर रंजीब बिश्वाल कांग्रेस के टिकट पर ओडिशा की जगतसिंह सीट से तीन बार 1996,1999 और 2014 में जीते।

भारतीय क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले और शारजाह के क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में आखिर गेंद पर जावेद मियांदाद के हाथों छक्का खाने वाले चेतन शर्मा बाद में टीवी में विश्लेषक के तौर पर खूब नजर आते रहे। वह भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य सेलेक्टर भी बने। चेतन शर्मा ने 2009 में बीएसपी के टिकट पर फरीदाबाद से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। क्रिकेटर मोहम्मद कैफ चुनावी पारी के लिए 2009 में कांग्रेस के टिकट पर फूलपुर लोकसभा सीट से मैदान पर उतरे थे लेकिन चुनाव हार गए। हिमाचल प्रदेश की ओर से एक रणजी मैच खेलने वाले अनुराग ठाकुर 1998 से हिमाचल के हमीरपुर से बीजेपी सांसद हैं। साथ ही मौजूदा मोदी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। हरभजन सिंह को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा है।

अंत में-तीन ऐसे क्रिकेटरों की बात जो दिग्गज तो रहे। राजनीति में भी रहे, बहुत लोकप्रिय भी रहे लेकिन सियासी पिच पर बहुत कामयाब नहीं रहे। महाराजा बड़ौदा फतेहसिंह गायकवाड़ ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। बीसीसीआई के प्रेसीडेंट भी रहे। वह 1957, 1962, 1971 और 1977 में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे। वह अकेले क्रिकेटर हैं, जो चार बार सांसद रहे। इसी तरह डॉ. विजय आनंद विजी जो विजयनगरम के महाराजा थे और 1930 के दशक में भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई तो वो उसके कप्तान थे। हालांकि एक खिलाड़ी के तौर पर उनकी जगह पर हमेशा सवाल उठते रहे। ये वही थे, जिनके कारण लाला अमरनाथ को इंग्लैंड दौरे के बीच से ही वापस भेज दिया गया था। हालांकि बाद में क्रिकेट कमेंटेटर के तौर पर वह बहुत लोकप्रिय हुए। विजी ने विशाखापट्टनम से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर 1962 में चुनाव लड़ा और सफल रहे। इस कड़ी में तीसरा नाम मंसूर अली खान पटौदी का है, जो भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ कप्तान और जोरदार बल्लेबाज थे। उनकी स्टाइल का जवाब नहीं था। बाद में उन्होंने अपने जमाने की मशहूर हीरोइन शर्मिला टैगोर से शादी रचाई, जो उस समय की चर्चित शादी थी। पटौदी ने दो बार चुनाव लड़ा। वह हरियाणा में मौजूद पटौदी रियासत के नवाब थे। उन्होंने 1971 में अपनी पार्टी वीएचपी बनाई, यानी विशाल हरियाणा पार्टी। वह पटौदी से उस पार्टी के उम्मीदवार बने। सारी कोशिश के बाद भी हार गए। उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें बीस साल बाद भोपाल से चुनाव मैदान में उतरने का मौका दिया, पर वह फिर हार गए।

1971 में मंसूर अली खान पटौदी का चुनावी मुकाबला हरियाणा के घाघ राजनीतिज्ञ बंसीलाल से था। गुड़गांव (अब गुरुग्राम) में बंसीलाल ने अपने चुनावी भाषण में कहा, ठीक है आप पटौदी को वोट देना चाहते हैं, उन्हें जिता देंगे तो क्या होगा। पहले तो आपको उनसे मिलने के लिए स्टेडियम में जाना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि देश के क्रिकेट स्टेडियम में घुस पाना कितना मुश्किल है। चलिए मान लेते हैं कि आप वहां भी पहुंच गए। किसी तरह पटौदी से मिल भी लिये, लेकिन वे आपको देंगे क्या... ज्यादा से ज्यादा बैट और बल्ला। बंसीलाल के उस भाषण का चुनाव पर बड़ा असर हुआ था।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

कार्ल मार्क्स : पति, पत्नी और 'वो'

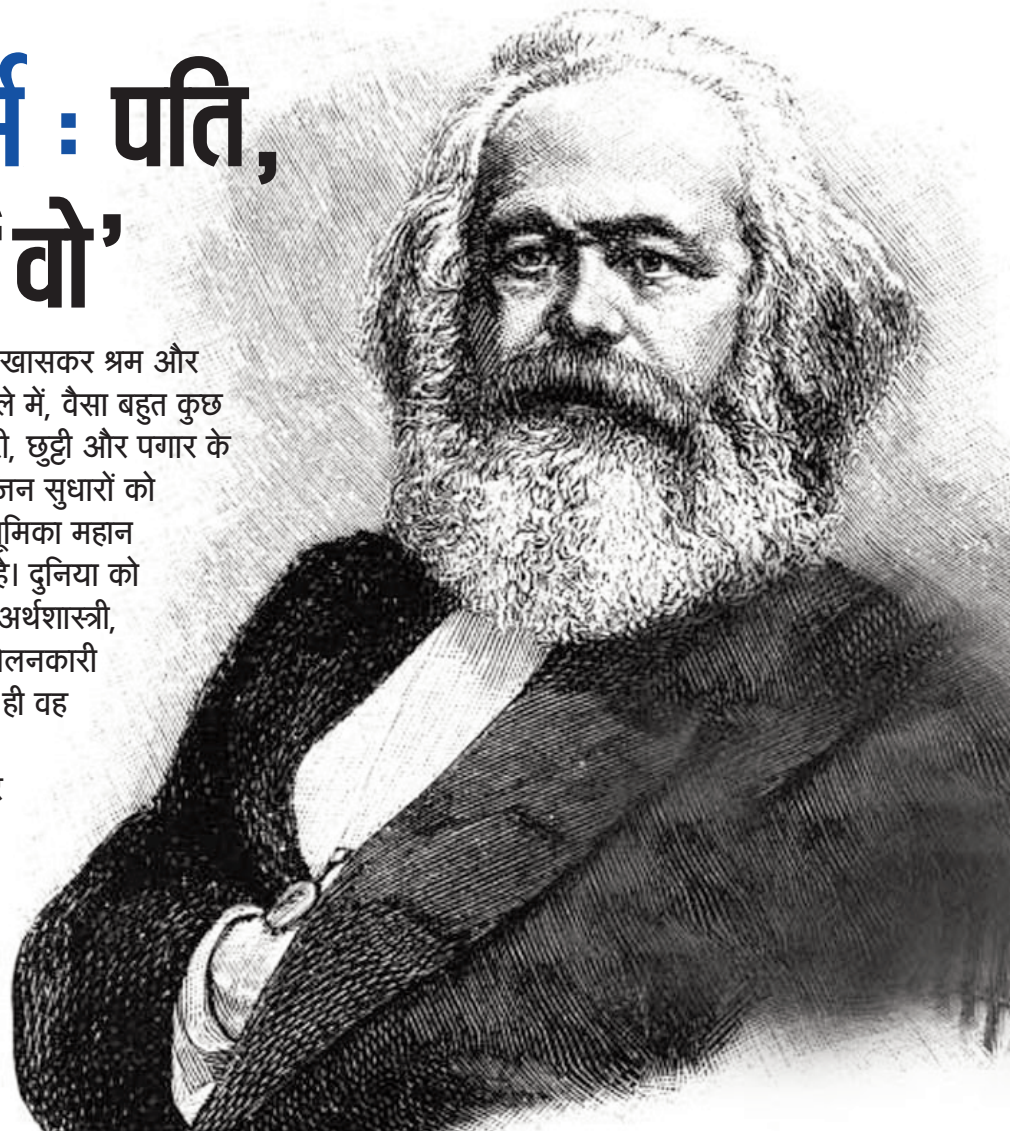

दुनिया को हम आज जैसा देखते हैं, खासकर श्रम और मजदूरों की स्थिति में सुधार के मामले में, वैसा बहुत कुछ पहले था ही नहीं। माजदूरों की नौकरी, छुट्टी और पगार के मामले में पिछले 100 सालों में हुए जिन सुधारों को आज हम देखते हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका महान समाज विज्ञानी कार्ल मार्क्स की भी है। दुनिया को बदलने वाले महान दार्शनिक, महान अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, लेखक, पत्रकार, आंदोलनकारी और साम्यवादी भी। इस सबके साथ ही वह रोमांटिक प्रेमी भी थे। दुनिया और परिवार से विद्रोह करके प्रेम की डगर पर बढ़ने वाले प्रेमी, लेकिन शायद खराब पति और दांपत्य की पटरी पर चलते हुए धोखेबाजी करते हुए किसी और के साथ प्यार में फिसल जाने वाले भी। इस सबके साथ ही वे स्नेही पिता भी थे। दरअसल मार्क्स की पर्सनैलिटी में बहुत से आयाम थे जिसमें कुछ पररस्पर विरोधाभासी भी थे।

संजय श्रीवास्तव

कुछ समय पहले मैरी गैब्रिएल की किताब लव एंड कैपिटल : कार्ल एंड जेनी मार्क्स एंड द बर्थ ऑफ ए रिवोल्यूशन काफी चर्चित हुई थी। किताब में कार्ल मार्क्स की जिंदगी और उसके सफर के साथ उनके व्यक्तित्व के कई पहलुओं को बारीकी से देखने की कोशिश की गई है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रायर में हुआ था और मृत्यु 14 मार्च 1883 को लंदन में हुई। उनकी लिखी जीवन की सबसे खास पुस्तक दास कैपिटल है, जिसे साम्यवादी देशों में गीता की तरह समझा जाता है। जब भी कोई साम्यवाद की ओर आकर्षित होता है तो उसे वह किताब जरूर पढ़ने की सलाह दी जाती है। उसे कम्युनिस्ट विचारधारा के घोषणापत्र के तौर पर भी देखा जाता है। उस दौर में मार्क्स और उनके अभिन्न दोस्त फ्रेडरिक एंगेल्स ने मिलकर कई लेख और किताबें लिखीं, जिन्होंने दुनिया को नये तेवर दिये।

कार्ल हेनरिक मार्क्स अपने मन-बाप के नौ बच्चों में सबसे उम्रदराज जीवित लड़के थे। उनके पिता हेनरिक एक सफल वकील और प्रबुद्ध व्यक्ति थे, जो कांट और वोल्टेयर के प्रति समर्पित थे और जिन्होंने प्रशिया में संविधान के लिए आंदोलन में भाग लिया। मां हॉलैंड से थीं। माता-पिता दोनों यहूदी थे। वे रब्बियों की लंबी कतार के वंशज थे। मार्क्स की शिक्षा 1830 से 1835 तक ट्रायर के हाई स्कूल में हुई। यह वह समय था जब पूरे यूरोप में उथल-पुथल चल रही थी। धर्म को चुनौती देने वाले आंदोलन मुखर हो रहे थे तो मिलों और खानों के मजदूरों की खराब स्थितियों और

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

कामकाजी वातावरण के विरोध में माहौल तैयार हो रहा था। मार्क्स जिस स्कूल में पढ़ने गए, उसके बारे में माना जाता था कि वह व्यवस्था विरोधी है। उदार शिक्षकों और विद्यार्थियों को आश्रय देने के संदेह में उनका स्कूल पुलिस की निगरानी में था। अक्टूबर 1835 में वे बॉन विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण की। छात्र जीवन में वह धार्मिक विषयों बहुत चाव से पढ़ते थे, हालांकि जेहन में बहुत से सवाल घूमते रहते थे। उस दौरान नशे और उपद्रव के कारण उन्हें एक दिन जेल में भी बिताना पड़ा था।

बाद के वर्षों में उनका विद्रोही तेवर आकार लेने लगा। उन्होंने टैवर्न क्लब की अध्यक्षता की, जो अधिक कुलीन छात्र संघों के साथ मतभेद रखता था। फिर वे एक कवि क्लब में शामिल हो गए. जिसमें कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल थे। राजनीतिक तौर पर विद्रोही छात्रों की गिरफ्तारियां हो रही थीं, लिहाजा उन्होंने बॉन छोड़ दिया। अक्टूबर 1836 में कानून और दर्शन का अध्ययन करने के लिए उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।

कार्ल मार्क्स जब ट्रायर शहर में रह रहे थे, उस दौरान वेस्टफेलन परिवार में उनका खूब जाना आना था। वह परिवार उनको प्रिय था और वह उस परिवार को। परिवार के मुखिया बैरन लुडविग वॉन वेस्टफेलन उनके शुरुआती मेंटर थे, जिनके साथ कला से लेकर राजनीति तक उनकी हर विषय पर लंबी बातें होती थीं। वेस्टफेलन का बेटा एडगर उनका बचपन का सबसे अच्छा और अकेला दोस्त था। मार्क्स के ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसी परिवार में एक प्रखर और सुंदर सी लड़की भी थी। मार्क्स एक ओर जहां अपने इस गुरु बैरन की बातों और ज्ञान से प्रभावित थे, तो उन्हें गुरु की बेटी को देखना अच्छा लगने लगा था।

गुरु की उस बेटी का नाम जेनी था। जेनी विद्रोही, सुंदर, तार्किक, प्रखर और ऊर्जा से भरी हुई एक लड़की थी। उन दिनों मार्क्स की हालत यह हो गई थी कि वह जेनी को जब देख नहीं पाते तो उदास हो जाते। जेनी को समझते देर नहीं लगी कि वह लड़का उसे पसंद करने लगा है, लेकिन दो बातें थीं, जो आगे जाकर शायद राह में कांटें बिछाने वाली थीं। पहली यह कि जेनी मार्क्स से चार साल बड़ी थी और दूसरी बात यह कि वेस्टफेलन परिवार इस तरह के किसी रिश्ते को पसंद नहीं करने वाला था। उधर, जेनी किशोर मार्क्स को मंत्रमुग्ध करती जा रही थी। दोनों अब रोज मिलते ही मिलते थे। बातें करने के लिए उनके पास पूरी दुनिया का विषय था और नजदीकी को फील करने का एहसास ही अलग था। फिर दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहने वाली स्थिति में पहुंच गए। इसमें कोई शक नहीं कि प्रेम के मामले में मार्क्स आवेगपूर्ण, आतुर और खासे रोमांटिक रहे होंगे। ये बातें बाद के दिनों में उनकी ओर से जेनी को लिखे पत्रों से भी झलकती हैं। उन दिनों वे प्रेम कविताएं लिखने लगे थे, जो जेनी को समर्पित होती थीं। शुरू में जेनी ने उस प्यार से खुद को दूर करने की कोशिश की क्योंकि शायद वह भ्रमित थी कि उसे कार्ल के साथ इस राह पर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। खैर, देर-सबेर ही सही जेनी को भी मार्क्स से प्यार हो गया। मार्क्स ने उसी समय एक प्रेम कविता लिखी, जिसका शीर्षक था,...आने वाली सदियों के लिए/प्यार जेनी है, जेनी प्यार का नाम है...मार्क्स के अनुसार वह ट्रायर शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी।

मार्क्स जब विश्वविद्यालय में पहले वर्ष की पढ़ाई करने गए तो उन्हें शहर छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उन्हें जेनी की बहुत याद आती थी। उसके बगैर रहना बहुत मुश्किल हो रहा और डर था कि कहीं जेनी के घरवाले उसकी शादी कहीं और न कर दें। जेनी 22 साल की तो हो ही चुकी थी, यानी शादी की परफेक्ट उम्र वाली। मार्क्स 18 वर्ष की उम्र होने के बाद अपने शहर ट्रायर लौटे। दोनों ने भरपूर प्यार किया और ये फैसला ले लिया कि दोनों गुपचुप सगाई कर लेते हैं। उसकी पहल भी जेनी की ही ओर से ज्यादा हुई। तब 1836 में दोनों की गुप्त सगाई हो गई। दोनों को ही अंदाज हो चला था कि उनके घर वाले उनकी शादी शायद नहीं होने देंगे। उनको दोनों का रिश्ता पसंद नहीं आएगा क्योंकि न तो मार्क्स के पिता और न ही जेनी के पिता ऐसा चाहते थे। गुप्त सगाई के बाद ऐसा नहीं हुआ कि दोनों के रिश्तों पर आंच नहीं आई। जेनी पर तो लगातार परिवार का दबाव पड़ रहा था कि वह शादी कर ले और वह भी कितना टाल पाती। एक दिन उसने परिवार वालों से साफ बता दिया कि वह मार्क्स के साथ रिश्ते में बंध

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

चुकी है। सगाई कर चुकी है। घर वाले स्तब्ध थे। जबरदस्त विरोध भी हुआ, लेकिन जेनी इतनी दृढ़ इच्छाशक्ति वाली थी कि कोई उसकी मर्जी के खिलाफ उससे कुछ नहीं करा सकता था। यह कहना गलत नहीं होगा कि कार्ल मार्क्स को उनकी जिन कृतियों के कारण दुनिया जानती है, उसकी असली प्रेरणा जेनी ही थीं, जो उनके लिखे हर पन्ने को चेक करतीं, उसमें रद्दोबदल करातीं और जरूरी सुझाव भी देतीं।

इस सबके बीच छह साल बाद जब मार्क्स ने डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की तो दोनों परिवारों का विरोध कुछ हद तक थम चुका था। फिर दोनों ने शादी कर ली। 19 जून 1843 को क्रुज्नाचेर पॉलुस्किर्चे (सेंट पॉल का क्रुज्नाच चर्च) में उनकी शादी हो गई। उस समय दोनों के पास बहुत सीमित या नाममात्र के पैसे थे। घर चलाने की चुनौतियां थीं, जिसमें बड़ी जिम्मेदारी जेनी ने उठाई। दोनों जब हनीमून पर गए तो मार्क्स अपने साथ 40 से अधिक पुस्तकों वाला बस्ता लेकर गए। उन दिनों वे दोनों लेख लिखकर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे। 1843 में शादी के समय कार्ल 25 वर्ष के थे और जेनी 29 वर्ष की थीं।

मैरी गेब्रिएल की किताब लव एंड कैपिटल के मुताबिक जेनी और मार्क्स का दांपत्य जीवन 'कड़वा-मीठा' था। जेनी के एक के बाद एक बच्चे पैदा हुए और वह घर भी संभाल रही थी। कार्ल मार्क्स घरेलू चुनौतियों, प्रबंधन और कामकाज से दूर अपने काम में लगे रहते। बच्चों को पालने के साथ सारी चीजें जेनी संभालतीं। मार्क्स ने सात बच्चे पैदा किए, जिनमें तीन वयस्क होने तक जीवित रहे (सभी लड़कियां थीं)। जेनी अक्सर कुंठित हो जाने वाले और बात-बात पर बिगड़ने वाले मार्क्स को न केवल प्रेरणा देतीं बल्कि उनको मोटिवेट भी करतीं।

माना जाता है कि जेनी ने अगर लिखने का काम गंभीरता से किया होता, तो वह भी अपनी खास जगह बनाने की क्षमता वाली महिला थीं। उनके पास गहरी पत्रकार की नजर थी। उसी वजह से मार्क्स के हर लेख और किताब के पेज को वह रंग देती थीं। बहुमूल्य सुझाव देतीं और जब मार्क्स को रोमांस की चाहत होती तो उन्हें पत्नी से वह भी भरपूर मिलता था। जेनी की पूरी कोशिश होती थी कि वह मार्क्स को खुश रखें। पति को महान लेखन और विचारों की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाती रहतीं। जेनी अपने पति के काम और राजनीति की कट्टर रक्षक थीं, तब भी जब उन्हें अपने विचारों के लिए निर्वासन और कारावास का सामना करना पड़ा। जब फ्रांसीसी अधिकारियों ने मार्क्स को पेरिस से बाहर निकाल दिया तो जेनी ने सारा फ़र्नीचर बेच दिया, लेकिन तब भी कर्ज बकाया ही रहा। वैसे, मार्क्स को संभालना आसान नहीं था। वह क्रोध करने में तेज़ थे। जल्दी कोई बात भूलते

कार्ल मार्क्स ने 21 जून 1865 को का जेनी को एक खत लिखा था। उसे भी उनका एक लव लेटर कह सकते हैं।

मेनचेस्टर, 21 जून, 1865
मेरी दिल अज़ीज़,
देखो, मैं तुम्हें फिर से खत लिख रहा हूं, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे दूर हूं और जब भी मैं तुमसे दूर होता हूं, तुम्हें अपने और भी करीब महसूस करता हूं। तुम हर वक्त मेरे जेहन में होती हो और मैं बिना तुम्हारे किसी भी प्रति उत्तर के तुमसे कुछ न कुछ बातें करता रहता हूं। ये जो क्षणिक दूरियां होती हैं न प्रिय, ये बहुत सुन्दर होती हैं। लगातार साथ रहते-रहते हम एक-दूसरे में, एक-दूसरे की बातों में, आदतों में इस कदर इकसार होने लगते हैं कि उसमें से कुछ भी अलग से देखा जा सकना संभव नहीं रहता। फिर छोटी-छोटी सी बातें, आदतें बड़ा रूप लेने लगती हैं, चिडचिड़ाहट भरने लगती है, लेकिन दूर जाते ही वह सब एक पल में कहीं दूर हो जाता है। किसी करिश्मे की तरह दूरियां प्यार की परवरिश करती हैं ठीक वैसे ही जैसे नन्हे पौधों की सूरज और बारिश करती है। ओ मेरी प्रिय, इन दिनों मेरे साथ प्यार का यही करिश्मा घट रहा है। तुम्हारी परछाइयां मेरे आसपास रहती हैं, मेरे ख्वाब तुम्हारी खुशबू से सजे होते हैं। मैं जानता हूं कि इन दूरियों ने मेरे प्यार को किस तरह संजोया है, संवारा है। जिस पल मैं तुमसे दूर होता हूं मेरी प्रिय, मैं अपने भीतर प्रेम की शिद्दत को फिर से महसूस करता हूं। मुझे महसूस होता है कि मैं कुछ हूं। ये जो पढ़ना-लिखना है, जानना है, आधुनिक होना है ये सब हमारे भीतर के संशयों को उजागर करता है, तार्किक बनाता है लेकिन इन सबका प्यार से कोई लेना-देना नहीं। तुम्हारा प्यार मुझे मेरा होना बताता है, मैं अपना होना महसूस कर पाता हूं तुम्हारे प्यार में। इस दुनिया में बहुत सारी स्त्रियां हैं, बहुत खूबसूरत स्त्रियां हैं लेकिन वह स्त्री सिर्फ तुम ही हो जिसके चेहरे में मैं खुद को देख पाता हूं, जिसकी एक-एक सांस, त्वचा की एक-एक झुर्री तुम्हारे प्यार की तस्दीक करती है, जो मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत याद है। यहां तक कि मेरी तमाम तकलीफों और जीवन में होने वाले तमाम अपूरणीय नुकसान भी उन मीठी यादों के साये में कम लगने लगते हैं।
मैं तुम्हारी उन प्रेमिल अभिव्यक्तियों को याद करता हूं। तुम्हारे चेहरे को चूमते हुए अपने जीवन की तमाम तकलीफों को, दर्द को भूल जाता हूं
विदा, मेरी प्रिय. तुम्हें और बच्चों को बहुत सारा प्यार और चुम्बन

तुम्हारा
मार्क्स

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

नहीं थे और जल्दी माफ नहीं करते थे। बौद्धिक जुनून के साथ आक्रोश भी उनमें भरा हुआ था। वह नशे में बिगड़ैल हो जाते। उनके राजनीतिक और बौद्धिक दुश्मन असंख्य थे, लेकिन कहा जाता है, वह जिन लोगों से वह प्यार करते थे, खासकर अपनी पत्नी, बच्चों और दोस्त फ्रेडरिक एंगेल्स को, उन्हें ही सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचाते थे। किताब लिखती है कि बेशक कार्ल मार्क्स की जिंदगी पूंजीपतियों की घोर आलोचना करते बीती, लेकिन किसी हद तक उन्होंने भी तो यही किया। लोगों का उपयोग किया। उनसे सेवा कराई और अगर किसी ने विरोध किया और अड़ियल साबित हुए तो उन्हें त्याग दिया। उन्होंने अपने आस-पास के लोगों से निरंतर बलिदान की मांग की। हालांकि कई बार वह जेनी के प्रति बहुत स्नेहिल होते थे। उनके दिल में इंसानियत के लिए और हर इंसानी रिश्ते के लिए अथाह प्यार भरा था। जेनी के बगैर वह रह नहीं पाते थे। जब उससे अलग होते थे तो उसे पत्र लिखते थे। 1881 में जेनी का निधन हो गया। उसके दो साल बाद इंग्लैंड में मार्क्स की भी मृत्यु हो गई। जेनी से बेइंतिहा प्यार के चलते उन्होंने अपनी हर लड़की के नाम के साथ जेनी जरूर जोड़ा।

बहुत से पत्र कार्ल मार्क्स ने जेनी को लिखे और जेनी ने मार्क्स को, लेकिन उसके बाद भी मार्क्स उस महिला से प्यार करने लग गए, जो उनकी मां ने जेनी के बच्चा पैदा करने के बाद उसकी केयर के लिए खासतौर पर उनके घर भेजी थी। मार्क्स की ओर से जेनी को मिली वह सबसे बड़ी चोट थी। गेब्रियल की किताब ने उसे 'अंतिम विश्वासघात' के रूप में वर्णित किया है। हेलेन डेमुथ उनके परिवार में हाउसकीपर बनकर आई थी और वह उसके प्यार में पड़ गए। उसके साथ गुपचुप पींगे बढ़ाने लगे। एक ओर जेनी गर्भवती थी तो दूसरी ओर कार्ल नौकरानी डेमुथ के करीब आ चुके थे। दोनों के बीच वह रिश्ते बन चुके थे जिसकी भनक शायद जेनी को नहीं थी या रही भी हो तो उन्होंने यह नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। फिर तो डेमुथ भी गर्भवती हो गई और उसने उनके बच्चे को जन्म दिया।

हालांकि मार्क्स परिवार के किसी भी पत्र में उसका कोई उल्लेख नहीं है, बस उस निराशाजनक समय का संकेत है जब मार्क्स ने शिकायत की थी कि 'घर पर सब कुछ हमेशा तनाव के घेरे में रहता है'। जब पत्नी उनकी इस हरकत पर आंसू बहाती तो वे क्रोधित हो उठते। जेनी के संस्मरण उनके अशांत घरेलू जीवन के बारे में भी उतने ही मौन थे। जेनी ने बस इतना लिखा कि '1851 की गर्मियों की शुरुआत में' एक घटना घटी जिसका मैं यहां विस्तार से वर्णन नहीं करना चाहती, हालांकि उसने हमारी व्यक्तिगत और अन्य दोनों तरह की चिंताओं को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। किताब कहती है, नौकरानी शायद 1850 की गर्मियों में गर्भवती हुई, जब जेनी हॉलैंड में अपने परिवार से वित्तीय सहायता की गुहार लगा रही थी। डेमुथ ने अगले वर्ष गर्मियों की शुरुआत में एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम उसने हेनरी फ्रेडरिक डेमुथ रखा। बाद में कार्ल मार्क्स के दोस्त एंगेल्स ने मार्क्स की प्रतिष्ठा बचाने के लिए बच्चे के पितृत्व पर खुद का दावा किया, जो सही नहीं था। पैदा हुए लड़के को एक पालक परिवार में छोड़ दिया गया। बाद में उसने अपना जीवन यह साबित करने में बिताया कि मार्क्स उसके पिता थे।

हालांकि उस बच्चे के पैदा होने के बाद घर में जितना भी कोहराम मचा हो लेकिन जेनी, कार्ल और डेमुथ में कुछ ऐसा समझौता जरूर हुआ कि तीनों आगे भी साथ रहे। डेमुथ उन दोनों से ज्यादा समय तक जिंदा रही, लेकिन इन तीनों के जीवन पर प्रकाश डालने वाले सबूत नष्ट हो चुके हैं। हालांकि मार्क्स जब मरे तो उनकी जेब में उनकी पत्नी जेनी की तस्वीर थी। बाद के वर्षों में जेनी मार्क्स आंतरिक दर्द से पीड़ित हो गईं, जिसका निदान लिवर कैंसर के रूप में किया गया। फ्रांस की पारिवारिक यात्रा के बाद 2 दिसंबर 1881 को 67 वर्ष की आयु में लंदन में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कार्ल मार्क्स की तरह लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में दफनाया गया था। 1954 में उनके अवशेषों को उनके पति और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक नई कब्र में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके ऊपर एक स्मारक बनाया गया। जेनी अपने पूरे कठिन जीवन में प्रतिकूल हालात के बाद भी सक्रिय रहती थीं। कम्युनिस्ट बैठकें आयोजित करने, शरणार्थियों के लिए आश्रय और राहत प्रदान करने और अपने पति को उनके दार्शनिक और आर्थिक कार्यों के निर्माण में मदद करने में लगी रहती थीं। उनसे परिवार को उम्मीद थी कि वह किसी प्रशिया अधिकारी या उच्च कुल के व्यक्ति से विवाह करेंगी। इसके बजाय जेनी ने फ्रांसीसी समाजवाद और जर्मन रूमानियतवाद में अपनी रुचियों को आगे बढ़ाया। जेनी की पढ़ाई ने उसे अपने लिए आदर्शों को महत्व देना सिखाया। छोटी उम्र से ही उन्होंने महिलाओं की समानता पर शुरुआती नारीवादी विचारों को अपना लिया था। कार्ल मार्क्स की पत्नी जेनी मार्क्स सबसे पहले क्रांतिकारी समाजवाद के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता वाली महिला थीं। वह अपने पति के विचारों का प्रतीक मात्र नहीं थीं, वह वास्तव में पूंजीवाद से मजदूर वर्ग की मुक्ति के संघर्ष में विश्वास करती थीं। वैसे कहा जाता है एक पिता के तौर पर मार्क्स स्नेहिल पिता थे।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

चुनाव : रील लाइफ सितारों का रीयल इम्तिहान

चर्चाएं तो बहुत रहीं कि इस बार अक्षय कुमार, रणदीप हुड्डा और मनोज बाजपेयी जैसे सितारे भी अपनी शोहरत के बूते लोकसभा पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनमें से एक को भी मौजूदा राजनीति अपने अभिनय करियर से बेहतर नहीं लगी। इधर, मेरठ में चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अवतरित हुए 'रामायण' के राम यानी अरुण गोविल का अंदाज-ए-बयां ही कुछ और रहा। लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे फिल्मी सितारों को लेकर एक विश्लेषण वरिष्ठ फिल्म समीक्षक पंकज शुक्ल का।

लोकसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू होते ही इस बार जो सितारा सबसे पहले मैदान में दिखाई दिया, वह रहे साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता कमल हासन। कमल हासन ने इस लोकसभा चुनाव में डीएमके प्रत्याशी डी. रविकुमार का प्रचार किया और अपनी राजनीतिक पार्टी मक्कल नीधि मइयम का चुनाव चिह्न लगी वैन में सवार होकर निकले कमल हासन को देखने भारी संख्या में लोग गलियों में और अपने घरों की छतों पर खड़े दिखाई दिए। उधर, तमिलनाडु के ठीक विपरीत दिशा में हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से जुबां केसरी कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लोकसभा पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। मथुरा से हेमा मालिनी हैं, दिल्ली में मनोज तिवारी, गोरखपुर से रवि किशन, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा और मेरठ लोकसभा सीट से अपने 'रामजी' अरुण गोविल भी भाजपा के टिकट पर ही किस्मत आजमा रहे हैं। तेलगु सिनेमा का बड़ा नाम रहे

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

अभिनेता पवन कल्याण अपनी खुद की बनाई जनसेना पार्टी के टिकट पर भाजपा के सहयोगी प्रत्याशी के रूप में पीतापुरम लोकसभा सीट पर प्रत्याशी हैं तो तमिल सिनेमा के अभिनेता विजय का अभिनय से संन्यास लेकर राजनीति में उतरने की घोषणा करना भी लोकसभा चुनाव से ऐन पहले खूब सुर्खियों में रहा।

वैसे तो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हुए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को भी चुनावी मैदान में उतारा था। फिर उसके बाद भी फिल्मी सितारों का राजनीति में आना-जाना लगा रहा, लेकिन उससे पूर्व सियासी मैदान में दिग्गज सितारों की जैसी मौजूदगी एमजी रामचंद्रन, एम करुणानिधि और जय ललिता ने तमिलनाडु में सजाई, वैसी सिर्फ आंध्र प्रदेश में एन टी रामाराव ही दोहरा सके। फिल्मी सितारों का देश की सियासत में मिला ये सबसे ऊंचा मुकाम है, लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव थोड़ा अलग है। चुनाव की चुनौतियां यह हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्अपनी संख्या लोकसभा में सहयोगी दलों के साथ 400 के पार ले जाना चाहती है और दूसरी तरफ है विपक्षी पार्टियों का जुटान, 'इंडिया' ब्लॉक, जो इस संख्या को कम से कम करने में लगा हुआ है। चुनाव की गर्मी से ज्यादा इस बार मौसम की गर्मी से लोग बेहाल है। मतदाता घरों से वोट डालने पिछले चुनाव के मुकाबले कम निकल रहे हैं। सत्ताधारी पार्टियों के समर्थक अपने में मगन हैं कि उनकी पार्टी तो जीत ही रही है और अगर वे वोट डालने नहीं भी गए तो एक-दो वोट से क्या फर्क पड़ने वाला है, वहीं विपक्षी दलों को अपने समर्थकों को घरों से निकालना भी कम टेढ़ी खीर नहीं है।

इस प्रचंड गर्मी में हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर एक काफिला जब एक विशालकाय छाते के नीचे खड़ी कंगना रनौत के साथ निकलता है तो समझ आता है कि देश में जनता के साथ रहकर, जनता जैसी दिक्कतों का एहसास करने वाले नेताओं के दिन अब नहीं

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

बचे हैं। नेताओं की संपत्तियां करोड़ों में हैं और फिल्मी सितारों के हलफनामों पर गौर करें तो उनकी जायदाद का मुकाबला करना भी बस चंद उन लोगों के बस में ही दिखता है, जिनकी पृष्ठभूमि कारोबार की है। फिल्मी सितारों की यह सियासत उन इलाकों में ही गुल खिलाती है, जहां के वे रहने वाले हैं या फिर जहां पर उनके मूल के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। अपनी कर्मभूमि की गलियों में उतरकर इलाकों के वाशिंदों की फिक्र करने वाले सुनील दत्त जैसे नेता अब नहीं रहे। मुंबई इन दिनों कराह रही है। पूरे शहर में शायद ही ऐसी कोई सड़क बची हो, जिसकी खोदाई न चल रही हो। जनता त्राहिमाम कर रही है और महाराष्ट्र की हर बड़ी पार्टी को दो टुकड़ों में बांट चुकी भाजपा आखिर तक मुंबई की लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के चुनाव को लेकर उलझी रही।

बीच में गोविंदा भी राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उनकी गाड़ी में सफर करते दिखाई दिए लेकिन ये सितारे जमीन पर

उतरकर कितना टिकेंगे, यह देखना दिलचस्प रहेगा।

अब तक जो सितारे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, उनमें से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला रहा भाजपा के टिकट पर मेरठ लोकसभा सीट से चुनाव में उतरे अभिनेता अरुण गोविल का। 1988 में इलाहाबाद लोकसभा सीट के लिए हुए उप चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शास्त्री के प्रचार में पहली बार सियासी माहौल का स्वाद चखने वाले अरुण गोविल को तब कांग्रेस सरकार ने दूरदर्शन पर एक धारावाहिक बनाने का मौका देकर उपकृत किया था। वरिष्ठ फिल्म समीक्षक इंदर मोहन पन्नू बताते हैं, उन दिनों रामायण के सारे कलाकार तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिले थे और राजीव गांधी के कहने पर ही अरुण गोविल ने इलाहाबाद जाकर कांग्रेस का प्रचार किया था। वह भी भगवा धारण करके। अरुण गोविल ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के सहारे भगवा ध्वज थामा है। मतदान के अगले ही दिन मेरठ छोड़ने को लेकर भी वह सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुए और उसे लेकर वह सफाई भी देते रहे लेकिन, सबसे ज्यादा वायरल हुआ उनका वह पोस्ट जिसमें उन्होंने लिखा, जब किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है तो उससे अधिक स्वयं पर क्रोध आता है कि हमने कैसे आंख बंद करके ऐसे आदमी पर भरोसा किया। जय श्री राम। स पोस्ट का सारे राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से मतलब निकाला लेकिन माना यही गया कि अरुण गोविल चुनाव के दौरान खुद को स्थानीय नेताओं का वांछित समर्थन न मिलने से खफा हैं।

उधर, भाजपा के ही एक और उम्मीदवार पवन सिंह ने चुनाव में टिकट मिलने के बावजूद धाकड़ अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के सामने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वह अपने राज्य बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से टिकट चाह रहे थे, लेकिन भाजपा ने उनकी बात और उन्होंने भाजपा की बात नहीं मानी। नतीजा अब पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं और उनके वहां से चुनाव मैदान में उतरने से भाजपा नीत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के समीकरण

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

गड़बड़ा गये हैं। अपने द्विअर्थी गानों के लेकर वह भोजपुरी में अश्लीलता फैलाने के आरोप भी झेल रहे हैं लेकिन बताया जाता है कि काराकाट में अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा की राह मुश्किल हो सकती है। वह पवन सिंह मसले पर बात भी करने से कतराते हैं। कहते हैं, मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं। मुझसे वाणिज्य का सवाल न पूछा जाए। इंडिया ब्लॉक के अन्य घटक दलों की तरफ से वहां राजाराम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं।

मामला कंगना रनौत का भी कम दिलचस्प नहीं है। वे हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति के अनुसार अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग अवतारों में दिखती हैं। उनके निशाने पर कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह हैं जो सूबे के राजसी परिवार से आते हैं। कंगना रनौत विक्रमादित्य को बार-बार 'छोटा पप्पू' कहकर बुलाती रही हैं, लेकिन अगर उस सीट पर 2009 से 2021 तक के चुनावी नतीजों व सियासी समीकरणों पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस का पलड़ा वहां कंगना के मुकाबले कहीं से कमजोर नहीं है। विक्रमादित्य सिंह मौजूदा विधानसभा में शिमला ग्रामीण से विधायक हैं और सरकार में युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं। उनके पिता वीरभद्र सिंह राज्य के छह बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उस सीट पर पिछले चुनाव में उनकी मां प्रतिभा सिंह जीत चुकी हैं। कंगना रनौत का पूरा प्रचार जहां उनकी दिलचस्प बयानबाजी और भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं की मेहनत से रंग ला रहा है, वहीं विक्रमादित्य को कांग्रेस के परंपरागत मतदाताओं का खूब समर्थन मिल रहा है।

भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने साल 2009 में उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़कर अपनी सियासी पारी शुरू की थी। 2014 में वह भाजपा के टिकट से उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आनंद कुमार को हराकर चुनाव जीते और पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भारी मतों से हराया, लेकिन इस बार मनोज तिवारी का सामना जेएनयू के पूर्व छात्रनेता कन्हैया कुमार से है। उस सीट पर युवाओं के बीच कन्हैया कुमार का क्रेज काफी देखा जा रहा है और अब तक टेलीविजन पर हुए आमने-सामने के सारे मुकाबलों में भी कन्हैया कुमार उन पर हावी दिखे हैं। मनोज तिवारी का उस सीट के पूर्वांचल के मतदाताओं पर काफी असर रहा है, लेकिन बिहार के कन्हैया कुमार इस बिंदु पर इस बार उनकी काट लगातार कर रहे हैं। मामला वहां भी दिलचस्प हो चला है।

पेंच आजमगढ़ के भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को लेकर भी फंसा है। हालांकि, वहां मामला त्रिकोणीय हो जाने और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर कांग्रेस की ही पूर्व नेता शबीहा अंसारी के मैदान में उतर जाने से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की राह कुछ मुश्किल हो चली है लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ का चुनाव प्रचार अब तक रंग नहीं ला पाया है। वह तिकोने मुकाबले में फंसे हैं और मुस्लिम मतों का बंटवारा होने की संभावना के चलते धर्मेंद्र यादव से बेहतर स्थिति में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन सूबे में लगातार बढ़ती गर्मी और दिनों दिन कम होते जा रहे मतदान से होश उनके भी उड़े हुए हैं।

ऐसा ही तिकोना मुकाबला होने से मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी भी बेहतर स्थिति में हैं। हेमा मालिनी का यह तीसरा चुनाव है। इस सीट से राजा महेंद्र प्रताप सिंह और साक्षी महाराज जैसे दिग्गज चुनाव जीत चुके हैं। हेमा मालिनी ने अपने चुनाव क्षेत्र में बीते दस साल में काफी काम भी किया है और यही वजह है कि पार्टी ने उन पर भरोसा करते हुए उन्हें लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। कभी साथी कलाकार विनोद खन्ना की चुनावी सभा में पहली बार सियासी माहौल देखने वाली हेमा मालिनी अब सधी हुई राजनेता हैं और बतौर वक्ता भी काफी परिपक्व हो चली हैं।

उधर, पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट भी सियासी पर्यवेक्षकों की रडार पर लगातार बनी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में वहां से जीते गायक बाबुल सुप्रियो अब तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इस सीट के लिए हुए पिछले उपचुनाव में जीतकर शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा पहुंचे थे और इस बार भी वह उसी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। भाजपा की पहली लिस्ट में इस सीट से भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को टिकट मिला था, लेकिन उनके पीछे हट जाने के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेंद्र सिंह सिंह अहलूवालिया उस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हैं। अहलूवालिया बर्दवान-दुर्गापुर निर्वाचन क्षेत्र से पिछला लोकसभा चुनाव जीते थे।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

अभिनेत्री : अदिति राव हैदरी

दम दम दमकतीं अदिति

हैदराबाद के निजामों के यहां शीर्ष पदों पर रहे हैदरी परिवार में जन्मी अदिति ने अपना पूरा नाम मां विद्या राव और पिता एहसान हैदरी के कुलनामों को मिला जुलाकर रखा है। हिंदी फिल्मों में वह लंबे समय से सक्रिय रही हैं और बीते साल रिलीज वेब सीरीज 'जुबली' के बाद से उनके सितारे एकदम से दमक उठे हैं। उनकी नई वेब सीरीज 'हीरामंडी' इन दिनों नेटफ्लिक्स पर धूम मचाए हुए है। दोनों वेब सीरीज की तुलना होने पर अदिति राव हैदरी कहती हैं, दोनों पीरियड फिल्म जैसी कहानियां हैं लेकिन दोनों का कालखंड अलग है और दोनों की कहानियां बिल्कुल अलग हैं। मुझे यह अनुभव बिल्कुल सपनों में घूमने वाले चित्रों जैसा लगा। आप तो जानते ही हैं कि 'जुबली' के निर्देशक विक्रमादित्य मोटवानी ने सिनेमा संजय लीला भंसाली की शागिर्दी में सीखा है। वह संजय सर के सहायक रहे हैं।

अदिति ने 'हीरामंडी' की शूटिंग 'जुबली' का काम पूरा होने के तुरंत बाद शुरू कर दी थी। 'हीरामंडी' के निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ वह इसके पहले फिल्म 'पद्मावत' में मेहरुन्निसा का किरदार निभा चुकी हैं। अब वह 'हीरामंडी' की बिब्बो जान बनी हैं जो इन कोठों पर राज करने वाली मल्लिका जान की बड़ी बेटी है। बचपन से ही शास्त्रीय नृत्य और संगीत का माहौल अपने आसपास देखने वाली अदिति बताती हैं, मेरी मां (विद्या राव) ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा है। वह आज भी ठुमरी, दादरा गाती हैं। नैना देवी की शागिर्द रही हैं। उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन से मिले अनुदान पर तवायफों पर शोध किया है। साथ ही और भी तमाम शास्त्रीय संगीतकारों से मेरा ताल्लुक रहा है। मैंने लीला सैमसन से शास्त्रीय नृत्य सीखा है और 'हीरामंडी' की शूटिंग हमने मेरे मुजरे से ही शुरू की थी। वह शूटिंग का पहला दिन था। ये वाला मुजरा पहले एपिसोड में आता है। संजय सर ने 'हीरामंडी' में तवायफों के किरदार कर रहीं हर अभिनेत्री के लिए चुन-चुन के अलग-अलग गाने तैयार किए हैं। ...तो यह हम सबके लिए एक ऐसा अनुभव रहा है, जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है।

Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

तब्सिरा

विभूति नारायण राय

क्या है इस खामोशी का मतलब!

खामोशी बाज़ वक्त रहस्यमयी होती है और कई बार भयानक भी। अट्ठारहवीं लोकसभा चुनने जा रहे भारतीय मतदाताओं की खामोशी को कैसे पारिभाषित करेंगे? जिस वक्त पाठक इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं, सात चरणों में फैले मतदान के तीन चरण बीत चुके हैं और नतीजों को लेकर एक रहस्यमयी खामोशी चारों तरफ पसरी हुई है। ख़ासतौर से हिंदी पट्टी के उन क्षेत्रों में, जिन्होंने पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी और उनके दल भारतीय जनता पार्टी को तीन सौ से अधिक लोकसभा सदस्य चुनने में मदद की थी, लेकिन इस बार जिस तरह की उदासीनता है, उसने एक ऐसी खामोशी बुनी है जिससे तमाम राजनैतिक पंडितों की अटकलें गड़बड़ा गयी हैं।

लोकसभा 2019 के आम चुनावों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली वे इलाक़े थे जिनमें भाजपा को मोदी के नाम पर लगभग सारी सीटें मिल गयी थीं। इन प्रदेशों में कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों को कुछ सीटें मिलीं, पर वे नगण्य ही थीं। तब इन सब के बल पर भाजपा तीन सौ तीन सीटें जीतने में कामयाब हो गयी थी। इस बार चुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले ही नरेंद्र मोदी ने 'अबकी बार चार सौ पार' का नारा लगा कर एक आक्रामक किस्म की मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने का प्रयास किया और शुरुआती दौर में उन्हें सफलता भी मिलती दिखी। उनके साथ सहानुभूति रखने वाले मीडिया समूहों ने भी उनके स्वर से स्वर मिलाया और इसके चलते वह यक्ष प्रश्न कहीं दब गया जो अब इस खामोशी के चलते उभर कर सामने आ गया है ।

'अबकी बार चार सौ पार' के नारे में यह निष्कर्ष निहित था कि 2024 में वे सभी सीटें तो वापस भाजपा को मिलेंगी ही जो 2019 मे उसकी झोली में आयी थीं, उनके अतिरिक्त उसे सौ से अधिक सीटें दक्षिण और पूर्वोत्तर के उन राज्यों से मिलेंगी जहां बार-बार के प्रयासों के बावजूद उसे उल्लेखनीय सफलता कभी नहीं मिल सकी। उनमें केरल और तामिलनाडु जैसे प्रदेश भी हैं जिनमें पूरी ताकत लगाने के बावजूद भाजपा एक सीट भी नहीं जीत पाती। इस बार अभी तक केवल ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति सुधरती दिख रही है, पर उनके बल पर तीन सौ तीन तक पहुंचना भी मुश्किल ही होगा। राजनैतिक पंडितों के लिए यह रहस्य ही रहेगा कि इस आशावाद के पीछे क्या कारण थे ? क्या सरकार ने मोदी की लोकप्रियता का अनुमान लगाने के लिए व्यापक सर्वेक्षण कराये थे ? यदि हां, तो क्या ये सर्वेक्षण इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) जैसी सरकारी एजेंसी ने किये थे या उनमें कुछ निजी प्रतिष्ठित संस्थान भी सम्मिलित थे? आईबी ने तो आपात काल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी को भी उनकी लोकप्रियता को लेकर जो फीडबैक दिया था, उस पर विश्वास कर उन्होंने आपात काल हटा चुनाव कराये और बुरी तरह से हारी थीं। लगता नहीं है कि मोदी सिर्फ आईबी के आकलन पर विश्वास करेंगे, उनके पास तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसा एक बड़ा और ज़मीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं वाला बड़ा संगठन भी है। सवाल यह कि क्या संघ का फीडबैक चार सौ सीटों वाली वाली गारंटी के पीछे था? कुछ भी विश्वास के साथ कह पाना मुश्किल है। कई बार यह ज़रूर होता है कि सलाहकार भी वही सलाह देते हैं जो राजा को प्रिय लगती है। क्या इस बार भी यही तो नहीं हुआ है ?

दूसरे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद मोदी समर्थकों की जिस तरह की प्रतिक्रियायें आयी हैं उनसे एक बात तो स्पष्ट हो गयी है कि 'अबकी बार चार सौ पार' सिर्फ चुनावी जुमला बन कर रह गया है। देखना यह है कि क्या मोदी 303 सीटों का अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पायेंगे? दो चरणों की खामोशी तो इसमें भी संदेह पैदा कर रही है। भाजपा समर्थक मीडिया और उनपर बहस करते भाजपा प्रवक्ता तर्क दे रहे हैं कि चूंकि मोदी समर्थक उनकी वापसी को लेकर आश्वस्त हैं और इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे चार सौ सीटें लेकर आयें या तीन सौ, इसलिए वे कड़ी धूप में बाहर नहीं आये। यह एक लचर तर्क है और इसे देने वालों के स्वर की हिचकिचाहट ही इसकी कमज़ोरी उजागर कर देती है। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जैसे शहरी निर्वाचन क्षेत्र में कम मतदान और ख़ास तौर से महिला मतदाताओं में जोश का अभाव कुछ ऐसा कहता है जो सत्तारूढ़ प्रवक्ताओं के कानों को संगीत तो नहीं ही लगेगा।

एक और यक्ष प्रश्न है कि यदि मोदी के नेतृत्व में भाजपा साधारण बहुमत से भी पिछड़ी तो क्या मोदी पुनः प्रधानमंत्री बन सकेंगे? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत मोदी का वह व्यवहार बनेगा जो कई बार अहंकार की हदों को छूने लगता है। उन्होंने पिछले विधान सभा चुनावों के बाद तीन बार के विजेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज़ चौहान को हटा दिया और राजस्थान की सबसे ताक़तवर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार कर दिया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी यही सब हुआ। अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं कि तीन सौ पार करने के बाद उत्तर प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। पिछले चुनावों के बाद उन्होंने चुन-चुन कर प्रदेशों के मज़बूत क्षत्रपों को कमज़ोर किया है। यदि इस चुनाव में भाजपा को सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों के समर्थन की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें समर्थन तो मिल ही जायेगा, पर इसकी पूरी संभावना है कि मोदी को पार्टी के अंदर से ही विरोध का सामना करना पड़े। बहुत से क्षत्रप अपने आस्तीनों में ख़ंजर छिपाये मौके की तलाश में हैं और कमज़ोर पड़ते ही सीज़र पर कौन सा ब्रूटस टूट पड़ेगा, कहा नहीं जा सकता।

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

Grand
Group of Companies

GRAND PRINTING PRESS

GRAND INFRAVENTURES PVT. LTD.

GRAND ENTERPRISES

(General Order Supplier, Publicity Products)

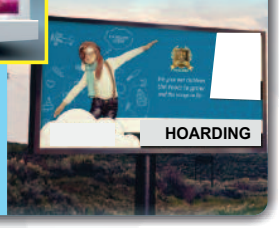

Corporate Off.: R-61, Nehru Enclave, Vishwas Khand, Gomti Nagar, Lucknow-10
Work's : Vijayeepur, Vishes Khand-2, Gomti Nagar, Lucknow-10
grandent.958@gmail.com grandinfraventurepvtltd@gmail.com
Phone No. : 0522- 4109512, 2720029
Mob. : 9415403957, 9889018300 - 500 - 600 - 900

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

All Magazine Hindi English international magazine

Journalism (Indian)
India Today Frontline Open
India Legal Organiser The Caravan
Tehelka Economic and Political Weekly The Caravan

Journalism (International)

Time The Week The New Yorker
The Atlantic Newsweek New York Magazine Foreign Affairs National Review
Money & Business

Forbes Harvard Business Review
Bloomberg Businessweek Business India Entrepreneur inc ET Wealth
Monyweek CEO Magazine
Barron's Fortune International Financing Review Business Today
Outlook Money Shares Value Research Smart Investment
Dalal Street Investment Journal

Science, History & Environment

National Geographic National Geographic Kids New Scientist
Down to Earth Scientific American
Popular Science Astronomy
Smithsonian Net Geo History
Science Philosophy Now BBC Earth
BBC Wildlife BBC Science Focus
BBC History

Literature, Health & General
Interest

The Writer Publishers Weekly TLS
prevention OM Yoga Reader's Digest
The New York Review of Books
NYT Book Review Harper's Magazine The Critic Men's Health
Mens Fitness Women's Health
Womens Fitness Better Photography
Architectural Digest Writing Magazine Pratiyogita Darpan

Sport

Cricket Today The Cricketer
Wisden Cricket Monthly
Sports Illustrated World Soccer Tennis Sportstar FourFourTwo
Auto & Moto

Autocar India UK BBC TopGear
Bike Car

Tech

Wired PC Magazine Maximum PC
PCWorld Techlife News T3 uk India
DataQuest Computeractive
Popular Mechanics PC Gamer
Macworld Linux Format
MIT Technology Review

Fashion & Travel

Elle Vogue Cosmopolitan
Rolling Stone Variety Filmfare
GQ Esquire National Geographic Traveler Condé Nast Traveler
Outlook Traveller Harper's Bazaar
Empire

Comics
Tinkle Indie Comics Image Comics
DC (Assorted) Marvel (Assorted)
Indie Comics Champak

Home & Food

Real Simple Better Homes and Gardens Cosmopolitan Home
Elle Decor Architectural Digest
Vogue Living Good Housekeeping
The Guardian feast The Observer Food Monthly Nat Geographic Traveller Food Food Network

Other Indian Magazines
The Economist
Mutual Fund Insight Wealth insight
Electronics For You Open Source For You Mathematics Today Biology Today Chemistry Today
Physics For You Woman Fitness
Grazia India Filmfare India
Rolling Stone India Outlook
Outlook Money Entertainment Updates Outlook Business
Open Investors India The Week India
Indian Management Fortune India
Scientfic India India Today Brunch
Marwar India Champak Travel + Liesure India Business Traveller
Smart investment Forbes india
ET Wealth Vogue india Yojana
Kurukshetra Evo INDIA New India Samachar Small Enterprise India
Voice & Data

हिन्दी मैगजीन

समय पत्रिका साधनापथगृ हलक्ष्मी उदयइंडिया निरोगधाम मॉडर्न खेतीइंडिया टुडेदेवपुत्र
क्रिकेट टुडेगृ हशोभा अनोखीहिन्दुस्तानमुक्ता सरिता चंपकप्रतियोगिता दर्पण सक्सेस मिरर
सामान्य ज्ञान दर्पण फार्म एवं फूड मनोहर कहानियां सत्यकथा सरस सलिल स्वतंत्र वार्ता लाजवाब आउटलुकसच्ची शिक्षा वनिता
मायापुरी रूपायन उजाला ऋषि प्रसादजोश रोजगार समाचार जोश करेंट अफेयर्स जोश सामान्य ज्ञान जोश बैंकिंग और एसएससी
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्सप्रकृ तमैल
राजस्थान रोजगार संदेश राजस्थान सूजस सखी जागरण अहा! जिंदगी बालभास्कर योजनाकुरूक्षेत्र
More.......

Send me message Telegram

Ya WhatsApp

M......8890050582

Click here magazines Telegram group

https://t.me/Magazines_8890050582

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search • https://t.me/Magazine_8890050582 (@Magazine_8890050582)

👇📚 **ENGLISH MAGAZINE** 📚👇

👉 **GET ALL FAST UPDATE OF ALL HINDI ENGLISH MAGAZINE JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL.**

Frontline,SportStar,Business India,Banking Finance,Cricket Today,Mutual Fund Insight,Wealth insight,Indian Economy & Market,The Insurance Times,Electronics For You,Open Source For You,Mathematics Today,Biology Today,Chemistry Today,Physics For You,Business Today,Woman Fitness India,Grazia India,Filmfare India,Femina India,India Legal,Rolling Stone India,Bombay Filmfame,Outlook,Outlook Money,Careers 360,Outlook Traveller,India Strategic,Entertainment Updates,Outlook Business,Open,Investors India,Law Teller,Global Movie,The Week India,Indian Management,Fortune India,Dalal Street Investmemt Journal,Scientfic India,India Today,HT Brunch,Yoga and Total Health,BW BusinessWorld,Leisure India Today,Down To Earth,Pratiyogita Darpan,Marwar India,Champak,Woman's Era,The Caravan,Travel Liesure India,Business Traveller,Rishi Prasad,Smart investment,Economic and political weekly,Forbes india,Health The Week, Josh Government JOBS,Josh Current Affairs,Josh General Knowledge,Electronic For You Express,Josh Banking And SSC,Highlights Genius,Highlights Champ,Global Spa,Bio Spectrum,Uday India,Spice India Today,India Business Journal,Conde Nast Traveller,AD Architectural Digest,Man's world,Smart Photography India,Banking Frontiers,Hashtag,India Book Of Records,ET Wealth,Vogue india,Yojana,Kurukshetra

👇 **JOIN TELEGRAM CHANNEL** 👇
👉 https://t.me/Magazines_8890050582

👇📚**हिन्दी मैगजीन**📚👇

समय पत्रिका,साधना पथ,गृहलक्ष्मी,उदय इंडिया,निरोगधाम,मॉडर्न खेती ,इंडिया टुडे,देवपुत्र,क्रिकेट टुडे,गृहशोभा,अनोखी हिन्दुस्तान,मुक्ता,सरिता,चंपक,प्रतियोगिता दर्पण,सक्सेस मिरर,सामान्य ज्ञान दर्पण,फार्म एवं फूड,मनोहर कहानियां,सत्यकथा,सरस सलिल,स्वतंत्र वार्ता लाजवाब,आउटलुक,सच्ची शिक्षा,वनिता,मायापुरी,इंडिया हेल्थ,रूपायन उजाला,ऋषि प्रसाद,जोश रोजगार समाचार,जोश करेंट अफेयर्स,जोश सामान्य ज्ञान,जोश बैंकिंग और एसएससी,इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स,राजस्थान रोजगार संदेश,राजस्थान सूजस,सखी जागरण,अहा! जिंदगी,बाल भास्कर,योजना,कुरूक्षेत्र,हिन्दुस्तान जॉब्स

👇 **JOIN TELEGRAM CHANNEL** 👇
👉 https://t.me/English_Newspaper_Banna

Like other groups, this list is not just written, we will make these magazine available to you with 100% guarantee.

JOIN TELEGRAM CHANNEL
👉 https://t.me/Premium_Newspaper

You will get the updates of all these magazinesfirst in the premium group.

👇 **JOIN BACKUP CHANNEL** 👇
👉 https://t.me/Backup_8890050582

SEARCH ON TELEGRAM TO JOIN PREMIUM GROUP
👉 @Lalit712Bot
Contact 👉 8890050582

🙏